

(1100/SK/SM)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमें बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, शून्य काल में बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको शून्य काल में मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 321 और 331 को क्लब किया जाता है।
श्री गणेश सिंह जी।

(प्रश्न 321 और 331)

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय संचार मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को मंजूरी दी गई। ... (व्यवधान) डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन के साथ-साथ कौशल निर्माण के लिए एक मिलियन मानव शक्ति के प्रशिक्षण की कार्य योजना शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय से देश के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वालों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन से बीएसएनएल और एमटीएनएल 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने तथा अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज इलाकों सहित समूचे देश में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा दूर संचार विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 2970 बसावट वाले ऐसे गांव हैं जहां आज तक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के 32 गांव अभी भी अछूते हैं। जनपद पंचायत रामनगर के ग्राम कंदवारी, जनपद पंचायत रामपुर के ग्राम बकिया तिवारियान, जनपद पंचायत नागौद के ग्राम दुरेहा, जनपद पंचायत उचेहरा के ग्राम गुढ़ा और जनपद पंचायत मैहर के ग्राम धनवाही-मझगवां, जनपद मझगवां में खोही, तुरा, वीरपुर, सती अनुसुईया में बीएसएनएल के टावर लगाए जाने हेतु निरंतर मांग हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कई बार टावर लगाये जाने का आग्रह कर चुका हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बसावट वाले 2970 गांवों में कब तक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी? मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के ग्राम कंदवारी, बकिया, तिवारियान, दुरेहा, गुढ़ा, धनवाही, खोही, तुरा, वीरपुर, सती अनुसुईया में बीएसएनएल के टावर कब तक लगा दिए जाएंगे? यह भी बताया जाए कि सतना जिले सहित मध्य प्रदेश में कौन सी मोबाइल कंपनियां बीएसएनएल टावर का लाभ इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग बेसिस पर ले रही हैं?

(1105/YSH/AK)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपका ही क्वेश्चन है, लेकिन आप मंत्री जी की तरह लंबा जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, अगर आप आसन की व्यवस्था को मानना चाहते हैं तो आप सभी ने यह तय किया था कि ऐसा कोई भी विषय, जो ज्वलंत विषय होगा, उसको हम प्रश्न काल के बाद में लेंगे, यह सदन ने तय किया था। मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है, अगर आप आसन से इस व्यवस्था को वापस लेना चाहते हैं, तो आप तय कर लीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मंत्री जी आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए।

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है और उनका जो क्षेत्र है, उसमें 98 प्रतिशत से ज्यादा गांव हैं, उनमें मोबाइल टावर लगे हुए हैं। वहां पर कवरेज मिलता है। वर्ष 2022 तक ऐसा कोई भी गांव नहीं रहेगा, जहां मोबाइल टावर नहीं होगा। अभी जो नई नीति आई है, उसमें टावर लगाना ही नहीं, बल्कि वहां पर 4जी सर्विस भी मिलेगी।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से कुछ स्थानों पर बीएसएनएल के टावर लगाने का प्रश्न किया था। मैं आशा करता हूँ कि वे इसकी स्वीकृति देंगे। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस गति की सर्वव्यापी ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी सहित सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाए जाने की कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के तहत अभी तक सतना जिले के कितने नागरिकों को सर्वव्यापी ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी मिल चुकी है और कवर नहीं किए गए क्षेत्रों की कनेक्टिविटी कब तक सुनिश्चित कर दी जाएगी? सतना जिले को बीएसएनएल के माध्यम से 3जी और 4जी की सुविधा कब तक दी जाएगी?

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि जो डिजिटल नीति है, उसके अनुसार वर्ष 2022 तक हमारे देश के सभी गांव कवर किए जाएंगे। माननीय सदस्य ने अपने जिले के बारे में बताया है तो उसकी जानकारी मैं उन्हें दे दूंगा। मेरे पास अभी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारी नीति यह है कि सभी व्यक्तियों और गांवों तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी की इजाजत हो तो क्वेश्चन नम्बर 321 के साथ 331 को भी हम क्लब कर रहे हैं।

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे प्रश्न काल में बोलने की अनुमति दी। मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदनगर में एमएससीबी ने बीएसएनएल द्वारा निर्धारित बिल का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण दूरभाष केन्द्र और ट्रांस रिसीवर की बिजली कटने की स्थिति आ गई है। महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और अगर वहां पर बिजली काट दी जाती है तो टेलीफोन एवं मोबाइल सेवाएं बाधित होंगी, जिससे जो ग्राहक समय पर अपने बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें असुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार एमएसईडीसीएल से बातचीत करने के बारे में और उनके बिल के भुगतान करने के बारे में कुछ सोच रही है?

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, वह सही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की क्या हालत थी। अभी जो पैकेज आए हैं, उससे काफी व्यवस्था ठीक हो रही है। हम करीब-करीब तीन चार महीनों से वहां की जो एमएसईबी है, उसके साथ बात कर रहे हैं। पहले कई कनेक्शन कटे थे, लेकिन उनको अब फिर से जोड़ा जा रहा है। अब कोई भी कनेक्शन नहीं कटे, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं।

(1110/ASA/SNB)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष, सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए पैकेज की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत वी.आर.एस. का ऑप्शन कर्मचारियों को दिया गया है और करीबन 92,685 कर्मचारियों ने इसमें आवेदन दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों द्वारा खाली किये जाने वाले रेसीडेंशियल

क्वार्टर्स की संख्या क्या है और क्या बीएसएनएल को रेवेन्यू जनरेशन के लिए इन एसैटेस के लैंड मोनेटाइजेशन करने की कोई मंशा है?

श्री संजय धोत्रे : माननीय अध्यक्ष जी, जो रिवाइवल पैकेज है, उसमें लैंड मोनेटाइजेशन या जो हमारी कुछ बिल्डिंग वगैरह हैं, उनको रेंट पर देना है। कई जगह इसका काम भी शुरू हो चुका है।

SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (HATKANANGLE): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to ask the hon. Minister about the closure of BSNL telephone exchange and base trans-receiver system which will affect the services of BSNL in my Parliamentary Constituency Hatkanangle in Kolhapur district. Due to delayed payment of one year, the rent of buildings which function as BSNL telephone exchanges and the base trans-receiver system, the landlords are threatening to seal the premises.

The mobile broadband users along with Government officers and people in the rural areas are dependent on the services of BSNL and when my constituency was devastated by floods, BSNL was the only service provider which was functioning during the time of natural calamity. I would like to know from the Government if this issue would be taken notice of and what steps would the Government take to clear such dues so that the services of BSNL are not affected in my constituency.

श्री संजय धोत्रे : माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे एक्सचेंज रेंट पर लिये हुए हैं, उनका पेमेंट करना और जो पहले सवाल पूछा गया था, बिजली के बिल वगैरह देना, वह हमारी प्रॉयोरिटी है और जो भी एक्सचेंज को डेमैज वगैरह हुआ है, वह काम भी हम प्रॉयोरिटी से कर रहे हैं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी सुना कि वी.आर.एस. दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को अभी भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ खासकर हमारे टॉवर्स की वजह से बीएसएनएल और एमटीएनएल बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बिजली की सेवाएं खंडित हुई हैं। कुछ नए टॉवर्स खड़े किए गए। सिंदुर्व जिले में केवल 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए का बिजली का बिल आया है। वह नहीं भरा क्योंकि बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। उसकी वजह से सारी सेवाएं वहां बंद हुई हैं। दिल्ली में भी आप देखते हैं कि हरेक जगह पर सेवाएं खंडित होती हैं। सरकार को सबसे पहले सर्विस रेस्टोरेशन पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि बिजली का भुगतान होगा तो सर्विस रेस्टोरेशन होगा और अच्छी सेवा मिलेगी और वीआरएस होने की वजह से आपके पास पैसे भी आएंगे। कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर नहीं मिली है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री संजय धोत्रे : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी जवाब में कहा कि बिजली का बिल देना, टॉवर्स एक्सचेंज के रेंट देना जो दूसरे के प्रीमाइजेज में हैं, वह हमारी प्रॉयोरिटी है और आपने जो पार्टिकुलर्स मांगे हैं, वह मैं आपको दे दूंगा।

(ends)

(प्रश्न 322)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अतारांकित प्रश्न सं. 1481 में कहा गया है कि मेरे थाने जिले में तीन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं और थाने जिले में सिर्फ चार ईसीएचएस एम्पैनलड हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन तीनों ही लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी पॉली क्लीनिक नहीं है। इसलिए लोगों को मुम्बई तक पॉलीक्लीनिक जाना पड़ता है। एक्स-सर्विसमैन को इसके कारण बहुत कठिनाई आती है। पॉलीक्लीनिक तो सिर्फ आउटपेशेंट डिपार्टमेंट है। अगर बड़ी बीमारी होती है तो लोगों को एम्पैनलड हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता है जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन जब एक्स-सर्विसमैन एम्पैनलड हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तब लोगों को ट्रीटमेंट कॉस्ट का 50 प्रतिशत बिअर करना पड़ता है और 40 प्रतिशत मेडिसिन्स पर बिअर करना पड़ता है। जो ट्रीटमेंट फ्री होता है, वह सिर्फ आईएनएस आश्विनी या नेवी आर्मी हॉस्पिटल्स में होता है जबकि ईसीएचएस जो स्कीम है, यह सीजीएचएस की धरती पर बनाई गई है, जहां पर ट्रीटमेंट पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। रक्षा संबंधी समिति की 46वीं रिपोर्ट भी यह कहती है कि हर जिले में यह पॉलीक्लीनिक होना चाहिए।

(11115/RAJ/SRG)

आज सिर्फ 427 पॉली क्लिनक्स पूरे भारत में हैं और 365 जिलों में पॉली क्लिनक्स नहीं हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कब तक यह कार्रवाई की जाएगी कि हर जिले में पॉली क्लिनक्स खोले जाएं, जिससे एक्स सर्विसमैन को तकलीफ न हो और मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र, कल्याण में भी पॉली क्लिनिक खोला जाए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी दी है। आप वहां के पॉली क्लिनक्स के बारे में हमें विवरण भेज दीजिए और हम निश्चित तौर से वहां पॉली क्लिनक्स बनाने की कोशिश करेंगे।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं पॉजिटिव अप्रोच के लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक अनस्टार्ड क्वेश्चन-2735 में कहा गया है कि पूरे देश में 26 लाख, 75 हजार, 223 एक्स सर्विसमैन हैं। गर्वनमेंट पॉलिसी के अनुसार इनका रिजर्वेशन सिर्फ कैटेगरी ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप-ए में 0.74 प्रतिशत और ग्रुप-बी में 1.02 प्रतिशत हैं। स्टैंडिंग कमेटी की 45वीं रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया गया है और हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने भी कहा था, जब Directorate of General Resettlement के साथ मीटिंग हुई थी कि implementation of reservation policy for ex-servicemen must be enforced in- house first. Departments and PSUs must set an example for rehabilitation of these ex-servicemen. So, he directed that upto 25 per cent of the vacancies in all categories of employees i.e. Group A, B & C should be filled up by Ex-servicemen. जब एक्स सर्विसमैन बड़ी पोस्ट्स, ब्रिगेडियर या

कर्नल, जैसी पोस्ट्स से रिटायर होते हैं तो वे ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने में हेजिटेट करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब एक्स सर्विसमेन बड़ी पोस्ट्स से रिटायर होंगे, तो क्या उनको ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में भी रिजर्वेशन दी जाएगी, ताकि उनकी शेष आयु अच्छी तरह से कट सके?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पास इसकी डिटेल् नहीं है। आप ने जो शंका प्रकट की है कि बड़े लेवल पर जो ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, उनका इन ग्रुप्स में समावेश नहीं हो सकता है। हम कोशिश करेंगे, जैसा आपने ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के बारे में कहा है, या उनके लिए कोई अन्य नई श्रेणी की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My question relates to the definition and interpretation of 'Ex-servicemen' belonging to Border Security Force, CRPF, CISF and all the forces, especially the BSF, who are the first frontier force to move towards the warfront when the war is declared. But unfortunately, all these forces are being considered as paramilitary forces. They are not coming within the purview of Ex-servicemen and they are being denied most of the welfare activities. Shri Rajnath Singh Ji, the hon. former Home Minister is well aware of the issue. My specific question to the hon. Minister is, whether the benefits which are available to the Ex-servicemen will be extended to all these paramilitary forces, especially BSF, CRPF, CISF etc. I want to know whether it will be considered by the Government.

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, अभी तक आर्म्ड फोर्सज, एयर फोर्सज और नेवल, इन तीनों फोर्सज के रिटायर्ड पर्सनल्स को ही हम एक्स सर्विसमेन के रूप में ट्रीट करते हैं। चूंकि, प्रेमचन्द्रन जी ने जो प्रश्न पूछा है वह गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, एक्स सर्विसमेन अलग-अलग शहरों में रहते हैं। अलग-अलग महानगरपालिका और नगरपालिका के क्षेत्रों में उनको प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्पशन देने का प्रस्ताव होता है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जब एक्स सर्विसमेन की संख्या लगभग 26 लाख है, तो पूरे देश में एक सार्वजनिक पॉलिसी के तहत इनको प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जेम्पशन देने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न टैक्स के विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि अब जिस तरह की टैक्स फैसिलिटीज दी गई हैं और वे कॉमन नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने एग्जेम्पशन के बारे में पूछा है, टैक्स रूल-रेग्युलेशन के मुताबिक होगा। अगर आप उसमें कुछ खास चाहते हैं, तो हम इस पर विचार करेंगे।

(इति)

(1120/VB/SPR)

(प्रश्न 323 और 338)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर दिया गया है, सदन के पटल पर रखा गया है, उसमें मुझे बताया गया है कि इस परियोजना में 50 परसेंट लागत राजस्थान सरकार निःशुल्क देगी और भूमि भी राजस्थान सरकार देगी। लेकिन राजस्थान सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। यह परियोजना अजमेर, नसीराबाद, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, टोंक के लिए है, जो अब आया है। मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2013-14 में पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन 323 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसकी दूरी 59 किलोमीटर है। उसमें सिर्फ सीसीए का अनुमोदन होना बाकी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह अनुमोदन कब तक हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: आपने एक साथ दो प्रश्न पूछ लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे तीन प्रश्न हैं।

माननीय अध्यक्ष: No.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): दो प्रश्न पहले पूछ लेता हूँ और एक बाद में पूछ लूँगा।

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): वर्ष 2013-14 में अजमेर-कोटा-नसीराबाद-केकड़ी-देवली के लिए रेल मार्ग स्वीकृत है। इसमें भी यही स्थिति है, इसमें भी अभी सीसीए का अनुमोदन होना बाकी है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह कब तक हो जाएगा?

श्री सुरेश चन्बासप्पा अंगड़ी: माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में पूछा है। इसके बारे में राज्य सरकार ने लेटर लिखा है। लैंड एक्विजीशन की कॉस्ट के कारण केन्द्र सरकार को ही यह भरना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने इसके बारे में राज्य सरकार को भी लेटर लिखा है। सीसीए के समय राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एग्री हुई थीं। मैं वह लेटर पढ़कर बताता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं, लेटर मत पढ़िए।

श्री सुरेश चन्बासप्पा अंगड़ी: उस समय राजस्थान में और केन्द्र में, दोनों जगहों पर यूपीए सरकार थी। उस समय मेरे मंत्री ने लिखा था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप यहाँ पर पत्र को न पढ़ें, उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेश चन्बासप्पा अंगड़ी: उस समय कैबिनेट में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कॉस्ट शेयरिंग के लिए एग्री हो गई थीं। लैंड कॉस्ट ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से यह उनके पास से नहीं होगा, ऐसा राज्य सरकार बताए। जब तक राज्य सरकार लैंड की इश्यू चेंज नहीं करती है, तब तक रेलवे को किसी लैंड को डेवलप करने का अधिकार नहीं है। यह आपको भी मालूम है। If he wants any specific details on this, we can provide the latest information. If he follows up with the State Government, then the same can be taken up.

माननीय अध्यक्ष: हम प्रश्न संख्या 338 को इसमें क्लब कर रहे हैं।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र अमरेली, गुजरात में, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। भावनगर डिविजन के अंतर्गत विसावदर-जूनागढ़ और वेरावल-तलाला-विसावदर सेक्शन गेज परिवर्तन आरवीएनएल द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रिकल सब-एस्टीमेट से संबंधित डीपीआर पश्चिम रेलवे को 12.04.2019 को भेज दिया गया। लेकिन पश्चिमी रेलवे की तरफ से अभी तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक सारा प्रोसेस लंबित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विसावदर-जूनागढ़ और वेरावल-तलाला-विसावदर सेक्शन गेज परिवर्तन का काम कब तक चालू किया जाएगा और उसकी मंजूरी कब तक दी जाएगी?

(1125/SJN/UB)

SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI: Sir, regarding this project, the viability study and other things are going on. In different stages, the estimates have to be sanctioned by the competent authority. हम माननीय सदस्य को सब कुछ हो जाने के डिटेल दे देंगे।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे क्षेत्र अमरेली में ढसा, खिजड़िया, लुनिधर, जेतलसर लाइन के दोहरीकरण का काम पिछले ढाई सालों से चल रहा है। वह एकदम मंद गति से चल रहा है। अभी जो नवंबर माह पूरा हुआ है, उसमें उसकी समय-सीमा भी खत्म हो गई है। लेकिन अभी तक 30-35 प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं हुआ है। वह काम बहुत ही डिले चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि उस काम को जल्दी से करवाया जाए, ताकि जनता को उसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

श्री सुरेश चन्नाबासप्पा अंगडी : महोदय, आदरणीय मंत्री ने जो सुझाव दिया है, हम उसको एग्जामिन करेंगे, लेकिन उसमें लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए। Where the exact problem lies, मैं उसकी स्टडी करके उनको डिटेल दे दूंगा और हम उसका एक्स्पेंडाइट करने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों और अधिकारियों को बुलाकर समस्या का समाधान कर दीजिएगा।

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हर गुरुवार को वहां शाम को, मैं भी, एमओएस भी और हमारे सभी अधिकारी बैठते हैं। उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को पत्र भी लिखा गया है। हम सेशन के दौरान हर गुरुवार को वहां पर 4 से 6 बजे तक रहते हैं। सभी माननीय सदस्य आते हैं, ताकि हम वहां पर उनको विषय के बारे में जानकारी दे सकें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको व्यवस्था दे दी गई है।

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अररिया में फारबिसगंज से सहरसा में एक छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आठ वर्षों से परिवर्तन होना है। महोदय, आठ साल हो गए हैं, लेकिन आज तक फारबिसगंज से सहरसा में परिवर्तन नहीं हो पाया है। वहां पर बड़ी लाइन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्यों यह काम पिछले आठ सालों से पूरा नहीं हो पा रहा है और कब तक यह काम पूरा हो जाएगा?

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कई वर्षों से वहां पर चर्चा भी चल रही थी और लैंड इक्विजिशन के विषय के ऊपर भी चिंता थी। उस क्षेत्र में पैसा भेजने के बाद भी शुरू में लैंड इक्विजिशन में तकलीफ थी। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वहां के जो मंत्री हैं, वह इसके लिए काफी चिंता कर रहे हैं और काफी इन्वॉल्व हो गए हैं। मुझे लगता है कि उसमें कुछ न कुछ प्रगति होने की संभावना दिखती है। लेकिन जब तक लैंड पर्याप्त मात्रा में हाथ में नहीं आती है, तब तक हम उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, the successive programme of the NDA is the Swachh Bharat Abhiyan, and the hon. Prime Minister has claimed that India would be hundred per cent open defecation free, but the Railway Ministry is acting totally against the hon. Prime Minister and the Swachh Bharat Abhiyan. There are more than 120 suburban stations railway stations in Chennai City. I have written to the hon. Railway Minister that there is not a single toilet facility across those stations. The travel time to Chengalpattu to Chennai is more than two hours and from Tiruvottiyur to Chennai Central is more than one-and-a-half hours. Several pregnant women travel on the train. As you know there are no toilet facilities in the suburban train and these people are made to suffer. You are in power since 2014, you cannot blame the previous Congress Government. The hon. Railway Minister, I would like the hon. Railway Minister to please answer this question.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश चन्बासप्पा अंगडी): Sir, the hon. Member is very senior and is also an ex-Minister. He is speaking very emotionally. महोदय, आपको मालूम है कि आजकल हर बच्चे और हर युवा रेलवे स्टेशन में जाने के बाद प्रधान मंत्री जी का नाम लेकर सेल्फी खींच रहे हैं। If any damage is taking place, especially in Tamil Nadu, whatever the reason may be, the hon. Member should have brought it to our notice. Today, he is bringing it to our notice.

(1130/GG/KMR)

The hon. Member can come to my office and I can show him on the dashboard how the railway stations are maintained. ...*(Interruptions)*

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): There are no toilets.

...*(Interruptions)*

SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI: You please come to my office. I can show you on the dashboard the position of each and every station of the country. Earlier, no station was clean. After our Prime Minister has taken the broom in his hands, today railway stations are clean.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य, आप भी एक मिनट रुकिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज आसन से नई व्यवस्था सुन लें। मैंने आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न दिया। अगर कोई भी सदस्य सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के बाद दो-तीन बार सीट से उठेगा, तो उसको अगली बार सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ज्यादा उत्तेजित थे, इसलिए मुझे भी लगा कि थोड़ा सा जोर देना चाहिए। माननीय सांसद महोदय भली-भांति जानते हैं कि देश भर में हरेक स्टेशन पर बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं सुधारने का काम तेज़ गति से चल रहा है। सफाई का मामला हो, टॉयलेट बनाने का मामला हो, यहां तक कि दिव्यांगों के लिए भी अब कई जगहों पर टॉयलेट्स बनाने का काम शुरू हो गया है। वे शायद एक जानकारी भूल रहे हैं कि जो सब-अर्बन स्टेशंस होते हैं, उन स्टेशंस पर कहीं भी और अधिकांश दुनिया में भी हम देख लें तो सब-अर्बन स्टेशंस पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं की जाती है। चूंकि वे छोटे स्टेशन होते हैं। लोग उसमें ज्यादा होते हैं, जगह उसमें दे नहीं पाते हैं। अगर उनका कोई सब-अर्बन स्टेशन का विषय है, तो सब-अर्बन स्टेशन में All over the world, no toilets are provided at suburban stations. जहां तक स्टेशंस के बाहर की बात है, सक्युलेटिंग एरिया, जिसको कहते हैं स्टेशन के बाहर का एरिया है, उसमें रेलवेज़ नॉर्मल कोर्स में टायलेट प्रोवाइड नहीं करती है। उसके बावजूद हमने अलग-अलग लोगों से, कंपनियों से, पीएसयूज़ से मदद ले कर और कुछ जगह रेलवे ने अपना पैसा डाल कर, दो हजार से अधिक जगह पर, सक्युलेटिंग एरिया में भी टॉयलेट्स प्रोवाइड करने का काम शुरू किया है। ...*(व्यवधान)*

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I have given Rs.20 crore from my MPLAD Fund.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप ऐसा करना कि माननीय सदस्यों के कोष से माननीय सदस्यों से पैसा ले लेना और पैसा ले कर इनके इलाके में बाथरूम बना देना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई दिक्कत है?

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे बीस करोड़ रुपये लगा कर, जितने उनके स्टेशंस की चिंता है, हम उसमें बढ़िया टॉयलेट्स बनाने की व्यवस्था कर देंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, मैं आपको एक बात बता दूँ। डीएमके के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह विषय पहले भी उठाया था। उनसे व्यक्तिगत बात कर के उनके यहां टॉयलेट्स बनाने की व्यवस्था आप जरूर कर लेना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कनिमोज़ी जी भी यही बोलेंगी।

...(व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, this is in continuation to the question the hon. Member asked. Railways is the only Department which still has manual scavenging. When the question is raised, the Railway Department says that cleaning job is given to contractors. But the contractors still use manual scavenging to clean the tracks and the people who do it are not even given protective gear. This is very shameful. I think the Railway Department has to take responsibility for this and not pass on the buck to the contractors.

SHRI PIYUSH GOYAL: I think my sister very well knows that across the country manual scavenging has been got rid of. On the railway tracks, we have ensured that during our tenure we rapidly expand the use of bio-toilets so that the trains do not throw out any muck on the tracks. But, I cannot do anything about the muck we inherited in 2014. That muck has come from over a hundred years and it has accumulated on the railway tracks. What do I do about that? If she has some better idea to remove that muck on the railway tracks, which was accumulated when there were no bio-toilets, then I will be very happy to implement any scheme that Madam Kanimozhi Ji has to suggest. But I think we have been able to convert more than 90 per cent toilets into bio-toilets. The muck of trains is no more thrown on the tracks. Now you will not get that smell which you used to get more than five years before.

(1135/CS/SNT)

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): महोदय, धन्यवाद। मैं केन्द्र सरकार और माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि रेलवे में हिंदुस्तान सबसे आगे निकल रहा है। जितनी भी रेल लाइनें देश के प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने शुरू की हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि जो नई रेल परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, यह उनकी नॉलेज में है, लेकिन जिन परियोजनाओं की घोषणा देश में पहले हुई, जैसे मेरी कांस्टीट्यूएन्सी श्रीगंगानगर में वर्ष 1998 में देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक गजसिंहपुर, पदमपुर, हनुमानगढ़ और पल्लू होते हुए, रावतसर, पल्लू होते हुए सरदारशहर तक एक रेल लाइन की घोषणा की थी। वह रेल लाइन अभी स्वीकृत भी नहीं हुई है। उस रेल लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वह स्वीकृत भी नहीं हुई है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने जिस रेल लाइन की घोषणा की थी, क्या सरकार उसे पूरा करने का विचार रखती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश चन्बासप्पा अंगडी): Sir, the hon. Member has asked a valid question about the details, priorities, and whether the projects have been sanctioned or not which were announced by the former Prime Minister, late Shri Atal Bihar Vajpayee. I will take all the details from the office and provide it to him.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य के सवाल को जरा सही परिप्रेक्ष्य में लेकर उसका उत्तर मिलना चाहिए। माननीय सदस्य प्रदीप जी ने अररिया से फारबिसगंज आमान परिवर्तन का प्रश्न पूछा था, आपने कहा लैंड एक्वीजिशन, आमान परिवर्तन में लैंड एक्वीजिशन कहां इनवाल्ड है? उसमें कोई लैंड एक्वीजिशन इनवाल्ड नहीं है। सारी लैंड्स क्लियर हैं। उनके सवाल का उत्तर हम भी जानना चाहते हैं कि वह योजना कब पूरी होगी? आप इसके बारे में बताइए।

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं स्पेसिफिक डिटेल्स राजीव जी को भेज दूंगा, लेकिन मैं लगातार वहां के पॉवर मिनिस्टर बिजेन्द्र यादव जी के साथ टच में हूँ।
...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): जो आप बोल रहे हैं, वह दूसरी लाइन है।...(व्यवधान)

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): आप सुन लीजिए। मैं उनके साथ टच में हूँ। अररिया के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में, गेज कन्वर्जन की स्पेसिफिक डिटेल्स लेकर आपको भिजवा दूंगा।

(इति)

(Q.324)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Speaker, Sir, we all know the state of affairs of the economy that we are witnessing today where our GDP has gone down. In this background, it is very important that global trade and industrialization need a major boost.

In this regard, what I would like to ask the hon. Minister is that which are the specific industries in trade sector that you are focusing on to increase the global trade. How are you going to strengthen the MSMEs sector so that they also play a major role in boosting up the global trade? And most importantly, how are you going to identify backward regions? What are you going to do to identify those backward regions, say, for instance, regions like Marathwada, where you can identify those regions, strengthen them and support them so that they too can also participate in the global trade?

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker, Sir, since the original question related to the high-level advisory group, I will start with the fact that this was a group which was constituted of high-level experts, like Dr. Surjit Bhalla, who is an eminent economist, our present Foreign Minister, Dr. Jaishankar, several people from the legal field, from industry associations, and small scale and medium scale representatives. They all have come out with a series of suggestions. The important thing to note is that every nation has some competitive and comparative strengths. It is the original Michael Porter theory that you cannot do everything yourself. There are certain areas where you have strength, as a nation you are competitive and you are able to reach out. Gem and Jewellery is one sector – there is another question about it – where India has competitive strength and we have been able to do very well. Footwear is an area where we have been able to do very well. Handicraft is another area, where small and medium enterprises, micro and tiny units have done very well.

So, Government is continuously engaged in assessing. In this report also, several sectors have been specifically identified on which the report has given vertical suggestions, for example, textiles, pharmaceuticals, garments, etc. Electronics is a thrust area which is providing jobs to a lot of people after the hon. Minister of IT has given a thrust to domestic manufacturing of electronic products.

(1140/GM/CP)

Medical devices are going to be an area of the future. Now that more and more people are getting free medical care because of Ayushman Bharat, we are going to make sure that medical devices along with medical electronics come to India. Obviously, every nation determines what its areas of strength are. We are focusing on those areas of strength. The Government is continuously engaging with stakeholders, with domestic industry and understanding what their pain points are. We are ensuring that this nation cleans up all the old issues of bad loans in the banks. When we clear up all the old accumulated problems, we are also preparing the nation to work with regional value chains, global value chains, engage with the world on equal and reciprocal terms. I can assure the Members of the House that the Government is very conscious that India will have to expand its export basket. The HLEG has given very good suggestions for the country as a whole and for specific sectors as to how we can double our exports and the Government is taking action on each one of those suggestions with the case in point being the income tax rates. The Committee had suggested that the income tax rates should be brought down to 18 per cent. I am happy to share with you that the Government has brought down the income tax rate to 15 per cent instead of 18 per cent for new domestic manufacturing unit that is set up. So, the Government is very conscious and continuously working for a better future for our MSME and domestic sectors.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): My question to the hon. Minister is: how is he going to deal with the tough competition that is coming from China? When our reform process started, smaller Far East countries like Thailand, Bangladesh, Vietnam etc. were nowhere in the race. But now, we are facing a tough competition from these countries of the Far East. What is it that the Government is doing? The hon. Minister said he has lowered down the income tax rates. But with the state of economy that we are passing through, is the Government considering to further lower the tax rates? The industry wants to know if he is spending on infrastructure as much as the Government had promised.

SHRI PIYUSH GOYAL: One small point that was left out earlier is about Marathwada. I am happy to share with the Members of the House that this

Government has given particular thrust to Marathwada. When I went to Marathwada during one of my visits, I was amazed to find that in 70 years after Independence, Marathwada had not received a single large Central project in the whole region. I was happy that I could participate with the then hon. Chief Minister Shri Devendra Fadnavis. As the hon. Member may be aware, a large manufacturing unit is being set up by the Railways in Latur in Marathwada region which will help meet the growing needs of Maharashtra's infrastructure, the metro suburban services. Obviously, infrastructure is the backbone of any economy, as one American President had famously said, "Did America make the highways or the highways made America?" The sense of the statement was that on the back of infrastructure, you not only boost the economy, but also give impetus to all other associated and related activities, your logistics costs come down and you become more competitive. The country is working towards making itself more and more competitive in the international region. I am sure Vietnam, Indonesia etc. also do their work and we have to do better than them. We are deeply engaged in studying what other countries are doing. Income tax is one move in that direction. Several other initiatives are being taken by the hon. Finance Minister and all the other colleagues in the Government under the leadership of Prime Minister Shri Modi. I can assure you that India will stand tall when it comes to engaging with the rest of the world and India will stand tall when we have to compete with any region of the world. China is gradually losing its competitive edge. India can gain a lot from the manufacturing sector which moves out of China. We are focused on certain sectors which are looking to move out of China. The hon. Minister Shri Ravi Shankar Prasad himself had met with several companies across the world. They have talked to him about their plans to come to India and set up manufacturing units in India. I am engaged with a number of companies across the world.

(1145/NK/RSG)

The hon. Prime Minister has met representatives of several companies in the United States and other parts of the world where he has visited to encourage investments coming into India, which is why FDI flows have gone up by 50 per cent in the last years over the previous five years. I am confident, in the coming five years, we will see a further boost in domestic manufacturing and inflow of capital for investments.

HON. SPEAKER: Shri Asaduddin Owaisi – not present.

(ends)

(प्रश्न 325)

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार के रक्षा उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने की क्या योजना है, यदि है तो वह क्या प्रमुख सामग्री है, जिसका निर्यात किया जा रहा है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय निर्यात के बारे में बहुत सजग है। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2016-17 में हमारा कुल निर्यात 1521 करोड़ रुपये का था, अब वर्ष 2018-19 में यह लगभग सात गुना बढ़कर 10,745 करोड़ रुपये हो गई है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं रक्षा मंत्रालय ने तय की हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट अटैची हैं, वहां के ऑफिसर डिफेंस के बारे में ही काम कर रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने उनके ऊपर भी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कारण निर्यात के लिए हमने एक्सपोर्ट नीति बनायी है। हमारी सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेस को सुगम और सरल बनाया है, इसके लिए हमने बहुत कुछ काम किया है।

एक ऑनलाइन एक्सपोर्ट पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से एप्रवूल के लिए एक्सपोर्ट अप्लीकेशन कंपनी से ऑनलाइन आती है और इसका निवारण भी ऑनलाइन करते हैं। इसलिए उनकी अप्लीकेशन को जल्दी खारिज किया जाता है। हमने ऐसे उपाय किए हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं उन आइटम्स की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हल्के लांचर्स होते हैं, बहुत सारे एक्वैटिक फेसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वेनुकेलर टारगेट लॉकेटर्स होते हैं, कई प्रकार के कम्पोनेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई रक्षा नीति है, यदि है तो क्या नीति है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): अध्यक्ष महोदय, सरकार नीति से ही चलती है। हमने एक्सपोर्ट वर्ष 2016-17 से शुरू किया था, सरकार की पृथक रक्षा संबंधी नीति नहीं है, नीति है तथापि संस्थागत तंत्र और सैन्य स्टोर निर्यात के लिए एनओसी क्लियरेंस जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाकर निर्यात को बढ़ावा देती है, अभी हमारा नीति बनाने का प्रयास है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी एक पॉलिसी है, पॉलिसी के सैलियंट फीचर्स क्या हैं, वे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा लम्बा है, इसमें समय लगेगा।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, Maharashtra has a lot of companies which would like to export and want to be in the business, including a big project which came to MIHAN where a company called Bharat Forge still seems to be struggling to make in India. The earlier Chief Minister

made a lot of fanfare but it has not created resulted in investments or job creation. I understand this is a very sensitive subject.

(1150/RK/SK)

Please share with us in a limited gambit of whatever you can share. All these companies do want to be into this business, in a competitive manner only on merit, but they are not getting the orders. So, if you could you give some direction in this regard because a lot of these companies are from my State of Maharashtra?

माननीय अध्यक्ष: शशि थरूर जी, आप भी प्रश्न पूछ लीजिए, ताकि माननीय मंत्री जी एक साथ जवाब दें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The interesting thing is that the Defence production of our country seems to have gone up by 12 per cent, from Rs.80,502 crore of 2018-19 to Rs.90,000 crore this year, at least the target of the Ministry. However, there is still a sizeable dependency on foreign original equipment manufacturers for subsystems and components. Until, we curb that dependence down and develop comprehensive capabilities in our country itself, how can we export? Rather, we may be importing more in order to manufacture to meet our export demand. So, the question that comes up to the Minister is, what is the current standing of indigenisation of our sub-systems and equipment and what is the value of exports of arms from this country, last year, this year and what are you projecting for the rest of the fiscal year?

श्री राजनाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले प्रश्न की जानकारी दे दूँ। माननीय सदस्य ने डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में पूछा है। मैंने कहा कि इसके कई सैलियंट फीचर्स हैं, यदि आप कहें तो इसकी डिटेल् दे दूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अगर सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए। रक्षा के विषय में उतना ही बताना चाहिए जितनी आवश्यकता है।

श्री राजनाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष, इसमें कई सैलियंट फीचर्स हैं। पॉलिसी की बात कही गई है, पॉलिसी के कई सैलियंट प्वाइंट्स हैं, तो स्वाभाविक है कि इसे मेशन करने की जरूरत होगी। आपकी इजाजत हो, तब मैं मेशन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आप मेशन कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, फॉरेन पॉलिसी और बहुत से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के कंट्रोल सिस्टम में उपयुक्त एक्सपोर्ट की मार्किट की पहचान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्द्धन एवं सुविधा एक निकाय यानी बॉडी का गठन किया गया है। सैक्रेट्री डिफेंस प्रोडक्शन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया है जो बराबर एक्सपोर्ट से संबंधित इश्यूज की समय-समय पर समीक्षा करती

रहती है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, प्रेजेंट पॉलिसी को कैसे प्रॉपरी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सके, इस संबंध में कमेटी बराबर विचार करती रहती है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट संबंधी स्ट्रेटजी में डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए कभी-कभी सरकारी सहायता भी प्रदान करते हैं या अन्य किसी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान किया जा सकता है, इसे भी प्रोवाइड करते हैं।

माननीय सदस्य सुप्रिया जी ने ऐसी कंपनियों के नाम पूछे हैं।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मेरा प्रश्न है कि 'मेक इन इंडिया' में इनको एनक्रेज करने के लिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र की बहुत सी कंपनियां डिफेंस में कुछ करना चाहती हैं, जैसे भारत फौज है, जितनी इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा थी, नहीं आई है।

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, हम 'मेक इन इंडिया' के तहत बहुत सी कंपनियों को पॉलिसी के तहत जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, कर रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इनडिजेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम अधिक से अधिक वैपन्स, आर्म्स, एम्युनेशनस अपने देश में ही तैयार कर सकें।

महोदय, मैं सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ, पिछले तीन-चार वर्षों से इनडिजेनाइजेशन पर सरकार ने विशेष रूप से बल देना प्रारंभ किया है। ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जिनका हम लोगों ने इनडिजेनाइजेशन किया है। हम अब अपने देश में ही इसे तैयार करने का काम कर रहे हैं।

(इति)

(प्रश्न 326)

श्री भगवंत खुबा (बीदर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार रूप से जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मेरा लोक सभा क्षेत्र चिंचौली तालुका में 50,000 घोर गरीब लोग शाहाबाद में फ्लोरिंग की माइनिंग करते हैं। पिछले चार साल से इको सेंसिटिव जोन के कारण यहां माइनिंग बंद हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति देने के बावजूद कर्नाटक में इनसेंसिटिव सरकार ने अनुमति नहीं दी।

(1155/MK/RC)

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी वहां सेंसिटिव सरकार आ चुकी है तो सरकार वहां पर घोर गरीबों की रोजी-रोटी के लिए इसको अनुमति दे और शाहाबाद फ्लोरिंग माइनिंग को चालू करे। धन्यवाद।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, basically we formulate the policy for mining. जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हम पॉलिसी फार्मुलेट करते हैं। All the related things including allotment, illegal mining, legal mining, etc. are handled by the State Government. I will find out for what reason the permission is not being given. If it is pending for want of environmental or forest clearance, we will try to interact with the concerned Department and try to solve the problem related to his constituency.

श्री भगवंत खुबा (बीदर): अध्यक्ष महोदय, केजीएफ, कर्नाटक देश भर में सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर कई सालों से खनन का कार्य बंद है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप केजीएफ सोने का खनन चालू करेंगे, यदि करेंगे तो कब करेंगे? यह बताने का कष्ट करें।

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, केजीएफ सोने के खनन का कार्य पिछली सरकार के समय में ही बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, उस समय की सरकार ने इसको बंद करने के लिए एक प्रपोजल कैबिनेट में ले गई थी। I am not criticising them. The proposal was to sell it to some cooperative sector entity, if my memory serves me right. This question is not related to the main question. Their total land is around 13,000 acres. In spite of that, the total sale value was kept at just Rs.250 crore. Its land value itself is very high. In spite of that, a Cabinet decision was taken like that. We are entirely reviewing it. We are also concerned about it. We are working out some solution and we will shortly come out with a policy in this regard.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 327।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय अध्यक्ष: रमेश बिधूड़ी जी।

आज तो मैंने आपको इजाजत दे दी है। लेकिन, आगे से जब तक मैं इजाजत न दूं, खड़े मत होना।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, ठीक है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पत्थर की खदानें चलती थीं। उसमें 46 से 47 गांवों के लगभग 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। नार्थ दिल्ली और मध्य दिल्ली के अंदर पत्थर की खदानों से स्ट्रॉंग केशर्स के जो मकान बनते हैं, उसके लिए लिंटर की रोड़ी 500 से 600 किलोमीटर तक आती थी। एनवॉयमेंट के नाम पर वहां पर बिल्डरों ने फ्लैट्स बनाए हैं। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। भ्रष्टाचार और एनवॉयमेंट के नाम पर राज्य सरकारों से मिलकर उस कारखाने को बंद करवा दिया। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एनवॉयमेंट के लिए जितनी गहराई तक खान होनी चाहिए, उतनी उनको खोदने दी जाए। लेकिन, उस कारखाने को बंद कर देने से 46 से 47 गांवों, लक्कारपुर, अनंगपुर, प्रहलादपुर, तुगलकाबाद, आया नगर, नाथूपुर के आस-पास के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान) एक मिनट सर। जो लोग मकान बनाते हैं, उनको बहुत महंगी रोड़ी का उपयोग करना पड़ता है। उनको 400 किलो मीटर से लाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि माइनिंग के विषय राज्य के होते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केंद्र की माइनिंग शेड्यूल अलग है और राज्य की माइनिंग शेड्यूल अलग है।
श्री प्रहलाद जोशी: सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा that we make the policies and the implementation is done by the State Government. As far as the case which he is referring to is concerned, if it is related to environment issue, let him write to me. I will communicate it to the Ministry of Environment. Let him also write directly to the Ministry of Environment. Let us try to understand the problem. I have taken note of his grievances and I will communicate to him directly.

(ends)

(1200/SNB/YSH)

(PP. 21-30)

(Q. 327)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Speaker, Sir, in the reply the hon. Minister has stated that in the last five years 7574 people have been recruited in the Southern Railway and from amongst them 1,433 candidates are from the State of Tamil Nadu. This is the main issue. In the Madurai Division particularly, in case of recruitment for Group D posts, like the trackman, gatekeeper etc. the locals have not been given importance and there has been a discrimination against the local people. That kind of a feeling is there amongst the youngsters.

Sir, this is a Government that has promised 10 crore jobs for the youth of this country. But there is a discrimination in recruitment in the Southern Railway in Tamil Nadu. That is the main issue. Has the hon. Minister received any complaints in this regard? Will the hon. Minister address this issue of discrimination of Tamils in recruitment in the Southern Railway?

SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI: Sir, it is not like that. There are no complaints. The recruitment is not done State-wise. It is done territory-wise. There are two systems of recruitment in the Railways, one is the RRB and the other is the RRC. RRB is responsible for recruitment of Group C and level 1, and RRC is responsible for recruiting Group D people. It is not done zone-wise also. It is done territory-wise. Everything has been computerised in the Railways in 2014. सर, कम्प्यूटराइज्ड में किसी को भी पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रदेश है। यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसके लिए कोई शिकायत भी नहीं आई है। हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो बताएं। We can solve the problem.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक – संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 12) – कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा – खनन गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन तथा कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों, कोयला मंत्रालय में इसके न्यूनीकरण के संबंध में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (c) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (d) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (e) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (f) (i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2019-2020.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (a)
 - (i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (b)
 - (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (c)
 - (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (d)
 - (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019.
 - (ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MEPZ Special Economic Zone, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MEPZ Special Economic Zone, Chennai, for the year 2017-2018.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2018-2019.
- (6)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2018-2019.
- (7)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2018-2019.

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2018-2019.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2018-2019.
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2018-2019.
- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2018-2019.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2018-2019.

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2018-2019.
- (14) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kandla SEZ Authority, Ahmedabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):
Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Lok Sabhas:-

THIRTEENTH LOK SABHA

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Statement No. 36 | Tenth Session, 2002 |
|---------------------|---------------------|

FOURTEENTH LOK SABHA

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 2. Statement No. 34 | Third Session, 2004 |
| 3. Statement No. 32 | Thirteenth Session, |
| 2008 | |

FIFTEENTH LOK SABHA

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 4. Statement No. 36 | Second Session, |
| 2009 | |
| 5. Statement No. 29 | Third Session, 2009 |
| 6. Statement No. 31 | Fourth Session, 2010 |
| 7. Statement No. 31 | Fifth Session, 2010 |
| 8. Statement No. 29 | Sixth Session, 2010 |
| 9. Statement No. 28 | Seventh Session, |
| 2011 | |
| 10. Statement No. 31 | Eighth Session, 2011 |
| 11. Statement No. 28 | Ninth Session, 2011 |
| 12. Statement No. 27 | Tenth Session, 2012 |
| 13. Statement No. 25 | Eleventh Session, |
| 2012 | |
| 14. Statement No. 24 | Twelfth Session, 2012 |

- | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 15. | Statement No.24
2013 | Thirteenth Session, |
| 16. | Statement No. 20
2013-14 | Fifteenth Session, |

SIXTEENTH LOK SABHA

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| 17. | Statement No. 19
2014 | Second Session, |
| 18. | Statement No. 19 | Third Session, 2014 |
| 19. | Statement No. 18 | Fourth Session, 2015 |
| 20. | Statement No. 15 | Sixth Session, 2015 |
| 21. | Statement No. 13
2016 | Seventh Session, |
| 22. | Statement No. 13 | Eighth Session, 2016 |
| 23. | Statement No. 12 | Ninth Session, 2016 |
| 24. | Statement No. 10 | Tenth Session, 2016 |
| 25. | Statement No.10
2017 | Eleventh Session, |
| 26. | Statement No. 8 | Twelfth Session, 2017 |
| 27. | Statement No. 7
2017-18 | Thirteenth Session, |
| 28. | Statement No. 6
2018 | Fourteenth Session, |
| 29. | Statement No. 5 | Fifteenth Session, 2018 |
| 30. | Statement No. 3
2018-19 | Sixteenth Session, |
| 31. | Statement No. 2
2019 | Seventeenth Session, |

SEVENTEENTH LOK SABHA

- | | | |
|-----|-----------------|---------------------|
| 32. | Statement No. 1 | First Session, 2019 |
|-----|-----------------|---------------------|

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table: -

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics, Bengaluru, for the year 2018-2019.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016: -
 1. The Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2019 (1 of 2019) published in Notification No. K-110022/632/2019/Auth-UIDAI (No. 1 of 2019) in Gazette of India dated 7th March, 2019.
 2. The Aadhaar (Enrolment and Update) (Seventh Amendment) Regulations, 2019 (3 of 2019) published in Notification No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13)/Vol.II (No. 3 of 2019) in Gazette of India dated 9th September, 2019.
- (4) A copy of the Notification No. 116-6/2017-NSL-II/(Vol.II) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th November, 2019 making certain amendment in Telecommunications Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018 (09 of 2018) under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.
- (5) A copy of the Indian Post Office Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.856(E) in Gazette of India dated 16th November, 2019 under sub-section (4) of Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 14 of 2019)–Performance Audit on Pradhan Mandtri Ujjwala Yojana, Ministry of Petroleum and Natural Gas under Article 151(1) of the Constitution.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (c) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (d) (i) Review by the Government of the working of the National High-Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

- (ii) Annual Report of the National High-Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (e) (i) Review by the Government of the working of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (f) (i) Review by the Government of the working of the GE Diesel Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the GE Diesel Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (3) A copy of the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.4219(E) in Gazette of India dated 21st November, 2019 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

Sir, I, on behalf of Shri V. Muraleedharan, beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2018-2019.
- (4) A copy of the Patents (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.663(E) in Gazette of India dated 17th September, 2019 under Section 160 of the Patents Act, 1970.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha: -

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at the sitting held on the 9th December, 2019 agreed without any amendment to the Recycling of Ships Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd December, 2019.”

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN**Final Action Taken Statement**

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I and V of the 13th Report of the Committee on Empowerment of Women (2017-18) on action taken by the Government on the recommendations contained in the 10th Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women (2016-17) on the subject `Women in Detention and Access to Justice`.

(1205/RU/RPS)

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
पहला प्रतिवेदन**

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
150th and 151st Reports

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

1. 150th Report on 'Export of Organic Products, Challenges and Opportunities'.
2. 151st Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its 146th Report on 'Impact of Banking Misappropriation on Trade and Industry'.

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
220th to 222nd Reports

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

1. 220th Report on 'Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Fifteenth Report on Working Conditions on Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force and National Security Guard)'.
2. 221st Report on 'Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Fourteenth Report on Working Conditions in Border Guarding Forces (Assam Rifles, Sashastra Seema Bal, Indo-Tibetan Board Police and Border Security Force)'.
3. 222nd Report on 'The Management of Worsening Traffic Situation in Delhi'.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 28, 43rd AND 50th REPORTS OF STANDING
COMMITTEE ON DEFENCE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to make the following statements regarding:-

1. The status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2017-18 on 'General Defence Budget, BRO, ICG, MES, CSD, DGDE, DPSUs, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pensions and ECHS (demand No. 19 & 22)' pertaining to the Ministry of Defence.
2. The status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on 'Ordnance Factories, Defence Research & Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (demand No. 20)' pertaining to the Ministry of Defence.
3. The status of implementation of the recommendations contained in the 50th Report of the Standing Committee on Defence on 'Provision of all weather road connectivity under Border Road Organisation (BRO) and other agencies upto International borders as well as the strategic areas including approach road – An Appraisal' pertaining to the Ministry of Defence.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 60TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
INFORMATION TECHNOLOGY - LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 60th Report of the Standing Committee on Information Technology on 'Setting up of post Bank of India as a Payments Bank –Scope, Objectives and Framework' pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 149TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
COMMERCE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 149th Report of the Standing Committee on Commerce on Action taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in 145th Report of the Committee on 'Impact of Chinese Goods on Indian Industry' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक

1208 बजे

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संस्कृत संवर्धन के सर्व समावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्व समावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

PERSONAL DATA PROTECTION BILL

1209 hours

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move to introduce a Bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data, specify the flow and usage of personal data, create a relationship of trust between persons and entities processing the personal data, protect the rights of individuals whose personal data are processed, to create a framework for organisational and technical measures in processing of data, laying down norms for social media intermediary, cross-border transfer, accountability of entities processing personal data, remedies for unauthorised and harmful processing, and to establish a Data Protection Authority of India for the said purposes and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि व्यष्टियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी ईकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टियों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली ईकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप इसकी प्रस्तावना रखेंगे? आपको कुछ विषय रखना है तो बोलिए।

...(व्यवधान)

(1210/KSP/IND)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Speaker, Sir, under Rule 72, I would like to oppose the introduction of the Bill. The Bill consists of 98 Clauses. It is an omnibus legislation. Already the Ministry of Information Technology has been riddled with various controversies, suspicions, questions etc. Our privacy is already under threat. Snooping industry has been growing under your leadership. When our privacy is under threat and when people are fighting cases in the Supreme Court on the issue of privacy, at this time, I think, this kind of a Bill should be examined thoroughly. You should not bring this Bill in such a supercilious manner. I know you have majority of numbers. But you should not bulldoze this kind of a sensitive Bill in such a supercilious manner. That is why, I propose to the Government that this Bill should be examined thoroughly by a Joint Parliamentary Committee. I request that my proposal should be accepted by the Government.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Speaker, Sir, under Rule 72 (i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Personal Data Protection Bill, 2019. Personal data protection and privacy has become an important point ever since it was revealed that Pegasus Software, a company under Israeli management, was snooping on Google and our privacies have been invaded.

The personal data protection is ensured by the judgement of the Supreme Court in Puttusamy case *vide* WP 494/2012 which has declared that the right to privacy is a fundamental right. So, there is no necessity for this Bill. The problem of privacy can be dealt with under existing laws of the country, taking a cue from the Supreme Court judgement.

The setting up of an authority called the Data Protection Authority will help in appointment of one more bureaucrat. It will further make matters complicated and lead to bureaucratic hassles. Therefore, I wholly oppose the introduction of this Bill, which will not give us the protection from snooping by foreign companies and *desi* companies on our personal data.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Speaker, Sir, I stand to correct myself. This Bill should be referred to the Standing Committee on Information Technology instead of the Joint Parliamentary Committee.

माननीय अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को रखेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है, पहले उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

श्रीमती महुआ मोइत्रा जी।

...(व्यवधान)

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of the Personal Data Protection Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

My primary objection is that Parliament lacks legislative competence on account of this Bill being violative of Article 14 of the Constitution of India which deals with the right to equality, also because of it being completely arbitrary, violative of Article 19 which deals with freedom of speech and expression and most importantly, it fails to provide adequate data protection to our citizens and is violative of the fundamental right to privacy as upheld by the Supreme Court in the Puttusamy case.

I also oppose the Bill in its current form and request that it should be referred to the Standing Committee on Information Technology for a thorough examination.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए। मैंने पूरा नियम पढ़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी पढ़ ली है। आप विराजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, जिन भी माननीय सदस्यों को मैंने बोलने की इजाजत दी है, उनका नोटिस सुबह दस बजे से पहले आने के कारण बोलने की इजाजत दी है।

(1215/SRG/ASA)

जब कभी कोई डिबेट होती है तो मैं आसन की तरफ से आपको बुला सकता हूँ लेकिन कुछ चीजें नियम प्रक्रिया में चलनी चाहिए।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सदन में जो यह बिल रखा है, इस पर जितनी आपत्तियां आई हैं, मैंने उन सबको सुना है। मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा। मैं फिर कहूंगा कि मैं माननीय अधीर बाबू का बहुत सम्मान करता हूँ। But you have not been briefed well today. I say it with greatest respect to you. The same shall be applicable to others.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I need not be briefed by anybody. ...*(Interruptions)*

श्री रवि शंकर प्रसाद: मुझे बोलने दीजिए। अब आगे से मैं फिर आपका नाम नहीं लूंगा, फिर आदर कम हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आगे से आप ऐसा करना कि आप आसन से बात करना। आप इनसे बात ही मत करना।

...*(व्यवधान)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I would like to very respectfully convey to this House that the Members are right that the Supreme Court had held that privacy is a fundamental right. But the Supreme Court has also added that any terrorist and a corrupt person has no right to privacy. The second point, to Saugata Babu with the greatest respect, is that the Supreme Court in the Aadhaar case itself has emphasized that they must come up with the data protection law. Therefore, there is a mandate of Supreme Court also that they must come up with data protection law. ...*(Interruptions)*.

Another thing which is very important to be noted is that we have not come up with this Bill suddenly. We set up a Committee headed by very distinguished retired Supreme Court Judge, Justice Srikrishna. They had the widest consultations in the entire country. 2000 recommendations were made. Thereafter, we discussed and we have come here. What is the essence of this Bill? A lot of things have been said on surveillance. One is a data principal. Who is the data principal? He is the individual whose personal data is under question. Second is data producer and the architecture of the Bill is that without the consent of the individual, if his data is taken, he will suffer penalty. The second is, if one misuses the data beyond the permissible consent, he will face consequences. We have given provision of penalty of crores of rupees on all the persons. Therefore, through this Data Protection Bill, we are safeguarding the rights of Indians. I would like to convey this with greatest of respect.

I do take this point that India's digital economy is rising. We have got 130 crore population and 121 crore mobile phones. We generate a lot of data, but a lot of data is also important for development of economy. We are also making a provision that anonymized data must be available for policy making, for innovation and others. One thing I would like to convey to this hon. House is that we have decided to put data into three categories. One is critical data -- critical is what, the Government will notify it from time to time; the second is sensitive data which relates to income, medical records, sexual preferences and a whole lot of things. Critical data cannot go out of India at all. Sensitive data can go out of India only with the consent of the individual and with the approval of the authority. Now, what about surveillance? What has been said is completely wrong, unsustainable, malicious and misleading... (*Interruptions*). What we are doing is, we are protecting the privacy of Indians, उनकी निजता की रक्षा कर रहे हैं, उनके डेटा की रक्षा कर रहे हैं और उनकी अनुमति और सहमति के बिना कोई भी नहीं ले सकता, वर्ना करोड़ों रु.का फाइन लगेगा। हम चर्चा के बाद इतनी बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, चूंकि यह विषय संवेदनशील है और पूरी दुनिया भी भारत के डेटा प्रोटेक्शन लॉ की प्रतीक्षा कर रही है तो भले ही इसके बनने के समय में बहुत चर्चा हुई है, हम चाहते हैं कि संसद की समितियों में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए।

(1220/KKD/RAJ)

यह हमारी सरकार का मानस है। हम ने एक फैसला किया है, हम कल प्रस्ताव लेकर आएंगे कि दोनों सदनों की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे। हम वह लेकर आएंगे...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The Standing Committee on Information Technology is there ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The Standing Committee has asked ...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You are the Chairman of the Standing Committee on Information Technology. You cannot speak for your cause. ...(*Interruptions*)

Sir, Dr. Shashi Tharoor is the Chairman of the Standing Committee on Information Technology. He should not advocate his own cause ...(*Interruptions*) हमारा कहना है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत महत्वपूर्ण लॉ है और दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, जिसमें सभी सदनों के लोग उपस्थित रहेंगे...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, how can he bypass my Committee? ...(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Then, what is the purpose of the Standing Committee? ...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The Standing Committee is well-known. I do not want to question it. The Standing Committee has to do a lot of work. This Joint Select Committee will be dedicated only and only for the Data Protection Law. ...(*Interruptions*) हम कल इसका प्रस्ताव लेकर आएंगे। हम यह चाहते हैं कि अगले बजट सेशन के पहले यह तैयार हो जाए...(*व्यवधान*) इसके लिए डेडिकेटेड रूप से आपके भी लोग रहेंगे...(*व्यवधान*) दोनों हाउसेज के लोग रहेंगे। हमारा ऐसा मत है, हम ने चर्चा भी की है। हम एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव ले कर आएंगे और इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ का विस्तारित विवेचन हो, यह हमारी आकांक्षा है।...(*व्यवधान*) Let the parliamentary process examine this in the most detailed manner possible. I think, the Joint Select Committee will have good numbers of Members from Opposition of this House and also that House ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि व्यष्टियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी ईकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टियों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली ईकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

...(*व्यवधान*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, we want division ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Yes, we want division ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खाली की जाएं।

(1225-1230/MM/RCP)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपका वाद-विवाद समाप्त हो गया है तो कृपया आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब कुछ नहीं हो सकता है, अब समय निकल चुका है और अब डिजीजन ही होना है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No. अब समय निकल चुका है। आप आपस में बैठकर विवाद को पहले निबटाया करो। अब समय निकल चुका है और अब तो मतदान होगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No. अब केवल मतदान होगा।

महासचिव।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : न इधर की बात रिकॉर्ड में जा रही है, न उधर की बात रिकॉर्ड में जा रही है। महासचिव के अलावा किसी की बात अंकित नहीं होगी।

... (व्यवधान) (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the operation of the Automatic Vote Recording System: - ...(*Interruptions*)

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. ...(*Interruptions*)
2. When the hon. Speaker says "Now Division", I, Secretary-General, will activate the voting button whereupon "RED BULBS" above display boards on both sides of hon. Speaker's Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously. ...(*Interruptions*)
3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously "ONLY" after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG. ...(*Interruptions*)

Red "VOTE" button in front of every hon. Member on the Head phone plate

and

any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat'

Ayes	:	Green Colour
Noes	:	Red Colour
Abstain	:	Yellow Colour ...(<i>Interruptions</i>)

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard and the Red BULBS above plasma display are "OFF". ...(*Interruptions*)
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
 1. If buttons are kept pressed before the first GONG.
 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG. ...(*Interruptions*)
6. Hon. Members can actually "SEE" their vote on display boards installed on either side of hon. Speaker's Chair. ...(*Interruptions*)
7. In case vote is not registered, they may call for voting through slips. Thank you. ...(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in protest, we walk out. ...(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, we are walking out ...(*Interruptions*)

1234 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रिंस राज, माननीय सदस्य, जिनको डिवीज़न नंबर नहीं दिया गया है, वह मतदान के लिए मतदान स्लिप की मांग कर सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि व्यष्टियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी ईकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टियों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली ईकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। ...(*व्यवधान*)

(1235/SJN/SMN)

सामाजिक सुरक्षा संहिता

1235 बजे

माननीय अध्यक्ष : आईटम नंबर 23 - श्री संतोष कुमार गंगवार।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप कोई विषय रखना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, under sub-rule 2 of the Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I would like to oppose the introduction of the Code on Social Security, 2019 on the following grounds. There are three grounds.

The first ground by which I oppose the introduction of the Bill is various provisions of the Bill curtails the existing benefits of workers which is against the mandate of the ILO Convention.

Sir, you may kindly see that the International Labour Organisation Convention mandates that the existing benefits of the labour class can never be curtailed. That is the principle which has been accepted in the International Labour Organisation Convention.

If you examine the code, various provisions of that violate or take away the rights which are being enjoyed by the working force or working class of this country. So, it is against the mandate of ILO Convention. That is my first objection because India is also a party to the ILO Convention.

Number two, it is violating Articles 42 and 43 of the Constitution. Since there is no time, I am not going to read Articles 42 and 43. Articles 42 and 43 are the Directive Principles of State Policy that have to be complied with by the Government because it is a welfare legislation.

Social Security welfare legislation should comply with the principles of Articles 42 and 43.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप प्लीज बैठकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लाबीज़ क्लीयर कर दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, after division, the lobbies have to be cleared.

Sir, Articles 42 and 43 are the Directive Principles of State Policy. The State is bound to comply with the Directive Principles of State Policy.

The Bill is not circulated two days prior to the introduction of the Bill which violates 19B of the Directions by the Speaker, Lok Sabha.

Hon. Speaker, you have reiterated and an assurance is given to the House that every Bill will be circulated two days before its introduction.

Sir, this is a Bill which contains 163 clauses and six schedules. Such a big Bill has come to my office at 0930 hours. How can I read the entire Bill and oppose the introduction of the Bill?

So, kindly give a specific direction once again reiterating that all the Bills should be circulated two days prior to their introduction.

With this, I oppose the introduction of the Bill. It is against the working class of this country. Hence, I do oppose the introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय, अब आपको मौका नहीं मिलेगा, मैंने आपका नाम दो बार पुकार लिया है।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Code on Social Security, 2019. This Bill says that it is a follow up of the Labour Conference held in 2003. It is a sixteen years old Convention which is being

brought here and so many Acts are there like Employees Provident Fund Act, Employees State Insurance Act. They want to put everything in the same Bill. This is what the capitalists, industrialists and Chambers of Commerce of the country want. No central trade union has ever demanded the social security legislation should be brought under one umbrella. This idea of bringing labour code is a punishment to the workers. If you see, they have made it more complicated instead of making it simple.

(1240/GG/MMN)

Separate Acts were there to take recourse when our provident fund dues were not given and when the ESI dues were not deposited by the owners. We should take recourse to the legislation. That is why, now they have linked this to the Insolvency and Bankruptcy Code. Under the Insolvency and Bankruptcy Code, the NCLT is not able to deal with all the problems. Now they are making it further complicated. That is why, I say that I am opposed to the introduction of the Bill. It should be immediately referred to the Standing Committee on Labour headed by Shri Bhartruhari Mahtab.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारा नोटिस है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी थी। अब मौका नहीं मिलेगा।

माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सिर्फ आधा मिनट दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक सैकेंड भी नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि श्रम कानूनों की जटिलता को कम करने के लिए, चार मैबर कोर्ट्स को समाहित करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय ने सन् 2014 से यह कार्यवाही शुरू की है। ...(व्यवधान) मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूँ कि यह चौथा और अंतिम लेबर कोर्ट है। ...(व्यवधान) श्रम कानूनों की जटिलताओं को कम करने के लिए हमने यह कदम उठाया है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम जो भी कानून लाते हैं, उस पर लगातार गंभीर चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) मजदूर संगठनों के साथ उन जटिलताओं को दूर करने के बाद ही लंबे समय के बाद यह बिल यहां पर आया है। ...(व्यवधान) मेरा आग्रह है कि

आपकी जितनी शंकाएं हैं, वे सारी की सारी दूर की जाएंगी। ... (व्यवधान) जब आप सदन में चर्चा करेंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ... (व्यवधान) हम 44 कानूनों को चार कोर्ट्स में बदलने का काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह पुरःस्थापित कर दिया है? ... (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं देख लूंगा, आपके विचार को मैंने सुन लिया है और मैं इस पर विचार करूंगा।
... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): क्या विचार करने से सही होगा? ... (व्यवधान) स्पीकर साहब, हम पूरा भरोसा रखते हैं। ... (व्यवधान) क्योंकि सारी स्टैंडिंग कमेटी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर – 24

श्री थावर चंद गहलोत जी।

... (व्यवधान)

**माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण
और कल्याण (संशोधन) विधेयक**

1242 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री थावर चंद गहलोत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज़ खोल दी जाएं।

...(व्यवधान)

SPECIAL MENTIONS

माननीय अध्यक्ष: अब शून्य काल शुरू होता है।

पहले श्री टी.आर. बालू जी, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। सबको मौका देंगे।

श्री टी.आर. बालू जी बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Government of India is legally mandated to compensate, year-on-year, any State deprived of 14 per cent growth rate. Last month, in November, the Finance Ministers of many States, namely, Delhi, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, West Bengal, Kerala and Puducherry, had met the hon. Union Finance Minister and demanded their rightful share of GST compensation. That compensation has to be distributed every two months to the States. But, of course, the money has not yet been distributed to the States. My State, the State of Tamil Nadu, has not been represented by its Finance Minister or any Minister but at the same time, the Leader of the Opposition in Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin is vociferously appealing to the Government of India to see that the GST compensation is extended forthwith to Tamil Nadu. Tamil Nadu is really at a severe cash crunch. (1245/VR/KN)

Sir, there is a debt trap of Rs.3.9 lakh crore. They do not know what is happening there. At the same time, the State Government has to look to the Government of India for each and everything, to even open their mouth for their own demands.

Sir, the State of Tamil Nadu is reeling under a cash crunch. It is in a debt trap. Through you, I humbly request the Finance Minister to kindly release the due amount to the State of Tamil Nadu without fail. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्रीमती करुणानिधि कनिमोजी और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, आईजीएसटी एक्ट के अनुसार स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिवाॅल्यूशन हुआ, उसकी वजह से कम्पनसेट करना चाहिए। हमारा तेलंगाना नया स्टेट है। तेलंगाना स्टेट के लिए अभी 4,531 करोड़ रुपये आईजीएसटी रिलीज करना है और टैक्स डिवाॅल्यूशन का 224 करोड़ रुपये रिलीज करना है। इसके लिए हम लोगों ने मिनिस्टर को लैटर लिखा है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लैटर लिखा है। हम लोग भी पूरा फॉलो-अप कर रहे हैं। मगर अभी तक यह रिलीज नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ अंडर री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार

हम लोगों को बेकवर्ड डेवलपमेंट के लिए 450 करोड़ रुपये रिलीज करने हैं, वह भी रिलीज नहीं किया है। उसी के अनुसार फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, लोकल रूरल डेवलपमेंट के लिए 312 करोड़ रुपये रिलीज करने हैं, वह भी रिलीज नहीं किया है। एफसी ग्रांट का यूएलबीज के लिए 393 करोड़ रुपये रिलीज करने हैं, वह भी रिलीज नहीं किया है। नीति आयोग ने हमारे मिशन भागीरथ के लिए 19,205 करोड़ रुपये रिकमंड किए हैं, वह भी रिलीज नहीं किया है। नीति आयोग ने मिशन काकतीय के लिए 5,000 करोड़ रुपये रिकमंड किए हैं, वह भी रिलीज नहीं किया है। कुल मिलाकर 29,891 करोड़ रुपये हमारे तेलंगाना राज्य को देने हैं, वह अभी तक नहीं दिए हैं। मैं आपके माध्यम से आईजीएसटी को तुरंत रिलीज करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी हाउस में हर एक मिनिस्टर ने सब स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करने के लिए वायदा किया है, मगर स्टेट गवर्नमेंट को जो न्यायपूर्ण पैसा मिलना चाहिए था, वह पैसा रिलीज नहीं करने की वजह से पूरी स्टेट सफर हो रही है। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल कर डेवलपमेंट करें तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। यह पैसा रिलीज नहीं होने की वजह से स्टेट डेवलप नहीं हो पा रही है।

सर, आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को इधर रिप्लाइ देना चाहिए। यह एक स्टेट का मामला नहीं है। सभी स्टेट्स का जो इश्यू है, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्लाइ देना चाहिए। पूरी कंट्री का डेवलपमेंट ठप हो गया है। इसका वन ऑफ द रीज़न है कि स्टेट के शेयर को रिलीज नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट जमा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, हमारे शेयर को रिलीज नहीं करने की वजह से यह सब प्रॉब्लम हो रही है। हमारे तेलंगाना स्टेट के आईजीएसटी के 4,531 करोड़ रुपये तुरंत रिलीज करें। हमारा नया स्टेट है, 6 साल पुराना स्टेट है। उन लोगों को नए स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, वह सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। टोटल ड्यूज 29,891 करोड़ रुपये को तुरंत रिलीज करने के लिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो एक खत लिखा है, उस खत की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि जीएसटी के माध्यम से जो कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुए थे, उस कमिटमेंट के माध्यम से जीएसटी रेवेन्यू अगर कम होता है तो उसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। आज महाराष्ट्र सरकार को कम से कम 15,558 करोड़ रुपये इस वर्ष का मिलना चाहिए, ताकि जीएसटी का जो एग्रीमेंट है, उस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को न्याय मिलना चाहिए।

(1250/CS/SAN)

दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी के पत्र लिखने के बाद भी महाराष्ट्र की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। वैसे मैं एलीगेशन नहीं लगाऊँगा, लेकिन मैं विनती

करूंगा कि महाराष्ट्र में आज शिव सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलायंस की राज्य सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार का महाराष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य निभाने का काम करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को लगभग 16 हजार करोड़ रुपये यानी 15, 500 करोड़ रुपया एक वर्ष का नहीं मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट के ऊपर बुरा असर हो रहा है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से विनती है...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम आपकी बात का समर्थन करते हैं।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि चाहे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार न हो, लेकिन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ काम कर रही है। इसलिए जो भी न्याय हो, वह न्याय राज्य सरकार को मिलना चाहिए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी, श्री सप्तगिरी उलाका, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल कुछ न्यूजपेपर और टीवी चैनल्स पर US Commission on International Religious Freedom ने अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने की बात की है।...(व्यवधान)

सर, यह देश संविधान से चलता है और जो अधिकार और कर्तव्य है, उसमें संविधान का जो 51(A) है, वह यह कहता है कि कोई भी नागरिक ;

“(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon

to do so;”

इस देश के गृह मंत्री ने इस देश की सुरक्षा, रक्षा, यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए, लोगों को नागरिक बनाने के लिए जो काम किया और जो हमारी पार्लियामेंट का अधिकार है, जो हमारी संप्रभुता पर उस यूएस के कमीशन ने अटैक किया है।...(व्यवधान) यह केवल पार्टीजन एंगल का सवाल नहीं है।...(व्यवधान) आज हम सरकार में हैं, कल आप सरकार में होंगे।...(व्यवधान) कल आप कोई कानून बनाएंगे और इस तरह से कोई दूसरा देश यदि आपके व्यक्ति को, आपके गृह मंत्री को, आपके प्रधान मंत्री को इस तरह की बातें कहेगा, तो यह हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है।...(व्यवधान) इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि यह देश के लिए शर्मनाक बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यह रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और यूएस को एक कड़ा मैसेज देना चाहिए कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करिए।...(व्यवधान) हमने जो काम किया है, वह अपने देश के लिए किया है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री विनोद कुमार सोनकर, डॉ. संजय जायसवाल, श्री एस.सी. उदासि और श्री तेजस्वी सूर्या को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I support the GST issue. Today I want to draw your attention to a very serious issue. The Commissions for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been set up in 12 States of the country. These States are Rajasthan, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Karnataka, Chhattisgarh, Bihar, Maharashtra and Goa. But when the West Bengal Government is trying to set up such type of a commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, it is the most unfortunate thing that the Assembly could not function in its Winter Session and had to be adjourned *sine die*. What is the reason? The ... (*Not recorded*) is not sending the Bill to the Assembly for which the Government is not being able to implement the Act and the law.

Sir, we strongly protest this heinous attitude of the present... (*Not recorded*) We will request the hon. Home Minister to intervene and see that the... (*Not recorded*) should not disturb the functioning of a State Government. It is an elected State Government. The policy of federal structure is going to be challenged. The Assembly had to close down yesterday only after four days it was in Session. So, it is becoming very serious and very unconstitutional. So, I hope that the Government of India should intervene and see that this Bill is send back. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी, श्री सप्तगिरी उलाका और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुदीप बन्दोपाध्याय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, इस विषय को उठा नहीं सकते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राज्यपाल की चर्चा नहीं कर सकते हैं। आपने किताब में लिखा है। आपने कानून बनाया है।

...(व्यवधान)

(1255/RV/RBN)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, मेरा असम, महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव, अजान पीर का असम है। मेरा असम, लासित बोड़फुकन, हजारिका का असम है। मेरा उत्तर पूर्व शांतिप्रिय छोटा प्रदेश है, जहां पर लोगों को रोजगार चाहिए, वहां निवेश चाहिए। जी.एस.टी. रिटर्न्स हमारे यहां भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन, पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे उत्तर पूर्व में विरोध हुए हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा विरोध पिछले बीस-पच्चीस सालों में नहीं देखा है।

माननीय अध्यक्ष: यह तो पास हो चुका है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, आज असम में लोग हाथों में तलवार लेकर, शंख लेकर विरोध कर रहे हैं। त्रिपुरा में दो दिनों से एस.एम.एस. और इंटरनेट बंद हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में लोग बोल रहे हैं कि आई.एल.पी. और सिक्स्थ शिड्यूल में होने के बावजूद भी आज उनकी भाषा और संस्कृति खतरे में है।

सर, पूरे देश को यह संदेश जाता है कि हमारा नॉर्थ-ईस्ट वन-नॉर्थ-ईस्ट है। हमें आई.एल.पी. में बांटने की कोशिश करने के बाद भी अपनी भाषा और संस्कृति में we are one North-East and we are one India. Therefore, I appeal to this Government to withdraw the Citizenship (Amendment) Bill. It is anti-India, anti-Constitution and anti-North-East.

माननीय अध्यक्ष: अब तो लोक सभा में यह बहुमत से पास हो गया न!

श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री सप्तगिरी उलाका को श्री गौरव गोगोई के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Hon. Speaker, Sir, I stand here to raise a matter of crucial importance to the war veterans of our country. After the 1962 war with China, a need was felt to increase the strength of the Indian Army. At that time, several thousand emergency and Short Service Commissioned officers were commissioned in the Army. These brave soldiers of our country led India to victory in two memorable wars, that of 1965 and 1971. However, about 2,000 of these soldiers were not absorbed in the Indian Army, many of whom are constituents of my constituency, Chandigarh.

Now, when the Narendra Modi-led NDA Government launched the One Rank One Pension scheme in 2016 for the war veterans of India, the scheme excluded these war veterans, who are retired senior citizens now. The veterans have held several meetings with General Bipin Rawat ji, with the then hon. Defence Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, and with our current Defence

Minister, Shri Rajnath Singh ji. However, the issue is still pending with the Ministry of Defence and the veterans are still waiting for it to be resolved.

It is my humble request to the hon. Defence Minister that a grant of *pro-rata* pension of Rs. 30,000 be provided to emergency and short service commissioned officers who put their lives on the line to protect our country, who fought the wars of 1965 and 1971 and who led India to the two of her greatest victories.

Vijay Diwas is commemorated on 16th December every year to celebrate India's 1971 victory. If this pension could be started, it will be an expression of our nation's gratitude to them. My gratitude to you for allowing me to speak. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को श्रीमती किरण खेर के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, India has more than 15,000 km. of land area, and more than 7,000 km. of coastal line. From Kashmir Valley to Rajasthan desert, from insurgent-infested North-Eastern region to naxal-infested areas, everywhere para-military forces are visible. But now-a-days the ex-para-military personnel are suffering from a sense of deprivation as they are not getting their legitimate due.

Their demand is very simple. According to the Central Civil Service Rules, the working hours is defined as eight hours. But the personnel of the para-military forces are working for more than 16 to 20 hours. However, they are being treated as officials under Civil Service Rules. They are demanding now that some sort of rule should be framed, like the para-military service rules instead of administering them under Central Civil Service Rules, at least with regard to their retirement age. Now, they are demanding that, like the defence personnel they should also be given the benefit of One Rank One Pension scheme.

(1300/SM/MY)

Old Pension System instead of New Pension Scheme should be given to those ex-paramilitary forces because they are also sacrificing their lives for the sake of our country, for the welfare of our country in order to make our country secured. So, they should not be deprived of having their legitimate dues. Sir,

they are demanding for implementation of ex-serviceman status to paramilitary CAPF *vide* MHA(R&W) Dte UO No. 27011/100/2012-R&W.

Sir, in the year 2016, the Central Government was reported to have assured the ex-paramilitary forces that the facilities and amenities that are given to the defence personnel will be provided to them. So, they were under the impression that the Central Government will do something for those people in order to face the severe financial stress and strain in the retirement age.

So, those ex-paramilitary forces should be conferred martyr status along with Rs.1 crore ex-gratia grant, employment and rehabilitation to martyred family. These are the issues for which I would like to draw the attention of this Government. 50 per cent GST rebate on Central Police canteen should be provided to them.

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, शेष शून्य काल भोजन अवकाश के पश्चात लिया जाएगा।
सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1302 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/CP/AK)

1403 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1403 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा और शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Need to undertake demarcation of submergence area in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 वर्षों से लम्बित अनधिकृत कालोनियों को पास करने की समस्या का इस सदन में विधेयक लाकर स्थायी समाधान किया गया है। लम्बे समय के पश्चात आज यह कालोनियाँ पास हो गई हैं, इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले बदरपुर क्षेत्र में स्थित कालोनियाँ पास हो गई हैं, इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले बदरपुर क्षेत्र में स्थित कॉलोनियाँ भी पास हो गई हैं, परंतु वहाँ एक और समस्या से लोग परेशान हैं जिसके बारे में, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत दिल्ली में जो भूमि को अलग-अलग जोन में बांटा गया है, उनमें से 1 जोन 0 जोन कहलाता है। यह जोन यमुना के फ्लड-प्लेन एरिया जिसे डूब क्षेत्र कहते हैं के विषय में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूब क्षेत्र की बाउंड्री की निशानदेही या डिमार्केशन आज तक नहीं की गई है, यह कार्य राजस्व विभाग या सिंचाई विभाग जो दोनों दिल्ली सरकार के अधीन का है। इन दोनों विभागों की यह जिम्मेदारी है कि यह गत कुछ निर्धारित वर्षों में हुई वर्षा के आधार पर डूब क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करें, क्योंकि आज तक यह दोनों विभागों की डूब क्षेत्र की सीमाएं अंकित नहीं की गई हैं इसलिए उसके आस-पास स्थित कालोनियाँ जैसे मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर इत्यादि के निवासियों को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वह भूमि पहले कृषि भूमि थी जिसे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किसानों ने विक्रय कर दी थी और उन पर आज कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिसमें लाखों लोग निवास करते हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र की निशानदेही या डिमार्केशन आज तक दिल्ली सरकार एवं उनके अधीन विभागों द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए वहाँ रह रहे निवासी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी निर्देशित किया है कि डूब क्षेत्र का डिमार्केशन किया जाए, उपरोक्त कालोनिया डूब क्षेत्र के बाहर हैं। राजस्व विभाग के एस0डी0एम0 इसके नोडल अधिकारी होते हैं। बच्चों के वयस्क होने पर या पुत्र के विवाह पश्चात यहाँ रह रहे निवासी कुछ अतिरिक्त कमरे बनाते हैं या फिर चाहे वह घर को रेनोवेट करते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है तो इसलिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात कर दिल्ली सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह जल्दी से जल्द दिल्ली विकास प्राधिकरण के समन्वय से डूब क्षेत्र का डिमार्केशन का कार्य पूर्ण करें।

(इति)

Re: Regarding setting up of a steel factory in Dhaurahra parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं सदन में विषय रखना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा धौरहरा की विधानसभा कस्ता के ब्लॉक बेहजम, जनपद लखीमपुर में इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के संबंध में लगभग 11 वर्षों पूर्व सैकड़ों एकड़ किसानों ने अपनी भूमि क्षेत्र के विकास के लिए नये उद्योगों की स्थापना के लिए क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए इस्पात मंत्रालय को दी थी। परंतु इस्पात मंत्रालय द्वारा कहीं न कहीं किसानों की अनदेखी की गयी है तथा भूमि अधिकरण के 11 वर्षों बाद भी इस्पात फैक्ट्री की स्थापना करने हेतु किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को ! बेरोजगारी की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

ब्लाक बेहजम जनपद लखीमपुर खीरी में 11 वर्षों पूर्व इस्पात फैक्ट्री स्थापित करने के लिए की गयी भूमि अधिग्रहण पर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा क्या कार्ययोजना बनायी गयी है, यदि कोई कार्ययोजना बनायी गयी है तो कितने समय में अधिग्रहित भूमि पर इस्पात फैक्ट्री कार्य शुरू होगा ?

(इति)

Re: Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Karauli-Dholpur parliamentary constituency, Rajasthan

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली- धौलपुर के हिण्डौन सिटी उपखण्ड मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध कराना चाहता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के करौली जिले में हिण्डौन सिटी सबसे बड़ा कस्बा तथा रेलवे स्टेशन है। यहां स्कूल शिक्षा के उचित साधन उपलब्ध न होने से स्थानीय विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यहां पर पर्याप्त संख्या में रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मी तथा अन्य केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते हैं तथा इसके साथ राज्य सरकार के कार्मिक भी काफी संख्या में निवास करते हैं। यह करौली जिले का औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण कस्बा है परन्तु हिण्डौन सिटी उपखण्ड मुख्यालय पर स्कूल शिक्षा के उचित साधन उपलब्ध न होने से यहां के बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के करौली जिला के हिण्डौन सिटी उपखण्ड मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के आदेश प्राप्त करने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

(इति)

Re: Need to set up a bench of Jabalpur High Court in Bhopal

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): मेरा संसदीय क्षेत्र भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है जो मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों से सीधे सम्पर्क में है तथा आवागमन की सुविधा से भी यहां पर प्रत्येक शहर, तहसील व ग्राम से आना-जाना अत्यंत सुविधाजनक रहता है, किन्तु भोपाल और आस-पास के जिलों में निवास करने वाले व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय जाना पड़ता है जिससे न्याय प्राप्त करने में अधिक समय व धन का अपव्यय होता है तथा पीड़ित पक्ष को भी लगातार परेशानी होती है।

भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ की अत्यंत आवश्यकता है। यह मांग निरंतर लम्बे समय से अधिवक्ताओं एवं आमजन द्वारा की जा रही है।

मैं सदन के माध्यम से मेरे क्षेत्र भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना यथाशीघ्र किये जाने का अनुरोध कर रही हूँ ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to provide fertilizer to farmers in Madhya Pradesh

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश में गरीब किसान परेशान व बेहाल है। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद (यूरिया खाद) का संकट का सामना करना पड़ रहा है जिससे किसान अपने खेत में समय पर खाद व बीज नहीं डाल पा रहे हैं जिससे किसानों में आक्रोश है।

महोदय, किसानों को खाद प्रदान करें। यही मेरा निवेदन है।

(इति)

Re: Need to include persons suffering from colour blindness under PH category

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मेरे संसदीय क्षेत्र में एक युवक की तकलीफों को मैं आवाज देने की कोशिश कर रही हूँ। निरव मकवाणा उनका नाम है। मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाला बच्चा 10वीं कक्षा में 83.38 प्रतिशत लाता है और 12वीं कक्षा में 83.83 प्रतिशत लाता है। श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पास करता है। और जब वो इंजीनियर हो के सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करता है तब उसे पता चलता है कि वो कलर ब्लाइन्डनेस नामक बीमारी से ग्रसित है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के 25 साल श्रेष्ठ परिणाम देते हुए पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी की आवश्यकता होती है तो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। न वो नोर्मल युवक में शामिल है और न ही दिव्यांग युवक में गिना जाता है। उसके लिए भविष्य अंधकारमय बन जाता है और सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब वो सरकार में पत्र लिखता है उसका जवाब मिलता है कि पीडब्ल्यू एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 के अन्तर्गत उसे दिव्यांग की श्रेणी में नहीं गिना जाता। यह एक किस्सा है लेकिन पूरे देश भर में ऐसे हजारों आशावान युवक युवतियां होंगी जिनको जीवन के युवावस्था में ही अपना पूर्ण भविष्य अंधकारमय दिखता है। महोदय यह दिक्कत इस लिए आती है कि आंखों में कुछ पिगमेन्ट बचपन से कार्यरत न होने की वजह से कुछ कलर्स आंखे पहचान नहीं पाती या देख नहीं पाती। जब कि कम दिखना दिव्यांगता का भाग है। इस प्रकार के बच्चों में यह बीमारी उसी प्रकार विकसित होती है। पिगमेन्ट काम न कर रहे हो एवं ऐसे पिगमेन्टों की संख्या बढ़ने से अंधत्व आता है और वह दिव्यांगता की श्रेणी में आता है तो इन केसों में भी हमें इस प्रकार की तकलीफ को दिव्यांगता की परिभाषा में गिनना चाहिए ताकि इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित बच्चों के परिवार को बचाया जा सके।

मेरी मांग है कि पूरे देश में इस प्रकार से ग्रसित युवक युवतियों की पहचान करते हुए उनके लिए जीवनयापन की व्यवस्था करते हुए कानून में संशोधन करके उन्हें नेचुरल जस्टिस दिलाया जाए।

(इति

Re: Need to set up a medical college in Tikamgarh parliamentary constituency, Madhya Pradesh

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ बुंदेलखंड का अभिन्न अंग है जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर व सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। बुंदेलखण्ड वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत अभाव है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जनता को अन्य स्थान जैसे भोपाल, इंदौर, दिल्ली में अपना इलाज कराने जाना पड़ता है। जिससे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को और अधिक भार उठाना पड़ता है। यदि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला जाता है तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा व आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त सेवाएँ भी प्राप्त हो सकेगी और यहाँ के युवाओं में शिक्षा को लेकर और अधिक उत्साह बढ़ेगा।

(इति)

Re: Upper Pravara (Nilwande-II) project of Maharashtra

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): The Upper Pravara (Nilwande-II) Project of Maharashtra with an estimated cost of Rs.2232.62 crore will irrigate an area of 2,12,758 acres and provide drinking water to the tune of 13.15 MCM. It was approved by the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in June 2018. This project will benefit six talukas in Ahmednagar district and one taluka in Nashik district. In order to expedite the completion of this project, there is a need to increase the funds allocated to it by including it in a Central Government Scheme. I request the government to include the Upper Pravara Project under any Central Government's Financial Assistance Scheme like Pradhan Mantri Kishu Sinchayee Yojana or Baliraja Jal Sanjivani Yojana so that project can be completed at the earliest which will be helpful in resolving irrigation and drinking water problem in my constituency of Ahmednagar.

(ends)

Re: Water from Western Gandak Canal to Bihar

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): The Western Gandak Canal was built after the agreement on water sharing of the Gandaki river with Government of Nepal. This canal is known in Bihar as the Saran Canal. It is drawn from a barrage built on the river at Valmiki Nagar under the Gandak Project and is the prime irrigation source for the region covering districts of Saran, Gopalganj, Siwan and West Champaran along with parts of east UP. The canal has 15,800 cusecs of water, out of which 7300 cusecs goes to Uttar Pradesh and 8,500 cusecs is proposed for Bihar.

For the agricultural and other economic activities in my district, there is a shortfall of 517/44 MCM of water. I have recently been informed that only 2500-3000 cusecs of the water of the Western Gandak Canal comes to Bihar and the rest is taken up by UP. We are facing a water crisis and it is imperative that measures need to be taken in this regard.

(ends)

Re: Need to allocate 5% seats in trains for general public under HO/EQ on the recommendation of Members of Parliament

श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, वर्तमान में रेलवे में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, सर्वोच्च और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों और अन्य वी.आई.पी. लोगों के लिए अति आवश्यक रेल यात्रा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जो सीट आवंटित करने की व्यवस्था है उसमें आम जनता के हित में सुधार करने की आवश्यकता है। अभी उक्त लोगों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे में कुल सीटों के लगभग पाँच प्रतिशत सीट इन लोगों के लिए निर्धारित है ताकि ये लोग अपने-अपने विभाग/क्षेत्र से संबंधित अनिवार्य कार्यों/बैठकों के लिए आपातकाल में अति आवश्यक रेल यात्रा कर सकें। यह जरूरी और आवश्यक है। लेकिन लोकतंत्र में आम जनता संप्रभु है। उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की व्यवस्था और शासन का संचालन किया जाता है।

इसलिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय से मेरी यह मांग है कि देश के वर्तमान यातायात की परिस्थिति के मद्देनजर रेलवे में आम जनता के लिए भी अनिवार्य रूप से एच.ओ./ई.क्यू. कोटा के तहत अलग से अखिल भारतीय स्तर पर पाँच प्रतिशत कोटा का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह कोटा देश के प्रत्येक माननीय सांसदों के अनुरोध पर उनके संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों/जंक्शनों से होकर गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेन में होनी चाहिए। इससे उनके क्षेत्र की आम जनता को अपने अनिवार्य अति आवश्यक यात्रा (जैसे बीमारियों का इलाज कराने के लिए, घर, परिवार, रिश्तेदार या अन्य लोगों के वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, श्राद्ध कार्यक्रमों तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों जिसमें व्यक्ति को शामिल होना अनिवार्य है, उसमें जाने के लिए, विभिन्न ऑफिसियल कार्यों एवं परीक्षा, संवीक्षा, अंतर्वीक्षा, साक्षात्कार आदि में शामिल होने के लिए जाना जरूरी होता है) करने में सुविधा मिलेगी।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार के रेल मंत्रालय से आग्रह है कि देश के वैसे आम जनता जो रेलवे के प्रतीक्षारत यात्री हैं उनके लिए भी माननीय सांसदों के अनुरोध पर रेलवे में एच.ओ./ई. क्यू. कोटा के तहत अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे के कुल सीटों/बर्थों में से पाँच प्रतिशत का सीटों/बर्थों का आवंटन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करवाने के लिए व्यवस्था किया जाये।

(इति)

**Re: Regarding mode of payment of wages to tea garden workers
in West Bengal**

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): महोदय मैं आपके माध्यम से सदन एवं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की 267 चाय बागानों के लगभग 12 लाख आदिवासी, एसटी, एससी एवं ओबीसी गरीब चाय मजदूरों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वर्ष 2019 और 2020 में चाय बागान मालिक द्वारा करोड़ों से अधिक नकद राशि बैंक से निकालने पर 2% दर के रूप में टीडीएस के रूप में काटा जा रहा है. इसलिये चाय मालिक चाय श्रमिकों को मजदूरी बैंक के माध्यम से देना चाहता है. यदि ऐसा हुआ तो चाय श्रमिकों को काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

चाय बागानों से बैंक की दूरी काफी है. खासकर मेरे लोकसभा क्षेत्र के चाय बागान से बैंक पोस्ट ऑफिस एक या दो चाय बागानों को छोड़कर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है. वहां बैंक के कामकाज करने के लिए दिन भर का समय चाय श्रमिकों को निकालना पड़ता है जबकि चाय श्रमिक यदि चाय बागान में काम नहीं करते तो उनकी मजदूरी काट दी जाती है . अभी भी वहां के श्रमिक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वह बैंक में जाकर बैंक का काम काज खुद कर सकें. इससे श्रमिकों को काफी समस्या हो रही है. ऑनलाइन वेजेस पेमेंट को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे चाय श्रमिक चाय बागानों में कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं चाय श्रमिकों को उनकी मजदूरी अभी तक नगद में दी जा रही है . अब चाय मालिक श्रमिकों को उनकी मजदूरी बैंक के माध्यम से देना चाहते हैं. यह चाय मालिकों का 2% टीडीएस बचाने का एक प्रयास है. वर्तमान दुआर्स में रेडबैंक , धनीपुर, मधु, डेकलापाडा जैसे अन्य कई चाय बागान बंद पड़ी हुई हैं. यदि यह नियम चाय बागानों में लागू करना है तो पहले चाय श्रमिकों को बैंक के कामकाज के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाए. जब तक चाय श्रमिकों को डिजिटल शिक्षा नहीं दी जाती तब तक चाय बागानों को इससे छूट दी जाए. मुझे डर है 2% टीडीएस बचाने के प्रयास से चाय बागान में काफी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं. जिससे चाय बागान बंद होने की भी काफी संभावनाएं हैं. जिस से चाय बागान में अस्थिरता पैदा हो सकती है यदि ऐसा होता है तो गरीब चाय श्रमिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

(इति)

Re: Need to reduce the rate of GST on marble and granite

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मान्यवर, हमारे देश में राजस्थान प्रदेश, मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद का सबसे बड़ा केन्द्र होने के साथ-साथ प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय भी है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में से 23 जिलों में मार्बल एवं ग्रेनाइट का खनन एवं उत्पादन का कार्य हो रहा है, जिसमें लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अशिक्षित एवं अकुशल श्रेणी से हैं तो दूसरी ओर अधिकांश मार्बल एवं ग्रेनाइट की खानें जनजातीय एवं आदिवासी जिलों में अवस्थित होने से स्थानीय जनजातीय लोगों को जीविकोपार्जन हेतु सहज रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जिससे ये लोग रोजगार में व्यस्त रहने के कारण अन्य असामाजिक कृत्यों से विमुख रहते हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाइट की लगभग 3000 गैंगसा इकाइयाँ संचालित हैं। ये सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की परिभाषा में आती हैं, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन वर्तमान में उक्त दोनों उत्पादों पर दिनांक 10.11.2017 से जीएसटी की दर 18 प्रतिशत चली आ रही है, जो कि जीएसटी की दरें तय करते समय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भारी उपेक्षा एवं अनदेखी का परिणाम है। जबकि पूर्व में सेल्स टैक्स के समय इन उत्पादों की दर मात्र 5 प्रतिशत ही थी। उक्त दर के चलते गत 1.5 वर्षों में इन दोनों उत्पादों के खनन एवं प्रसंस्करण में लगभग 10 करोड़ का संभावित नया निवेश थम सा गया है, वहीं दूसरी ओर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत ही रहने पर आने वाले समय में भी 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते वर्तमान में कार्यरत हजारों इकाइयों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा तथा मार्बल एवं ग्रेनाइट का विशाल व्यापार भी चौपट हो जायेगा। यदि दोनों उत्पादों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से कम हो जाती है तो प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गरीबों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि वर्तमान में जन आवास योजना में मार्बल एवं ग्रेनाइट का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने से निर्मित मकानों की लागत अधिक आ रही है जिससे उक्त महत्वाकांक्षी योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन से भी कृत्रिम मार्बल भारी मात्रा में आयातित होने से भारतीय मार्बल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। हालांकि गत 20 सितम्बर, 2019 को जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में उक्त दोनों उत्पादों की दरों को कम करने का अनुरोध रखा गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अतः महोदय, आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि आगामी जीएसटी अनुसूची में परिवर्तन के समय राजस्थान प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद की वर्तमान जीएसटी दर 18 प्रतिशत से कम करवाने की महती कृपा करावें।

(इति)

Re: Need to set up CGHS dispensaries in Rohtak and Jhajjar districts, Haryana

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिले रोहतक एवं झज्जर में एक भी सीजीएचएस डिस्पेन्सरी नहीं है। दोनों ही जिलों में Postal Dept., Forest Dept., CGST, Income Tax, Railways, BSNL, EPFO, FCI, AIIMS और IIM जैसे केन्द्र सरकार के 16 से अधिक कार्यालय एवं संस्थान कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही जिलों के दिल्ली-एनसीआर में अवस्थित होने के कारण यहाँ केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं जो कार्यरत तो हैं और देश के अन्य स्थानों पर हैं परंतु उनके आश्रित परिवारजन जो सीजीएचएस लाभार्थी हैं वो यहीं रह रहे हैं और डिस्पेन्सरी नहीं होने के कारण वे सभी सीजीएचएस लाभों के लिए दिल्ली पर निर्भर हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सीजीएचएस लाभों से वंचित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला झज्जर और रोहतक में एक-एक सीजीएचएस डिस्पेन्सरी शीघ्रतिशीघ्र खोलने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to construct approach road on both sides of Yamuna river bridge in Kairana parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, कैराना लोक सभा की विधान सभा गंगोह में दौलतपुर – लाखनोती यमुना नदी के पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। यह पुल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है। पुल के दोनों तरफ से जोड़ने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है जिससे प्रतिदिन आने- जाने वाले यात्रियों को यातायात की समस्या से जूझना पड़ता है। दोनों राज्यों की यह एक मुख्य मांग है कि पुल के दोनों तरफ की सड़कों का निर्माण हो जिससे यातायात सुलभ और सरल हो सके।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त दोनों राज्य के यात्रियों की सुविधा हेतु यमुना नदी के पुल के दोनों तरफ जाने वाली सड़कों का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाये।

(इति)

Re: Need to ensure toilet facilities and their regular cleanliness at petrol pumps across the country

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित पेट्रोल पम्प भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहर/गांव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पेट्रोल पम्पों के माध्यम से पेट्रोल-डीजल वितरित किया जाता है। पेट्रोल पम्पों पर शौचालय आवश्यक हैं। हालांकि कुछ पेट्रोल पम्प मालिकों ने शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया है और जिन लोगों ने शौचालयों का निर्माण करवाया है, वे उनका रखरखाव नहीं कर रहे हैं। सेनेटरी इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें समय-समय पर सरकार को निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नियमन होना चाहिए। यदि पहले से ही नियम बनाए गए हैं, तो उन पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और पेट्रोल पम्प के मालिक को दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया उसका असर भी देखा गया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश के सभी पेट्रोल पम्पों के शौचालयों की साफ सफाई के निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(इति)

**Re: Need to start construction of sanctioned flyover in Jabalpur,
Madhya Pradesh**

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में मेरी मांग पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर की सौगात दी गई थी। उक्त फ्लाई ओवर दमोहनाका से मदन महल तक प्रस्तावित था जिस पर लगभग 978 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय भी स्वीकृत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी, 2019 को केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उक्त सड़क का विविधवत भूमि पूजन के उपरांत भी प्रदेश सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त मार्ग जबलपुर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है। यातायात के भारी दबाव के कारण आमजनों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह है कि उक्त सड़क की निर्माण प्रक्रिया को प्रारंभ किये जाने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(इति)

**Re: Need to extend Rewari-Sikar train no. 59728/29 upto Jaipur
and also run train no. 12955/56 through Reengas, Sikar,
Jhunjhunu , Surajgarh and Loharu**

श्री नरेन्द्र कुमार (झुंझुनू): राजस्थान राज्य का शेखावटी क्षेत्र में जिला झुंझुनू आता है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ शिक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जिला है। साथ ही व्यापारी एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। अतः मेरे जिले में रेलों का सम्पर्क बहुत ही कम है। जिले में रेवाड़ी से सीकर पैसेंजर गाड़ी संख्या 59728/59729 चलती है। अतः उक्त ट्रेन को जयपुर तक रवाने का श्रम करावें। साथ ही गाड़ी संख्या 12955/12956 एस एफ एक्सप्रेस मुम्बई से जयपुर तक चलती है, उक्त ट्रेन को रीगस, सीकर, झुंझुनू, सूरजगढ़, लुहारू तक संचालन करवाने का श्रम करावें।

(इति)

Re: Issues pertaining to farmers of Chandrapur district of Maharashtra

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): The farmers of Chandrapur district did not celebrate Diwali this year as their crops were destroyed due to heavy post monsoon showers. It has been reported that crops in 13 lakh hectares of farmland have been hit due to unseasonal rainfall. The farmers are committing suicide in Vidarbha region following massive crop destruction due to unseasonal rains. In Rajura, Korpana Ballarpur, Waroa, Wani tehsils have suffered maximum losses. As per primary estimates, cotton crop in more than 8,153 hectares, soyabean in more than 1,332 hectares, have been damaged. It is my humble request to Hon'ble Minister to pay Rs.20,000/- per hectare for soybean and paddy crops and Rs.30,000/- for cotton. Further, a suitable help for orange growers may be provided and loans should also be waived.

(ends)

Re: Problems being faced by fishing community

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): India has 7500 Km long coastline and 14 million people depend on fishing for their livelihood. Fisheries sector is heavily contributing to the food security and GDP of our country. Fishing community is in deep crisis today due to the adverse impact of climate change. They are always exposed to rough seas and cyclones occur frequently. They are facing employment loss throughout the year and have no opportunity of alternative jobs for their livelihood. It has been reported that Union Government is planning for an investment of Rs. 25000 crore in fisheries sector in the next five years. I request the Government to conduct a nationwide study on the employment loss among fishermen and consider implementing a national employment guarantee scheme for fishermen. Fishing community is much concerned about the provisions in the proposed Marine Fisheries (Regulation and Management) Bill, 2019. I request the Government to consider their concerns in this legislation.

(ends)

Re: Need to extend the benefit of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to forest dwellers and Adivasi people of Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासी एवं आदिवासी समुदाय के जीवन-यापन हेतु परंपरागत अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से जमीनों का पट्टा इनके नाम किया है। इससे लाखों वनवासियों में एक नई आशा एवं ऊर्जा का संचार हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार इन वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु अपने विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत इन्हें लाभांवित कर रही है।

पर इस वर्ष के लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 'वन अधिकार अधिनियम 2006' के तहत छत्तीसगढ़ के जमीन पट्टाधारक, वनवासी एवं आदिवासी समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। जिससे उन्हें योजना के तहत 6 हजार रूपए का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत वनवासी एवं आदिवासी समुदाय के नाम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी जमीन पट्टाधारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे।

(इति)

Re: Proper implementation of E-waste law

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): The Global E-Waste Monitor report published in 2017 says that India generates about 2 million tonnes of E-Wastes per year. We have a separate law and rules for safe disposal of E-Wastes. But the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards which are mandated to monitor its implementation has miserably failed in their duty. They do not conduct random checks. No manufacturer is collecting the E-wastes mandated by the law. About 95% of the E-Waste is recycled in the informal sector only. Other than this E-wastes are imported illegally into India. Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary) Rules ,2016 bans the import of E-Wastes. But the shortage of manpower in the Board of Excise and Customs leads to failure in distinguishing between a second hand product and E-Waste. The government should take urgent steps to properly implement the E-Wastes Law.

(ends)

Re: Need to remove the condition of number of habitations for construction of roads under PMGSY in Araku parliamentary constituency, Andhra Pradesh

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): I would like to raise the issue of urgent need for development of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in my Parliamentary constituency of Araku.

Sir, as we all know the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is a one-time special intervention of the Union Government to provide rural connectivity, by way of single all-weather road to the eligible unconnected habitations in the core network. PMGSY is executed through State Governments. The primary objective of the PMGSY is to provide connectivity, by way of an all-weather road to the eligible unconnected Habitations in the rural areas with a population of 500 persons and above in Plain areas and in respect of the Hill States (North-East, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand), the Desert Areas (as identified in the Desert Development Programme), the Tribal (Schedule V) areas and Selected Tribal and Backward Districts, the objective would be to connect eligible unconnected Habitations with a population of 250 persons and above. The Government of India has taken a decision to accelerate execution of all-weather road connectivity to eligible habitations as per the Core Network of PMGSY by March, 2019.

However, in spite of this Sir, there is an urgent need for even removing the limit of 250 persons for the Tribal (Schedule V) areas and Selected Tribal districts as due to this specific factor the most isolated areas are not able to be connected. Sir, especially in the case of my constituency Araku, the terrain is densely forested and hilly. More often than not precious lives are lost due to inability to reach the hospital or the nearest health centre.

Sir, I would like to draw the attention of the Hon'ble Environment Minister also because sometimes there is a huge delay in getting approval for forest clearance for projects especially road and other developmental projects.

So through you, Speaker Sir, I would like to request the Hon'ble Minister to take steps to remove the habitation number guidelines for PMGSY. This will go a long way in helping improving the connectivity, saving precious lives and ultimately help in spurring the rural economy in the State. (ends)

Re: Sea erosion along coastline of Andhra Pradesh

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Groynes are Hydraulic Structures which are built along the coastline to interrupt water flows from the ocean or sea and limit the movement of sediments: A Groynes length and elevation and the spacing between successive Groynes is determined according to local wave energy and beach slope. Andhra Pradesh with a coastline of around 974 km has frequently been affected by cyclones and inundated by storm surges. Of this, between 1990 and 2012, 275 km was under erosion, 417 km showed accretion -- the process of coastal sediment returning to the visible portion of a beach or foreshore following a submersion event and 153 km coastline was found to be stable, as per remote sensing and GIS analysis published in 2015.

Due to the high amount of sea erosion, the construction of Groynes has become necessary as the erosion and reduced fish catch have impacted the livelihood of people living in the coastal region especially in my parliamentary constituency of Amalapuram.

In this regard, I would like to request the Hon'ble Minister for Environment Forest and Climate Change to sanction necessary funds to help the State of Andhra Pradesh and my constituency of Amalapuram to combat the menace of climate change which is eating up our coastlines in the form of Sea Erosion.

(ends)

**Re: Need to request Government of Bangladesh to start dredging in
Icchamati river, flowing from Bangladesh into India**

SMT. NUSRAT JAHAN RUHI (BASIRHAT): I would like to draw the attention of the Government towards the plight of 20 lakhs people who have been badly affected by the dying river Icchamati. The river is flowing from Bangladesh to India and for rejuvenation of the river which is silted at off take point at Pabakhali to Fatehpur, a length of 19.5 Km and Fatehpur to Duttapulia via village Mobarakpur-Halder Srinathpur, P.S.-Mahespur, District Jhinaidah in Bangladesh covering stretch of 36.5 Km requires dredging urgently and protection from dangerous problem created by effluents flowing from sugar mills in Bangladesh in RV Mathabhanga near Kustia District, Bangladesh.

I would request the Government to kindly take up the matter with Bangladesh Government and urge its counterpart to start dredging immediately in 36.5 KM area which comes under their territory.

(ends)

Re: Need to protect Sundarbans in West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): The Sundarban eco-region is home to the largest contiguous mangrove forest in the world. Parts of the forest are designated as World Heritage Sites due to their rich biodiversity. The natural areas of the Sundarban are influenced by human use and in recent years by climate change. The natural area was at least twice as large in the 1830s when Dampier and Hodges surveyed the extent of standing forest. This indicates that we are losing parts of our rich nature to climate change. With rising sea levels, islands are disappearing and the increasing salinity in the water and soil has severely threatened the health of mangrove forests and the quality of soil and crops. With every high tide, part of land is consumed and the rest is left even more saline. The area is suffering from numerous problems like coastal flooding, erosion, loss of land to mention a few. Cyclones are the most severe and most frequent in the Sundarban region. Out of 14 global tropical cyclones associated with the highest fatalities in recorded history, nine have occurred in the Bay of Bengal and Sunderbans has protected us all. Now it's our turn to protect Sunderbans, I request the government to take even more serious steps because the present efforts are not yielding desired results.

(ends)

**Re: Need to provide specialist doctors and dialysis centre
in Buldhana parliamentary constituency, Maharashtra and also
provide safe drinking water in the constituency**

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरे बुलढाणा संसदीय क्षेत्र के शेगांव, जलगांव, जामोद, संग्रामपुर, खानगांव, नांदुरा, मलकापुर इत्यादि स्थलों में जल में अत्यधिक क्षार की मात्रा से लोगों में किडनी जैसे गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं तथा इन बीमारियों के उपचार हेतु क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सक और अत्याधुनिक डायलेसिस सेन्टर्स का अभाव है जिस कारण मेरे क्षेत्र के गरीब लोग अत्यधिक परेशानी में हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे बुलढाणा संसदीय क्षेत्र के शेगांव, जलगांव, जामोद, संग्रामपुर, खानगांव, नांदुरा, मलकापुर इत्यादि स्थलों में किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तहसील स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक और अत्याधुनिक डायलेसिस सेन्टर्स की स्थापना किए जाने के साथ-साथ इसके ग्रामीण अंचलों में पानी में क्षार की अत्यधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए इसके निजात हेतु एक कार्य योजना लागू करके क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(इति)

Re: Need to start telecast of programmes from Doordarshan Kendra at Diwari sthan in Saharsa district, Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य का सहरसा जिला काफी पिछड़ा है। यहां दिवारी स्थान में 20KW एचपीटी दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण हुए लगभग 21 साल हो गये, लेकिन आज तक उसका ना उद्घाटन हुआ और ना ही उससे कार्यक्रम प्रसारित हो गया है। अब उसकी बाउंड्रीवाल भी गिरने लगी है जिससे आम जनता में क्षोभ और निराशा है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से और सूचना और प्रसारण मंत्री जी से आग्रह है कि दिवारी स्थान में बने दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र चालू कराये, और उससे एफ.एम. स्पोर्ट्स तथा अन्य चैनलों के प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराये।

(इति)

Re: Sharing of coal cess between Centre and States

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Today I want to bring forth the issue of sharing the coal cess between centre and states. India's almost 20% of coal production comes from mines of Odisha. While the state has always been supportive of centre's policies to increase the production to meet the national demand, the state does not have any such benefits reciprocated. From the inception of the Clean Energy Cess or commonly known as Coal Cess in 2010, tax has increased 800% with current rate of Rs. 400 per tonne collecting almost Rs. 87,000 crores till the FY 2017-18.

I would humbly want to draw your attention to the amount of fund that has transformed in any kind of project for promoting clean energy initiatives. Only Rs. 15,911.49 crore of the total funds, which is roughly 18% of total funds have been utilised for the clean energy projects by the National Clean Energy Fund (NCEF). In spite of enough evidence of no action and multiple neglected requests of states to allocate the funds for state level projects, we seem to be at impasse.

Supporting the federal nature of our constitution, I on behalf of my state strongly argue for a definitive plan of action from the government, either by preparing a roadmap to spend the remaining unallocated funds within next year dedicated to improve the clean energy production or to devise a mechanism to share the funds with the states enabling them to boost more project required in the energy sector.

(ends)

Re: Setting up of a AYUSH hospital in Vikarabad, Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): After persistent demands from the people of Vikarabad, Ministry of AYUSH has approved setting up of 50-bedded integrated AYUSH Hospital under National AYUSH Mission in 2016-17 in Anantgiri, Vikarabad, Ranga Reddy district of Telangana.

I am given to understand that Ministry of AYUSH has also sanctioned Rs, 200 lakhs for preparing DPR. Being sanctioned under a Centrally Sponsored Scheme, the Government has to provide Rs. 900 lakhs for construction, furniture, fixture, equipment, etc., Rs. 30 lakhs annually for medicines, diet and other consumables and Rs. 11 lakhs for salaries.

The objective of setting up of this 50-bedded hospital in Vikarabad is to ensure the optimal development and propagation of AYUSH system of healthcare with focused attention on development of education and research in Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy.

Since 2016-17, the proposal is moving at snail's pace and I even don't know whether DPR has been prepared. In view of the above, I request the Hon'ble Minister of AYUSH to ensure that DPR is prepared early and also request to take up construction work of hospital and complete it in a time-bound manner.

(ends)

Re: Budgetary allocation for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) scheme is acclaimed to be the largest public works employment project in the world. The World Bank in its World Development Report 2014 has termed the MGNREG Act as a stellar example of rural development. The NCAER study of 2015 shows that the act has achieved lowering rural poverty by almost 32 per cent between 2005-06 and 2011-12. This has prevented 14 million people from falling into poverty trap. But MGNREG scheme suffers the worst apathy of the government. Budgetary allocations for the programme have constantly fallen, in comparison to the revised expenditure presented every year. It is awfully inadequate, given the wage payment arrears. Wages are not being paid to the workers regularly and the wage arrears have heaped too high. There are instances of suicides because of non-payment of wages. Average number of person days employed have gone down to only 35 days per year. Alleged Corruption in handling public funds meant for MGNREG schemes has been reported in many states.

Government should immediately intervene to pay the arrears amount in every village. Sufficient funds should be allocated to improve implementation of the scheme in full force. Number of workdays should be enhanced to 200 and the minimum wage to Rs. 500/ day. Workers under MGNREGA should be declared as scheme workers and all the benefits and social security available to the scheme workers should be made available to them. Moreover, the banks are levying minimum balance charges on the accounts of the workers. Ministry of Finance should take immediate steps to stop levying of minimum balance charges and the charges levied on the accounts of the MGNREGA beneficiaries in the past three-year period should be refunded.

(ends)

SPECIAL MENTIONS

1404 hours

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Thank you, Sir.

In Salem District, 3 to 4 lakh people are involved in silver anklet-making, a cottage industry, for over 100 years. Silver anklets, which are manufactured in Salem District, are being sold in many States in India. Men, housewives and unemployed women are directly involved in this industry, and their families are dependent on this industry for their livelihood. Daily, 5 to 6 tonnes of silver anklets are manufactured, and the annual turnover is worth around Rs. 5,000 crore. Revenue of the silver industry is also a factor in the growth of Salem District.

The industry has been declining due to inclusion of online trade of silver, the price of silver not being stable, and its fluctuation is abnormal. Prior to this, no taxes were imposed on the silver anklet-manufacturing cottage industries. Further, the workers in the industry are losing their jobs as GST has been imposed on the silver anklet-manufacturing industries.

I would request the Central Government, through you, to completely exempt the GST tax imposed on the silver-anklet manufacturing industries. I would also request the Central Government to ban online trade of silver. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1405/SPR/NK)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, an All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) was sanctioned for Kerala but the same is yet to be established. Considering the importance of providing expert medical care and advanced facilities for treatment at affordable cost to lakhs of pilgrims at Sabarimala , I urge upon the Central Government to take immediate steps in establishing the AIIMS hospital sanctioned for Kerala and the same is to be located at Chengannur, which is located in the central part of Travancore.

Chengannur is the gateway to Sabarimala in Kerala, where lakhs of pilgrims from entire southern India assemble, reside and

transit. Only a medical facility such as AIIMS can offer treatment and medical emergencies effectively at affordable costs. Besides Sabarimala, an advanced hospital like AIIMS would also serve the needs of the entire central Travancore region and Chengannur, which is also located at a vantage point for ease of movement of people in the surrounding districts.

I must add that as per *Mathrubhumi* news report of 9th December, 2019 – *Mathrubhumi* is one of the largest newspapers of Kerala - in the last three weeks of last month, since the opening of Sabarimala shrine this season, about 61,997 pilgrims sought treatment for various ailments, which includes cardiac conditions. Cardiac patients include people from the age group between 20 and 67 years. Pilgrims endure the severity of conditions. This increase in patients even in the first three weeks and lack of specialty healthcare in Sabarimala zone is worrisome.

Therefore, I would request the Government to take urgent steps in establishing the AIIMS at Chengannur and also release funds for the same. ...(Interruptions) If it is not possible, I would like to request the hon. Government to set up any other super speciality hospital in Chengannur so that pilgrims of Sabarimala would avail healthcare facilities.

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लागू की थी, जिसमें निचले तबके के गरीब लोगों के लिए निःशुल्क इलाज और जांच के माध्यम से हजारों-लाखों लोगों का इलाज होता था। परन्तु वर्तमान सरकार की योजना के अनुरूप कार्डधारक थे, लेकिन अब नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। जिससे गरीब लोगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में काफी आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आह्वान करता हूँ कि गरीबों की इस योजना को तुरंत चालू करे और नए कार्ड का वितरण शुरू करें।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी का गोल्डन प्रोजेक्ट 'आयुष्मान भारत' के अंदर आज गरीबों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। परन्तु बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड या आधार कार्ड में थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण आज उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है और वह इस सेवा से वंचित हो रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार का ऐसा डायरेक्शन हो कि इन सब छोटी-मोटी त्रुटियों पर ध्यान न देकर गरीबों का 'आयुष्मान भारत' का कार्ड बने, ताकि वे अपना इलाज करा सकें। इसके साथ-साथ इसमें सेल्फ चिकित्सा और सर्जरी के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज भी आयुष्मान भारत के तहत हो सके। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि ओपीडी के अंतर्गत इसमें उल्लेख नहीं है। यदि कोई गरीब व्यक्ति ओपीडी में जाता है, उसके पास डॉक्टर की फीस और प्राथमिक दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता है, जिससे वह इलाज नहीं करा पाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसमें और लोगों को जोड़ा जाए, अभी भी बहुत सारे गरीब और वंचित लोग छूटे हुए हैं और वह इससे जुड़ना चाहते हैं। भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए, आज के दिन कोई गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो गया है। किन्तु इस योजना के माध्यम से वह अपना इलाज करा पाते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

(1410/SK/UB)

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने मुम्बई एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए नवी मुम्बई के नजदीक एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू किया है। सरकार ने 1100 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करके नवी मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी को एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू करने के लिए कहा है। वर्ष 2021-22 तक एयरपोर्ट शुरू होने की संभावना है।

नागरिक उड्डयन मंत्री जी के पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुम्बई शहर से नवी मुम्बई एयरपोर्ट जाने के लिए एक छोर से 40 किलोमीटर और दूसरे छोर से 70-75 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग हो, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मेट्रो रेल हो या यातायात के अन्य साधन हों, का काम तत्काल शुरू करना चाहिए, ताकि जब वर्ष 2021-22 में एयरपोर्ट शुरू होगा तो मुम्बई के नागरिकों को यहां जाने के लिए असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इस प्लान की चर्चा स्थानीय राज्य सरकार और एयरपोर्ट निगम के साथ शुरू की जाए और इस काम को अंतिम स्वरूप दिया जाए। धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं आज आपके माध्यम से देश की सुरक्षा का बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। चीन की टेलीकॉम कंपनी हूएहवे कंपनी का संबंध सीधा चीन की फौज से है। इसके ऊपर एक नहीं अनेक बार डाटा चोरी का आरोप लग चुका है। इसके सीईओ वर्तमान में जेल में हैं। ये सारा डाटा चोरी करके चीन की फौज को देते हैं, इसके कारण देश की सुरक्षा को खतरा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां, चाहे गुगल हो या कोई और हो, इन सबने इससे सामान लेने पर रोक लगाई हुई है। हमारे देश में जानकारी के अभाव से इनकी बिक्री खुले रूप से हो रही है।

महोदय, 5जी के लिए जरूरी इक्विपमेंट का निर्माण भी इनके द्वारा किया जा रहा है, जो ये कंपनियां बेच रही हैं। हमारे देश के लोगों और सरकार द्वारा जानकारी के अभाव में सामान खरीदा

जा रहा है, जिसके कारण देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क आदि देशों ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का सामान खरीदते हैं। ये लोग इसके माध्यम से डाटा चोरी करके चीन सरकार और चीनी फौज को प्रोवाइड कर रहे हैं। यह देश की सुरक्षा का विषय है। धन्यवाद।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

मैं लद्दाख यूनिजन टेरिटरी से आता हूँ, जो सबसे बड़ी, दुर्गम और बर्फीली लोक सभा कांस्टीटुएन्सी है। इस लोक सभा कांस्टीटुएन्सी में सर्दी में बर्फबारी और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन्स की वजह से कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जांजस्कार के शुनशादे से अक्षु अभ्रन तक, द्रास बटालिक, सांगकु से थैला इचु गांव और लेह डिस्ट्रिक्ट के नोपरा, चांगथांग और विशेष रूप से सिंगेलालो में रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, लैंड लॉक हो जाती है। सर्दी में इस वजह से केवल अपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से ही नहीं बल्कि ब्लॉक तहसील हैडक्वार्टर से भी यह रास्ता चार-पांच महीने के लिए बंद हो जाता है। इस कारण सरकार की ओर से जो स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और डैवलपमेंटल एक्टिविटीज चलाई जाती हैं, यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। साथ ही रिलीफ मैटीरियल भेजना होता है या और कुछ भेजना होता है, नहीं भेज पाने के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों को सुविधाएं देने के लिए तीन हेलीकॉप्टरों की जरूरत है।

(1415/MK/KMR)

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में तुरंत साधन पहुंचाने के लिए तीन हेलिकॉप्टरों की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में तीन हेलिकॉप्टर- एक लेह के लिए, एक कारगिल के लिए और एक इमरजेंसी के तौर पर सैंक्शन करके दें। लेह-मनाली और लेह-जोजिला दो तरफ रोड नेटवर्क रहता है। सर्दी में ये दोनों रोड नेटवर्क बंद रहते हैं। सोनमर्ग में कभी बर्फ होती है कभी नहीं होती है, लेकिन सोनमर्ग में लद्दाख के करीब 300 से ज्यादा व्हीकल्स 15-20 दिनों से स्ट्रैंडेड हैं। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उन लोगों के साथ भेदभाव करती है। लद्दाख के सिविलियन, जो वहां स्ट्रैंडेड हैं, उनके पास खाने के लिए जेब में पैसा नहीं है। उन लोगों को डंडा मारकर वहां से वापस लेह की बजाय श्रीनगर की तरफ भगा रहे हैं। सेलेक्टेड गाड़ियों को लेह और लद्दाख की तरफ छोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में पर्सनली इंटरवीन करें और उन लोगों को जल्द से जल्द सोनमर्ग से कारगिल लेह की तरफ भिजवाने की कृपा करें।

SHRI A. NARAYANA SWAMY (CHITRADURGA): Hon. Speaker, Sir, thank you for permitting me to draw the attention of the House to an urgent matter of my

Parliamentary Constituency Chitradurga, which is a Constituency reserved for Scheduled Castes in Karnataka.

Chitradurga is declared as a drought area where there is no irrigation facility and drinking water. The people in Chitradurga are suffering from diseases like fluorosis caused by presence of excess fluoride. Women who are mainly suffering from excessive bleeding, infection in uterus and tumour in the uterus are forced to go in for removal of uterus. More than 3000 such cases per annum can be seen. At the same time, we find cervix mouth and cervical cancer in more women. This Government announced setting up of medical colleges in many Districts but my Constituency was left out. So, I humbly urge upon the hon. Prime Minister and the hon. Health Minister to announce setting up of a medical college in Chitradurga in the coming Budget and also set up clinical research facilities and provide medical interventions that are required regularly to address the issues. Thank you.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Hon Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government, through you, to a very serious issue of my Constituency Kasargod.

Sir, the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Hindustan Petroleum Corporation Limited have jointly submitted a plan to the Government of Kerala for setting up of a mammoth petroleum storage terminal at Payyanur in Kasargod Parliamentary Constituency in Kerala.

The State Environmental Impact Assessment Authority has denied approval to the project based on the ambiguity on ground vibration and the geological features of the location. The location earmarked, 85 acres of land, is an ecologically fragile area having mangrove forests, paddy fields, waterbodies, rivers and backwaters. The livelihood of thousands of people who rely upon agriculture and fishing would be badly affected. The Indian Naval Academy is only two kilometres away from the proposed petroleum storage terminal. In the backdrop of the drone attack on oil storage facilities in Saudi Arabia recently, such a plant will jeopardise national security.

The State Government has expressed its disinterest to acquire land for the project as the Union Government is planning to disinvest its stake in the BPCL. Furthermore, the Union Government is targeting to switch over from fuel-based vehicles to e-vehicles within next 10 years. All these factors nullify the

grounds for such a big petroleum storage terminal at Payyanur in Kannur. The local people are agitating against the proposed project. So, I request the Government to cancel the petroleum storage terminal project at Payyanur immediately.

(1420/YSH/SNT)

माननीय अध्यक्ष : श्री राम कृपाल यादव उपस्थित नहीं।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मार्ग 77 मधौल से मुजफ्फरपुर के बीच हमारे संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर सड़क काफी खराब और जर्जर स्थिति में है। वहां हर दिन दुर्घटना होती रहती है। जान-माल की भी क्षति होती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का भी कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया है। बार-बार आग्रह के बाद भी सड़कें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष जी, एनएचआई बिहार में टोल का तो निर्माण जल्द कर देती है, लेकिन हाजीपुर-छपरा और हाजीपुर-मुजफ्फरपुर का लगभग 10 साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर एनएचआई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुजफ्फरपुर से हाजीपुर और हाजीपुर से छपरा राजमार्ग को जल्दी ठीक कराया जाए। इस पर निर्माण कार्य कराया जाए और साथ ही साथ मधौल से मुजफ्फरपुर जो दो किलोमीटर की सड़क है, उसे भी ठीक कराया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को श्री अजय निषाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): स्पीकर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या पर दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रभाव मेरे संसदीय क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। पंजाब में पिछले पांच सालों में एचआईवी एड्स के मरीज 34 परसेंट बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के साथ करीब साढ़े आठ लाख एचआईवी पेशेंट पूरे हिन्दुस्तान में हैं, उसका 12.29 परसेंट का हिस्सा पंजाब में बढ़ा है। सर, इसकी एक वजह है। इंजेक्टेबल ड्रग यूजर का जो टीका लगाते हैं, उसकी समस्या अमृतसर में बहुत ज्यादा है। पंजाब के अमृतसर शहर में 16,500 पेशेंट है। इसके लिए पंजाब सरकार ने कोशिश की है। पंजाब सरकार ने ऑड क्लिनिक खोले हैं। सात लाख बीस हजार लोग जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें से सिर्फ दो लाख दस हजार लोग ऑड क्लिनिक तक पहुंचे हैं। यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमृतसर शहर में लोग कष्ट कम करने के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें न्यूजपेपर्स में आती हैं तो यह बहुत शर्म की बात होती है। मेरी आप से दरखास्त है कि सरकार इस बीमारी के ऊपर ध्यान दे। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, वे तो लेते ही हैं। उनकी जरूरत बढ़ गई है। बेरोजगारी की वजह से और पाकिस्तान की वजह से यह समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरी आपसे दरखास्त है कि सरकार इस पर एक्शन ले और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध कराए और उनके इलाज का प्रबंध करे।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सर, धन्यवाद। मेरे ऊपर इनकी अपार कृपा है। यह बाबा भोले हैं। यह सबके लिए हैं। बाबा भोले की जया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और साथ ही साथ सरकार का ध्यान उन कम्प्यूटर पढ़ने वाले बच्चों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में सरकार ने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए एक स्कीम चलाई थी। वह स्कीम आईसीटीआई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए थी। इसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर की पढ़ाई होती थी। कुछ वर्षों के बाद कम्प्यूटर शिक्षा समाप्त कर दी गई, क्योंकि सरकार की स्कीम बंद हो गई थी। इसे कई राज्य चला रहे हैं और कई राज्य नहीं चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विगत चार वर्षों से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम्प्यूटर की शिक्षा ठप्प पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है।

सर, आज कम्प्यूटर युग आ गया है और बचपन से ही बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा मिले, इसके लिए हर आदमी, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे कम्प्यूटर की पढ़ाई करें। कम्प्यूटर के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। विगत वर्षों में सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया था, जबकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन वहां पर पढ़ाई बंद है। हजारों शिक्षक जो इस पढ़ाई से जुड़े हुए थे, जो कम्प्यूटर की पढ़ाई करवाते थे, वे बेरोजगार हो गए हैं।

(1425/RPS/GM)

बच्चे भी कम्प्यूटर शिक्षा के अभाव में, खासकर गरीब और गांव के बच्चे, बहुत परेशानी में हैं।

मैं, आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अविलम्ब बच्चों पर ध्यान दीजिए। इससे जहां कम्प्यूटर के शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार मिलेगा, वहीं कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को एक नया जीवन देने का काम भी करेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि अविलम्ब हस्तक्षेप करके इस स्कीम पर विचार कीजिए और इसे पूरे देश में चलाइए। धन्यवाद।

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, Kolkata Metro Rail Corporation governed by the Railway board has increased the fare prices by Rs. 5 for all stages except the first two-kilometre journey, thereby causing financial burden on 6.5 lakh passengers on daily basis, particularly lakhs of common people who come from low income groups, students, unemployed youth and retired senior citizens. Why did the Railway Board burden the common people with fare hike? Why did the Railway Board not take into consideration other options to increase revenue, like setting up retail outlets, pharmacies, installation of ATMs etc. What measures has the Kolkata Metro Rail Corporation taken to improve the poorly maintained Metro and frequent disruptions, accidents and disasters including the unprecedented one on 31st

August when 50 buildings in Bowbazar area were found having cracks and around 400 persons evacuated? Ms. Mamata Banerjee was the Railway Minister for a long time but she never increased the fare. I request the Railway minister to consider taking back the price hike of Metro tickets.

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, I take this opportunity to draw the attention of the Government to the increasing problem of intrusion of elephants into human habitats in Thalli and Shoolagiri talukas of Krishnagiri district. It is high time to have a strategy with environmental factors and human factors to eliminate the intrusion of wild animals. The enormous increase in human population propelled by the agricultural and industrial growth has led to the conversion of forest land into human settlements. Due to this, the wild elephant and other animals face acute shortage of resources, such as water and food, forcing them to often move into the human habitats. In addition, using the man-made devices like detonators for wild retaliation is resulting into crop damage, human injuries and human casualties. Some precautionary measures like fencing are only temporary solutions and there is a need to design a wireless sensor network-based system for elephant intrusion. It will access a base station, collect the information from different sensors and the message collected can be automatically transmitted to the forest officials to avoid the intrusion of elephants. Therefore, there is a need for such an intelligent elephant surveillance and tracking system. I request the Government to initiate suitable measures to bring down the casualty of lives and other potential damages.

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Hon. Speaker, Sir, in my Parliamentary Constituency, Walajapaet is the first established municipality in India and it is now 155 years old. There is a district headquarters hospital, which is situated on the Chennai-Bengaluru National Highway. This hospital has been constructed on both sides of the Highway. There are 5000 out-patients and 500 in-patients from about 100 nearby villages visiting the hospital daily. The beneficiaries of this hospital are from poor agricultural background and down-trodden people. The patients have to cross this heavy traffic-congested National Highway from one side to other to avail their treatment from this hospital. As per the police records, about 30 to 40 accidents are taking place every day on this stretch. I urge the Government to provide an underground subway and a road

overbridge linking the villages on both sides of the National Highway-4, which will certainly help the patients and general public, especially the elderly people, to move freely and without fear to cross this road.

(1430/RSG/IND)

Every day more than 50,000 vehicles are passing through Arcot town in my constituency and it has turned out to be a congested traffic junction. This can be rectified if there is a bridge constructed near the S.S.S. College junction.

There are forty villages in and around Melvisharam-Poottuthakku, located close to the Chennai-Bangalore National Highway. There are 20 to 35 accidents taking place in this same area. Here also, we need a bridge.

There is a narrow bridge at Katpadi on the Vellore-Chittoor Highway which was constructed a hundred years ago and has become very old and weak. Being a small bridge, this has forced the vehicles to stand in a queue for long periods to cross this small bridge. This causes heavy traffic congestion in this area. So, one new bridge with capacity for more vehicles should be constructed to replace the old one.

In view of the above, I request the hon. Minister of Road Transport and Highways to provide necessary bridges or underpasses on the Chennai-Bangalore National Highway near Walajapet District Headquarters Hospital, near the S.S.S. College junction at Arcot town bypass bridge, at Melvisharam-Poottuthakku, and at Katpadi on the Vellore-Chittoor Highway.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Speaker Sir.

The Nagapattinam-Koodalur-Mysore Road NH-67 is an important road. From Nagapattinam to Thanjavur, the Phase-III was awarded by National Highway Authority of India to Madhucon Projects Limited to construct a two-lane highway at a cost of Rs. 417 crore. The project commenced in the year 2016 and was supposed to be completed in the year 2017 but the work was completed only up to 24 kilometres; the remaining portion of road length of 54 kilometres with four bypasses at different locations is still pending. Suddenly the contractor did not progress the work. The NHAI terminated the contract but the pending work of more than 54 kilometres is not completed. There are a lot of accidents on the 54-kilometres stretch of the road. Now with the north-east monsoon rainfall, a part of the road is getting damaged.

I would request the hon. Minister of Road Transport and Highways to take up the matter urgently for completing the work on the 54-kilometre portion. Thank you, Sir.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। हम आपसे छोटे हैं इसलिए 'माननीय' कहना, शायद हम जैसे सदस्यों के लिए जरूरी नहीं है। आप चेयर से हमें इज्जत दे रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

महोदय, मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने करतारपुर कोरिडोर गुरु नानक देव जी को चाहने वाले लोगों के लिए खोला है। चूंकि यह धर्म से जुड़ी बातें हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। हमारे बहुत बड़े लीडर परमजीत सिंह सरना जी गृह राज्य मंत्री और होम सैक्रेटरी से बात करके यहां से नगर कीर्तन लेकर गए। गुरु ग्रंथ साहब सोने की पालकी में रखा हुआ था। जब ग्रंथ साहब को बस से उतारा गया, तो सोने की पालकी से ग्रंथ साहब को बाहर निकालना पड़ा। इससे लोगों की धार्मिक आस्था हर्ट हुई है। मंत्री जी इस बात की इन्क्वायरी करें।

दूसरी बात यह है कि करीब 6 हजार से ज्यादा श्रद्धालु वहां गए। भारत सरकार ने सारे इंतजाम किए, लेकिन जब श्रद्धालु वापस आकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, तो मन दुखता है। लोग जब करतारपुर से प्रसाद लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं और अमृत भी लेकर आते हैं। जहां सिक्थोरिटी चैक है, वहां डॉग स्क्वायड से प्रसाद को चैक कराया जाता है। हमारे पास सिक्थोरिटी चैक करने के बहुत से गैजेट्स हैं। यह बात सही है कि सिक्थोरिटी देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन प्रसाद को अलग से चैक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि प्रसाद को डॉग्स से चैक कराया जाएगा, तो कहीं न कहीं हमारे देश के नाम पर और सिक्थोरिटी एजेंसीज के नाम पर लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान वाले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश वाले हमारी ज्यादा चैकिंग करते हैं।

महोदय, इसके लिए आप आर्डर करें और होम मिनिस्ट्री भी ध्यान में रखें कि डॉग प्रसाद चैक न करें, लेकिन बाकी सारी चैकिंग जरूर होनी चाहिए।

(1435/ASA/RK)

***श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली):** In the 2018-19 financial year for only the potato farmers of Hooghly district, the National Insurance Company Hooghly District Cooperative Bank Limited released Rs. 57,36,68384 in 11 blocks of Hooghly and on 17 October, a directive was issued that within 7 days i.e. by 25 October, the money would have to be deposited in the accounts of those 88,280 potato growers. But Speaker Sir, this premium amount was to be shared proportionately by the Centre, state and the potato farmers. However, the insurance claim could not be finalized as the State Government failed to pay its share of premium. The state government spends generously on festivals, pujas, sports, etc. The revenue

* Original Bengali.

earnings of the government have increased manifold due to GST; the salaries of the MLAs are regularly increasing. But when it comes to paying premium amount for farmers, the government declares that it has no money, the treasury is empty. In Singur, seeds are being strewn everywhere for agriculture, but only weeds are coming up instead of crops. The Central Minister has mentioned that West Bengal has opted out of the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme and has introduced a new scheme known as Bangla Fasal Bima Yojana (Bengal Crop Insurance Scheme). Actually the state government failed to pay its entire contribution to the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme. Therefore the final claim of 2018-19 has not been settled yet. West Bengal government has tried to come up with a new scheme in order to evade the payment of dues to its farmers. It wants to disburse the same amount in the name of Bangla Fasal Bima Yojana next year. Thus the farmers are being highly deprived.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, यह क्या हो रहा है? ऐसे चलेगा क्या?

...(व्यवधान) यू.पी. में बीजेपी ने क्या किया? ...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप अमृतसर से तमिलनाडु तक सबको टाइम देते हैं। ...(व्यवधान) आज अमृतसर को भी टाइम मिला और तमिलनाडु को भी टाइम मिला।

देश में शिक्षकों की हड़ताल वगैरह, जैसे गैस्ट टीचर्स हैं, जैसे जे.एन.यू. में अभी हड़ताल हुई थी। इसी तरह से पंजाब में भी ई.टी.टी, बी.एड. और टैट पास जो शिक्षक हैं, वे पिछले तीन महीने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र संगरूर, जहां से शिक्षा मंत्री भी बिलॉग करते हैं, वे वहां पर हड़ताल करके बैठे हैं। उन पर लाठीचार्ज होता है और पिछले दिनों हमारे पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत भद्दी गाली उनको दी जिससे वे बहुत ज्यादा आहत हैं।...(व्यवधान) मैं यह चाहता हूँ कि ई.टी.टी. और टैट पास जो टीचर्स हैं, उनका जो मसला है, क्योंकि मैं स्वयं एक टीचर का बेटा हूँ। टीचर को नेशन बिल्डर कहते हैं। लेकिन अगर उनको लाठियां पड़ेंगी, उन पर अत्याचार होगा, खासकर वहां पर गर्ल्स टीचर्स भी हैं, तो वे आगे जाकर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगी? पंजाब सरकार की इस नालायकी पर मुझे यहां स्टेट इश्यू पर बोलना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि एच.आर.डी. मिनिस्ट्री इसमें हस्तक्षेप करके पंजाब में पिछले तीन महीने से जो ई.टी.टी. और बी.एड. पास टीचर्स हड़ताल पर बैठे हैं, उनका मसला हल करे। उनको नौकरी दी जाए। वहां स्कूल खाली पड़े हैं, टीचर्स हड़ताल पर बैठे हैं। पंजाब के इस मसले की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि भारत के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय रहे हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे तथा उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज-सुधारक, विचारक, चिंतक एवं साहित्यकार थे तथा उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं।

(1440/RAJ/RC)

सर्वप्रथम उन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने स्वीकार किया था। सबसे पहले उन्होंने ही राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता हेतु भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वीर सावरकर ही ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे, जिन्हें फ्रांस, विदेशी भूमि पर बंदी बनाने के कारण मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा। साथ ही साथ, वे पहले ऐसे क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही, अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरोध में आंदोलन शुरू किया।

अंत में, मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राष्ट्र के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दे।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सत्र के लिए दो दिनों का समय बचा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सदस्य शून्य काल में अपना विषय उठा सकें। इसलिए आप सभी की अनुमति हो तो एक मिनट में अपना विषय रख दें। अगर ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो मैं 15 सेकेंड का और समय दे दूंगा। क्या आप सभी की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, पूरा देश नवम्बर-दिसम्बर में गीतामयी हो गया है। इसमें हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का प्रयास है और गीता मुनि स्वामी ज्ञानंद महाराज की वजह से पूरा देश गीतामयी हो गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि श्रीमद् भगवत गीता एक सर्वकालिक और सर्व अलौकिक ग्रंथ है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1785 में वारेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विलिकिन्स के द्वारा इसे अंग्रेजी में अनुवाद कराया। उसके बाद 15 वर्षों में इसका फ्रेंच और जापानी भाषाओं में अनुवाद हुआ। आज न्यूजर्सी, हार्वर्ड और सियाटन यूनिवर्सिटीज में इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इसे उत्तरों की किताब, आनसर्स ऑफ बुक कहते थे। वास्तव में गीता जी सभी समास्याओं का समाधान हैं। उदाहरण के तौर पर, चिकित्साओं के लिए चिकित्सा शास्त्र, कानून व न्यायवादियों के लिए न्यायशास्त्र, मनोवैज्ञानिकों के लिए मानस शास्त्र और दार्शनिकों के लिए दर्शन शास्त्र है। इसे आप जिस दृष्टि से देखेंगे, वैसी ही प्रतीत होती है। हमारा कोई दृष्टि दोष है कि हम इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर सकें हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि स्वाधीनता सेनानियों के लिए यह जीवन का अंग रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने सदन में सहमति दी है, घड़ी लगी हुई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

...(व्यवधान)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, इसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसको ऐसे बोलते कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तीस सेकेंड में बात पूरी हो गई।

श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, in our country snake bite incidents has become a problem. In Kerala, one girl student died in the class room itself because of snake bite. So many snake bite incidents are taking place. Around 46,000 people die and 1,40,000 people become disabled every year because of this.

The problem is that we do not have region-specific and species-specific anti-venom. So, I would urge upon the Government to re-visit the manufacturing protocol and develop region-specific therapies for snake bite. It should ensure sufficient availability of drugs in the country so that the people are provided with proper treatment in time and their lives are saved. This is what I want to bring to the notice of the Government.

श्री अजय कुमार (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में रेल मार्ग मैलानी-बहराइच है, जो जंगल से होकर गुजरता है और आमान परिवर्तन, उसका एनओसी वन विभाग से नहीं मिल पाने के कारण नहीं हो सका है, इससे हमारे जिले की रेल सेवा प्रभावित हुई है और एक बड़ा भू-भाग रेलवे सेवा से वंचित हो रहा था, जिसमें रेल मंत्रालय ने एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर पलिया, निघासन, बेलरायां और सिंघाई रेल मार्ग की घोषणा की है।

(1445/VB/SNB)

जिसका सर्वे प्रारम्भ हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त मार्ग का सर्वे शीघ्र पूरा करवाकर बेलरायां, पलिया कलां, सिंघाई और निघासन रेल मार्ग को शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा को श्री अजय कुमार द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Sir, I would like to bring to your kind notice that one Swami Vivekanand Institute of Rehabilitation Training and Research Centre (SVNIRTAR) under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is located in the Cuttack district of Odisha and has been in existence since 1975.

Till date this premier institution is rendering its service to disabled people and also is working hard to meet the challenge of accessibility, inclusion and

empowerment of PWDS and also providing comprehensive rehabilitation services to persons with locomotor disabilities.

Presently, this institution is facing a lot of problems which require immediate attention. I would like to request the hon. Minister, through you, to take early steps to take care of its infrastructural deficiencies. The institution needs a multi-storied building to work as an administrative office, one 1000-seat auditorium and one workshop as the said unit is functioning for the last more than 40 years in AC sheet roofed building in damaged condition.

Secondly, the Artificial Limb Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), a Public Sector Undertaking of Government of India is not able to supply the required number of tricycles for disabled persons. Only around 50 per cent of the requirement is being met from ALIMCO for the last few years ...*(Interruptions)*

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित रेलवे के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

मैं यहाँ पर दिवा-वसाई रेल लाइन के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र में अपर कोपर स्टेशन है। अपर कोपर स्टेशन से दिन भर में केवल चार मेमू रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसके आसपास के इलाकों में दिन-ब-दिन आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 30 हजार यात्री रोज अपर कोपर स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। कल्याण- दिवा-वसाई रेल लाइन पर सिर्फ चार रेलगाड़ियाँ चलती हैं। पहली, सुबह पौने छः बजे चलती है, उसके बाद दूसरी, सीधे दस बजे चलती है। लास्ट की ट्रेन रात को आठ बजे वहाँ से चलती है। अगर लोगों को दफ्तर जाना है या काम पर जाना है, तो लोगों को वहाँ नौ बजे पहुँचना पड़ता है। लेकिन पहली गाड़ी सुबह पौने छः बजे होने के कारण लोग वहाँ दो घंटे पहले पहुँचते हैं।

मैं यह दरखास्त करता हूँ कि ज्यादा-से-ज्यादा मेमू गाड़ियाँ इस स्टेशन से चलाई जाएँ। मैंने पहले भी इस सदन में यह विषय रखा है कि इस सब-अर्बन सेक्शन पर लोकल ट्रेन शुरू करने की बात मार्च में ही हुई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए जल्द-से-जल्द इस सब-अर्बन सेक्शन पर लोकल ट्रेन सर्विस और मेमू ट्रेन की सर्विस बढ़ाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी ने ही फैसला किया है कि इसे एक मिनट में खत्म करना है।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो मुद्दा उठाने का मौका दिया है, वह बहुत ही दर्द भरा है। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मण्डी में भीषण अग्निकांड हुआ। लोग इसे अग्निकांड कह रहे हैं। तीन दिनों की अपनी फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि यह अग्निकांड नहीं है, बल्कि यह एक नरसंहार है। इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास सात लाइनों की बात है। उस प्लैट में घरेलू मीटर कनेक्शन लगा था, उसका बिल लाखों रुपये में आता था, लेकिन बिजली विभाग इस पर चुप था। वह क्यों चुप था, यह सवाल

है। उसमें फैक्ट्री चल रही थी, उसका कोई लाइसेंस नहीं था। लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चुप था। एक फ्लैट में सौ से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, उसमें चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट चुप था। उसमें से एक आदमी ने डेढ़ मिनट के लिए फोन किया और वह चिल्लाता रहा कि मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था।

(1450/SPS/RU)

वहां का विधायक आम आदमी पार्टी का है, वहां का पार्षद आम आदमी पार्टी का है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वर्ष 2017 से री-डेवलपमेंट प्लान में शिफ्ट नहीं किया गया। मैं आपके मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार गरीबों को मौत न दे। इसके लिए उससे जवाब मांगना पड़ेगा। इसमें 43 गरीब लोग, वे चाहे बिहार के ही क्यों न हो, मर गए हैं। क्या गरीब यहां मरने के लिए आए हैं? कुछ दिन पहले इन्होंने बिहार के लिए खराब स्टेटमेंट दिया था। कुछ दिन पहले इसी सी.एम. ने कहा था कि 500 रुपये की टिकट लेकर चले आते हो और आज उसी बिहार के 43 लेबर्स जलने और सफोकेशन से मर गए हैं। ... (व्यवधान) मत बोलिए, इस पर बोलने का अधिकार नहीं है, आप काम करिए। मैं आपके मार्फत चाहता हूं कि संसद जवाब मांगे कि सरकार ने आंख बंद क्यों रखी?

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेड्डी, श्री जनार्दन सिंह सिग्ग्रीवाल और श्रीमती रमा देवी को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चिराग पासवान (जमुई): स्पीकर महोदय, धन्यवाद। मैं भी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी की तरफ से बात रखना चाहता हूं। रविवार की सुबह इस दुखद समाचार को लेकर आई। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं, जिनको आप उम्र भर नहीं भूल सकते हैं और यह भी उन्हीं घटनाओं में से एक है, लेकिन जरूरत है कि जब ऐसी घटना घटित हो तो उसके बाद ऐसी कार्रवाई की जाए कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच होगी। निरंतर यह कहा जा रहा है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन मेरा सवाल है और हमें यह जानने की जरूरत है कि दोषी कौन है? इस घटना में जो लोग दोषी हों, उनके लिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उनके प्रति नामजद एफ.आई.आर. दर्ज हो। मुझे नहीं पता कि सही मायने में वहां का मकान मालिक दोषी है, वहां की जितनी अथॉरिटीज हैं, उनमें जल बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, एम.सी.डी. हो, डी.डी.ए. हो या स्थानीय नेता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो दोषी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए।

सर, एक रिहायशी इलाके में चार मंजिला इमारत थी। वहां हमारी पार्टी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से सांसद हैं, हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी सहित जनशक्ति पार्टी का एक डेलीगेशन गया। बिहार के जो 43 लोग मरे हैं, उनके लिए मुझे ज्यादा दुख इसलिए होता है, क्योंकि वे मेरे प्रदेश के लोग हैं और हजार किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए अपना प्रदेश छोड़कर यहां पर आते हैं, लेकिन उनके घर उनकी लाश जाती है। इससे बड़ी दुखद घटना और कोई नहीं घट सकती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दोषियों को चिह्नित किया जाए, उन पर

नामदर्ज एफ.आई.आर. हो और मृतक के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा मिले, क्योंकि इसमें परिवार के इकलौते सदस्य की भी जान गई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा, श्री प्रिंस राज, श्री राम कृपाल यादव और श्रीमती रमा देवी को श्री चिराग पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, I am right behind the pillar. So, I have to pray only to Lord Narasimha before I speak here.

Sir, I thank you very much for allowing me to speak. Olympics is to be held next year but India traditionally does not get the number of medals for a country of our size. So, I think that it is essential that we build a sports culture in our country but our educational system does not encourage sports because it is so exam-oriented....(Interruptions) Sir, I urge upon the Minister of HRD to please make sports compulsory as a subject and prescribe certain physical tests which a student has to qualify before writing his examination.

There are many schools which do not even have playgrounds. Schools which do not have playgrounds should be derecognised and physical education teachers must be given their due importance in schools. In most of the schools, physical education teachers are only used to pull up students who come late to class. You should make sports compulsory and perhaps come up with some criteria like running a mile within eight to ten minutes as a compulsory criterion to write public examination because parents nowadays are only focussed on exams and completely neglect sports. Unless it is made as a part of the curriculum and made compulsory that students should pass certain physical tests before you write the public exam, parents will never encourage students to participate in sports. That is the only way in which we can encourage a sporting culture in India.

(1455/MM/KSP)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिस पर आप स्वयं चिंतित हैं, प्रधानमंत्री चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं। कल ही बालयोगी ऑडिटोरियम में डॉ. जे.वी. दीक्षित का "Keep Fit" पर व्याख्यान आपने करवाया है। स्वाभाविक है कि आपने स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण विषय माना है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज बच्चों में पेकेज्ड जंक फूड खाने का प्रचलन बढ़ रहा है। Nationwide Seventh Annual School Health Fitness Study, 2016 की रिपोर्ट आयी है। इस रिपोर्ट में आया है कि आजकल स्कूलों में फिटनेस का लेवल कम

होता जा रहा है और खास तौर से शहरी इलाकों में। जहांगीर हॉस्पिटल, पुणे ने भी किया है और यूसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, लंदन ने भी किया है, जिसमें 30 परसेंट बच्चे ओबेसी या ओवरवेट के शिकार हैं। इर्रैग्यूलर फूड हेबिट्स या जंक फूड के कारण 70 परसेंट बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके कारण उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, पुअर फिज़िकल हेल्थ हो रही है, रेस्पाइरेट्री प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यह तमाम सब हो रहा है। तीन सौ स्कूल्स के 9 से 17 साल के 13300 बच्चों का सर्वे हुआ है, जिसमें पाया गया कि 93 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो पेकेज्ड फूड खाते हैं, 60 परसेंट हाई सॉल्ट और हाई शुगर खाते हैं और 53 परसेंट बच्चे एक दिन में खाते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, इन्होंने रेग्युलेट करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनायी है जो फूड को रेग्युलेट करते हैं और बच्चों के लिए खास तौर से Food Safety and Standards (Safe Food and Healthy Diets for School Children) Regulations, 2019 भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का प्रचलन है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम एक Eat Right Campaign हो और स्वास्थ्य को नुकसान होने से रोकने के लिए कम से कम इस तरीके से लिखा जाए as not suitable for children जो पेकेज्ड फूड्स हैं, उन पर एक वॉनिंग हो, जिस प्रकार से सिगरेट पर होती है "Cigarette is injurious to health". यही मैं आपके माध्यम से बच्चों के लिए, जो भारत का भविष्य हैं, उनको बचाने के लिए आग्रह करना चाहता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्रीमती रेखा वर्मा को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Speaker, Sir, SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural rates for Employment) Software developed by the National Informatics Centre (NIC), which is used for MNREGS activities, is undergoing technical problems for the last few weeks. Due to the slowness of the software, the upload of documents, estimate creation and online approvals have not been done for the last few weeks. This is happening because of lack of server space while multiple logins are done during office hours. Consequent to this, the Gram Panchayat, which is the implementing agency of MNREGS in the State, fails to meet the demand of jobs from lakhs of registered workers. The Central Government should provide a dedicated server for the State as a permanent solution.

Then, a total of Rs. 1,000 crore is pending as Central share under various components in MNREGS, including Rs. 858 crore for wages, Rs. 78 crore for material components and Rs. 64 crore for administrative expenditure. I would also request that the Central Government should enhance MNREGS wages in

accordance with minimum wages provided in the State of Kerala which is Rs. 600 and also take necessary steps for generating 100 days work for all in a financial year.

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Mr. Speaker, Sir, I thank you for allowing me to raise a matter of urgent public importance relating to the question of irregularities in the Dhamra LNG Terminal. IOC constructed its own terminal in Ennore at a cost of Rs. 5,150 crore with a capacity of 5 MMBTU. Then, IOC and GAIL have entered into a 20-year User Pay Contract with a private group for the LNG Terminal in Dhamra for Rs. 46,500 crore. This was done without following a tender process. When I asked a question to the hon. Minister, in reply to my question, he said that this was done as a result of a long commercial negotiation, basically admitting that there was no tender process. Given that this will lead to higher prices for consumers in West Bengal, Bihar and Jharkhand and also that this will supply gas to two subsidised fertilizer plants, I think, this matter is of urgent importance which needs to be investigated. (1500/SJN/SRG)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। महोदय, मैं अपनी सीट से बोल रहा हूँ, जैसा कि आपका निर्देश है। महोदय, मैं बिहार के जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ दो करोड़ लोग रहते हैं, जो सारण कमिश्नरी में हैं। नेपाल से नारायणी नदी जो बिहार में गंडक केनाल के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है, उसकी एक लंबी धार 22 किलोमीटर तक नेपाल से पानी चलता है। उसके बाद 112 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जाता है और बिहार में 68 किलोमीटर पानी आता है। वर्ष 1956 की एक संधि नेपाल के साथ है और उत्तर प्रदेश की सरकार के भी साथ है। उसमें लगभग 15,000 क्यूसेक पानी बिहार में प्रवेश करता है। 15,000 क्यूसेक पानी में से लगभग 8,000 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश को चाहिए और 8,500 क्यूसेक पानी सिवान, गोपालगंज और छपरा को चाहिए।

मैं अपने जिले की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से हूँ। मैं यह बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जिसके बारे में, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूँ कि मेरा पानी चोरी कर लिया गया है, पिछले 50 वर्षों में मेरा लगभग 48,00,000 क्यूसेक पानी चोरी हो गया है। मेरा सारण जिला है, जो इस पूरी नहर के अंतिम छोर पर है, उसे औसतन तीन से चार हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था। पिछले 55 वर्षों में जो पानी उत्तर प्रदेश के धार से चलकर बिहार के बंटवारे में मिलना चाहिए था, वह हमारे क्षेत्र में प्रवेश न कर पाने के कारण आज सारण जिला को वाटर डेफिशिएंट घोषित कर दिया गया है। ललन जी भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं।

महोदय, मुझे यह पता लगाना है कि आखिर मेरा यह 48,00,000 क्यूसेक पानी क्या नेपाल में है? यहां पर माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हैं। वह भी इस पर संज्ञान ले सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में ही यह 48,00,000 क्यूसेक पानी चला गया है। हमारे किसानों और बिहार के सिवान, गोपालगंज और छपरा के दो करोड़ किसानों को पिछले 50 वर्षों में और अभी के मौसम में इससे 6,000 क्यूसेक पानी हमारे इलाके को देना चाहिए था। हमारी केनाल में एक भी बूंद पानी नहीं है। यह मामला बहुत संगीन है। आज भारत सरकार ने मेरे जिले को वाटर डेफिशिएंट घोषित किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि मेरे पानी को तलाश करके मेरे जिले में वापस भेजा जाए, जो संधि के तहत है। मेरा चोरी किया हुआ पानी कहां है, उसे मुझे वापस लौटाया जाए।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिमा) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रेल परियोजना के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिमा में कुरसेला से बिहारीगंज एक रेलखंड है, उसका सर्वे कराने का काम तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान साहब जी ने किया था। वर्ष 2004 और 2005 के रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था। आज बीस वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन उस रेल परियोजना पर कोई काम नहीं हो रहा है। बोर्ड टँगा हुआ है, शिलान्यास हो गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि कुरसेला-बिहारीगंज रेल खंड पर काम होना चाहिए। चूंकि यह पिछड़ों का इलाका है, यह काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ। हम लोगों ने पहले भी इस सदन में इस पर कई बार चर्चा की है। लेकिन उस पर कोई भी सकारात्मक काम नहीं हुआ है। यह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि इस परियोजना पर तेज गति से काम किया जाना चाहिए और इस पंचवर्षीय में यह काम पूरा होना चाहिए।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र क्योंझर जहां से मैं चुनकर आई हूँ, उसका करंजिया एक बहुत बड़ा असंबली सेगमेंट है। वहां की आबादी भी बहुत है, जो कि ज्यादातर ट्राइबल लोग हैं। आज के समय में भी वहां के लोग रेल की सुविधाओं से वंचित हैं। यह वहां के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, जिसे मैं इस सदन में आपके सामने रखना चाहती हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि मरवन जिले के बादामपहाड़ जहां पर एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है, वहां से जाजपुर रोड तक एक नई रेलवे लाइन वाया करंजिया-आनंदपुर तक बनाई जाए, जिससे कि करंजिया को नजदीकी टाउनशिप के साथ जोड़ा जा सके, ताकि वहां के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले सके। चाहे वह बिजनेस के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या फिर किसी और काम के लिए हो। मैं यह आशा करती हूँ कि मैंने यहां पर जो मांगें रखी हैं, उस पर माननीय रेल मंत्री जी ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और मेरे क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे।

(1505/KKD/GG)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHICODE): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for allowing me to raise an urgent matter of public importance.

It has been reported in a newspaper that the newly issued passports from Kozhikode Passport Office deviate from the standard passport booklet. Now, we can see that it carries the lotus symbol instead of 'lion symbol'. The same passports are being used in the 36 passport offices in our country.

The hon. Minister is present here. The lotus is printed inside a rectangle on the page where the passport officer's signature and seal are seen.

The lotus emblem causes a suspicion as it is the election symbol of the BJP, which is the Ruling Party at the Centre ...(*Interruptions*)

Sir, I can show a paper, 'Mathrubhumi', which has published this news with a photo. So, this is again a saffronisation of Government establishments.

I would, therefore, urge upon the Government that this booklet should be immediately withdrawn, and a high level inquiry be ordered into the matter.

Thank you.

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाले कलवा तथा हिरौली के बीच दो किलोमीटर लंबाई का नया एलिवेटिड रेल मार्ग का भूमि पूजन 10 दिसंबर, 2016 में माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा संपन्न हो चुका है। तीन साल होने के बावजूद भी वह काम धीमी गति से चल रहा है। इसमें खाली दीघा स्टेशन का काम चालू है, लेकिन जो दो किलोमीटर का एलिवेटिड ब्रिज है, उसमें 2100 झुग्गी-झोपड़ी बाधित होती हैं। उनका पुनर्वसन करने का काम एमएमआरडी के माध्यम से होना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप इस अतिमहत्वपूर्ण परियोजना के लिए एमएमआरडी को निर्देशित कर, इन झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों का पुनर्वासन का काम जल्द से जल्द करें।

SHRIMATI NUSRAT JAHAN RUHI (BASIRHAT): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise an important and urgent matter.

My Parliamentary Constituency, Basirhat, is a very important area in terms of national security as it is adjacent to the Bangladesh border and there are a lot of BSF camps situated over there. It is also the Gateway to Sunderbans. For better communication, increase of export-import, and to promote tourism in Sunderbans and Taki, it is very important that we construct

a national highway from Barasat to Hemnagar *via* Berachampa, Basirhat, Hasnabad and Hingaljanj, which is more than 100 kilometres distance.

Sir, this whole stretch is a very backward area. So, construction of national highway will contribute to the economic development and growth. Thus, I would request the Government to kindly accept my proposal and make sure that we have a national highway in that area. Thank you.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Respected Speaker, Sir, I am really thankful to you for allowing me to raise a very important and urgent matter of public importance.

The Coconut Development Board under the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, has come up with a scheme of area expansion in coconut farming by providing a financial assistance of Rs. 6,500 for two years and that too, in an instalment of Rs. 3,250 per annum.

Sir, the Board also initiated the formation of Coconut Producer Societies by associating 40 to 100 coconut growers in a contiguous area with a consolidated minimum of 4,000 to 5,000 palms. The objective is the 'socio-economic upliftment of the farmers through productivity improvement, cost reduction, efficient collective marketing & processing, and product diversification.

Sir, the Government is well aware of the fact that the cultivation of coconut costs around Rs. 80,000 for two years. So, this financial assistance of Rs. 6,500 is too meagre an amount. Hence, it is requested that as the Board itself envisages the 'socio-economic upliftment of the farmers' through this scheme, at least, an amount of Rs. 40,000 should be provided as an assistance to the coconut farmers.

Sir, as we all know, Odisha is very much naturally prone to calamities. In the last 'Fani' cyclone, the whole of coastal region, especially Sakhigopal, has been badly affected where nearly one lakh coconut trees have been devastated and 50,000 farmers' families are on the road. The State Government has done enough to rejuvenate them.

(1510/RP/KN)

Still it is not adequate. I request, through you, to the hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare to kindly look into this matter and provide the amount of assistance to the coconut farmers and producers. The hon. Minister

is also request to enhance it to a reasonable amount so that farmers can implement this scheme successfully in the State of Odisha and elsewhere.

*SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. As many as 20 Indian labourers have lost their lives in Sudan. A fire accident took place in a ceramic factory in Sudan, where 60 Indian labourers were working, Out of which 7 labourers are battling for their life. Mohammad Salim and Boopalan Balu of Tamil Nadu; Sonu Prasad of Uttar Pradesh; Billu Ram of Haryana; Rabindra Kumar Mann, Surendra Kumar and Bhajan Lal of Rajasthan are the seven Indian laboureres who are battling for their life with severe burns in the hospitals of Sudan. Even though Our Indian Embassy in Sudan has made necessary arrangements for providing medical care to those laboureres, the medical treatment is inadequate in a underdeveloped country like Sudan. Hon. Union Minister of External Affairs is very much present here in this august House. I urge upon him to take special attention on this issue and arrange for bringing those seven labourers to India through air ambulance besides providing them the required compensation. I also urge upon through you Hon. Speaker that the Government should take necessary steps to bring to India the bodies of 20 deceased Indian labourers. Thank you

श्री पशुपति कुमार पारस (हाजीपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बिहार के हाजीपुर से आता हूँ। हाजीपुर सुगौली रेलवे लाइन वर्ष 1996-97 में माननीय तत्कालीन रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के समय में स्वीकृत हुई थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था। 22 वर्ष बीत जाने के बाद वह कार्य आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ खगड़िया से कुशेश्वर स्थान वाया शहरबन्नी रेलवे लाइन की मंजूरी भी आदरणीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान द्वारा की गई थी। आज तक वहां जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है, जबकि वह क्षेत्र आदरणीय पासवान जी का गाँव है, घर है, मेरा भी घर है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि ये दोनों जो परियोजनाएँ हैं- हाजीपुर-सुगौली और खगड़िया-कुशेश्वर स्थान जो रेलवे लाइन हैं, उनको यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाए। उस पर यथाशीघ्र काम शुरू किया जाए।

दूसरा हाजीपुर में डीएम कार्यालय है। काफी भीड़ रहती है। काफी पदाधिकारी-कर्मचारी आते-जाते रहते हैं और वहाँ बहुत सी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जिनका ठहराव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री से आग्रह करूँगा कि हाजीपुर में जो भी एक्सप्रेस ट्रेन जाती हैं, उसका ठहराव हो। धन्यवाद।

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Thank you, Speaker, Sir, for allowing me to speak. In 'zero hour', through you, I would like to draw the attention of the Government towards a developmental demand of my constituency, that is,

Shirur, Maharashtra. Sir, in my constituency, there are three MIDCs where many plants of many multi-national companies are located. उसी के साथ मेरे क्षेत्र के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनकी मेहनत के बलबूते वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में होता है। उसी के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र में पिलग्रिमेज जैसे भीमाशंकर है, आलंदी है। हेरिटेज प्लेसेज जैसे शिवनेरी है, वधु-तुलापुर है। अष्ट विनायक में से चार विनायक वहाँ पर स्थित हैं। इसलिए आपके द्वारा मैं एविएशन मिनिस्ट्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वहाँ पर खेड़ तहसील में चाकन एरिया में एयरपोर्ट की मांग को पूरा किया जाए। ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

(1515/CS/RCP)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, क्या हम विदेश मंत्री जी से एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन माँग सकते हैं? विदेश मंत्री यहाँ पर हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, दो मिनट का समय दीजिए... (व्यवधान) 10 सेकेंड का समय दीजिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ना-ना, नहीं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, यह शून्य काल है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुभाष सरकार।

...(व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार (बंकुरा): मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद... (व्यवधान) इस शीतकालीन सत्र में, शून्य काल में एक बार भी मौका न मिलने के बावजूद आपकी कृपा से आज मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर मिला है... (व्यवधान)

*Respected Speaker Sir, I take the floor to raise an urgent matter relating to my state West Bengal. In the year 2014 when the Health Minister was Dr. Harshavardhan, who is also the present Minister of Health, West Bengal has asked for three projects. For three medical colleges, 150 crore rupees have been allocated under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana by the Central Government. This amount was earmarked for improved kidney treatment, special orthopedics treatment, neuro surgery, cardiac surgery etc. The 3 medical colleges are Bankura Medical College, Malda Medical College and North-Bengal Medical College. However, 5 years have already passed, the work has not been completed so far. No medical equipment has been purchased, doctors have also not been appointed. Moreover, there is no doctor in all the super-specialty hospitals which

have come up with the aid of National Health Mission. The hospital buildings have been constructed, equipment are in place, but there are no doctors or nurses. Patients are not getting proper treatment. This is the pathetic situation of the healthcare sector in West Bengal. The 150 crore rupees provided under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana have been squandered. Buildings have not been constructed, medical equipment have not be procured, doctors have not been appointed. Thus I urge upon Hon. Minister of Health to issue a letter to the state government in this regard and seek explanation on this issue.

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, the district of Wayanad which is predominantly inhabited by the tribal people is presently connected to other parts of Kerala mainly by the Thamarassery Churam Road which had been constructed during the British rule. ...(*Interruptions*) Due to increase in population and other factors such as people using this road as a route to Karnataka, the Government of Kerala had mooted an idea of the construction of another road Poozhithode-Peruvannamuzhi-Padinharethara Road and the then Chief Minister, Shri K. Karunakaran had laid the foundation stone in 1994. The proposed road is passing through the forest covering 13 kilometres. Two local Gram Panchayats in the area had agreed to surrender their land to the Forest Department in lieu of the forest land to be used for construction of the road. It is unfortunate that the road construction still remains to be a dream as environmental clearance has not been given by the Ministry of Environment and Forests till date.

I would, therefore, request that, considering the necessity of the new road, and in the larger public interest, environmental clearance may be given at the earliest.

Thank you, Sir.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हम एक क्लेरिफिकेशन माँगना चाहते हैं...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी।

...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय भर्तृहरि महताब जी।

...(*व्यवधान*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. I want to draw the attention of the Government towards the crisis of the Scheduled Tribes' education in the country, and particularly in Odisha. ...(*Interruptions*) Odisha has

the largest number of the Scheduled Tribes in the whole country.
...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं तो आप स्पष्टीकरण माँगने लग जायेंगे। सदन सिस्टम से चलता है। आप नियम-कानून के मुताबिक कुछ चीज माँगिए। आप प्रक्रिया से आइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, यह हमारे देश से जुड़ा हुआ प्रश्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दीजिए।

भर्तृहरि महताब जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the leader of the Congress Party is disturbing repeatedly. ...*(Interruptions)*

You have no right to disturb the 'Zero Hour' ...*(Interruptions)* If the Minister is free, if he is willing to respond, he will respond. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर उनसे मिल लेना।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We are not disturbing...*(Interruptions)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You do not hijack the House. ...*(Interruptions)* You cannot hijack the House. ...*(Interruptions)* We have also an equal right to speak. ...*(Interruptions)* You cannot hijack the House. ...*(Interruptions)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We are not hijacking...*(Interruptions)* It is our right...*(Interruptions)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): You are hijacking ...*(Interruptions)* You cannot hijack the House. ...*(Interruptions)*

(1520/MMN/RV)

You can only plead. You cannot hijack the House. You are disturbing others. ...*(Interruptions)* There is 'Zero Hour'. This is the 'Zero Hour' where you are doing this. ...*(Interruptions)*

Hon. Speaker, Sir, I want to draw the attention of the Government towards the crisis of the Scheduled Tribe's education in the country, particularly in Odisha. Odisha has the largest number of Scheduled Tribes in the whole country. The literacy rate of Scheduled Tribes of Odisha has constantly been

lower than that of the total population. The literacy rate of Scheduled Tribes was 52.24 per cent in 2011, while the overall literacy rate of Odisha was 72.9 per cent. The gap is that of 20.66 per cent. Adding to the hiatus, there is a huge disparity between male and female literacy rate of Scheduled Tribes. Sir, 51.48 per cent is the literacy rate for males and it is only 23.37 per cent for females. I would like to request the Government to come up with new education scholarship exclusively for the benefit of the Scheduled Tribe students of Odisha.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, through you, I would like to draw the kind attention of the Government to an important matter. I would like to say that pension was introduced in the banking industry in the year 1995 after decades of struggle. Pension is a social security cover for the superannuated officials. It particularly helps them to meet their medical and other basic needs of post-retirement. But even after two decades, neither the pension was reviewed nor was it updated for the bank employees. I would like to give a fair example regarding this. A General Manager, who retired before 2002 in the banking sector, receives somewhere around Rs.25,000 but after 2015, the same level General Manager is receiving Rs.65,000. One more thing is that the General Manager, who retired in the year 2000, gets lesser pension than a clerk who retired in the year 2015. But my argument is that with this paltry pension, some of the pensioners are not able to meet their medical expenses.

With one point, I would like to conclude. I would say that many pensioners are forced to take personal loans for paying the medical premium also. The final point I would like to tell you is that in March, 2019, the Finance Ministry has issued an order for updating the RBI's retirees but they have left out the national bank employees. Sir, since the Finance Minister is also available in the House, through you, Sir, I would like to request her to consider my request. Thank you.

DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for having allowed me to raise an important issue related to my South Chennai Constituency.

Tholkappia Poonga or Adyar Eco Park in the Adyar estuary area of Chennai is the brainchild of my mercurial leader, Dr. Kalaignar. He has named that park after the legendary iconic forerunner, Tholkappiar. Dr. Kalaignar's dream has been spearheaded by our Party Leader, Thalapathy M.K. Stalin. The

project was envisioned to be completed in three phases with the object of restoring the flora and fauna of that particular Adyar creek, estuary area, as well as preserving the fragile eco system and also safeguarding the endangered migratory birds. These are the objectives.

But the present Tamil Nadu State Government has been very lethargic. The Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Services Limited and Chennai Rivers Restoration Trust have been entrusted with the task of developing this park. The Phase-I of the park has 1,36,500 plants for the Adyar Poonga. The environmental clearance for it was obtained from the Union Ministry of Environment and Forests in mid-January, 2011. The second phase has also been delayed by the State Government, even though the funds have been allotted.

(1525/VR/MY)

To manage the Chennai River Restoration Trust and its activities, the Government formed a special purpose vehicle in the name of Adyar Poonga.

....(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 1 मिनट 15 सेकेंड में माइक बंद हो जाएगा। अब साढ़े तीन बजने वाले हैं। अभी जिन माननीय सदस्यों को शून्य काल में मौका नहीं मिला है, उन सभी माननीय सदस्यों को छह बजे के बाद मौका दिया जाएगा।

***श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम):** Thank you respected Speaker Sir, I take the floor to talk about the issues of my constituency Birbhum. The condition of National Highway 60 in my area is extremely pathetic. Buses are not able to ply on this road. The Siuri-Rampurhat bus is forced to take a detour through Kirnahar-Bolpur. So local people are facing a lot of problems. Moreover rampant accidents are taking place on this road. On the one hand the motorists are being advised by the Minister to wear helmets while riding two-wheelers, to fasten seat belts while driving cars, penalties and fines are being imposed on those who violate the rules to prevent deaths; on the other hand, nothing is being done to improve the conditions of the roads. Then if accidents occur and people die because of bad roads, who will be held responsible for that? So I demand that all the roads should be repaired immediately. Moreover, since 1960, the bridge over Morgram to Dubrajpur road has never been repaired. The other bridges like Tilpara, Mallarpur, Brahmoni, Deucha canal, Kargil, Lake canal, Chandrabhaga, Bakreshwar are also tottering. If these are not repaired in time, any day, major accidents can happen. So Sir this is very urgent and should be addressed as early as possible. Thank you for giving me this opportunity.

सर, मुझे एक-दो मिनट और दे दीजिए। इतने कम समय में मैं आपकी तारीफ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा और मौका दे दीजिए, ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूँ।

माननीय अध्यक्ष: अभी तारीफ के लिए मौका नहीं है।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदन का ध्यान जनगणना 2021 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें संख्या से ज्यादा होने वाले ओबीसी समूह की गणना बहुत सालों से सरकार द्वारा नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, देश में वर्ष 1931 की जनगणना में आखिरी बार एकत्रित किए गए जातिगत आंकड़ों के आधार पर 52 प्रतिशत ओबीसी थे। इसी के आधार पर तैयार की गई मंडल आयोग की 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण की सिफारिशों के अनुसार तत्कालीन श्री वी. पी. सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। आने वाली 16वीं जनगणना के लिए वर्ष 2021 का कार्यक्रम सरकार द्वारा जाहिर हुआ है। इसी संदर्भ में अगस्त और सितम्बर 2019 में जनगणना प्रीटैस्ट भी हुआ है, लेकिन इस प्रीटैस्ट के अनुसार प्रश्नावली के 13 नंबर कॉलम में ओबीसी (वीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) का उल्लेख नहीं है।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरावती में वर्ष 2014 में वैगन रिपेयर वर्कशॉप लाँच हुई थी। अगर हम इसका आज तक का बजट देखते हैं तो यह टोटल 299 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो फिनिशिंग डेडलाइन दी गई है, उसके अनुसार वर्ष 2020 तक यह कारखाना कंप्लीट होना चाहिए, परंतु इन चार कंपनियों की वजह से आज तक इस कारखाने का काम 60 परसेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें विक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। प्रेमको कंपनी, जो कोलकाता से बिलाँग करती है, यह एक कंस्ट्रक्शन तथा इंजीनियरिंग कंपनी है। इसमें एक ब्लास्ट सप्लाय कंपनी भी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे किसानों की जगह गई है। वर्ष 2014 में रेलवे डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रॉमिस किया था कि वहां हर परिवार के एक मेम्बर को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। आज वहां किसी के पास भी काम नहीं है और सभी लोग बेरोजगार हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से विनती रहेगी कि ये जो कंपनियां हैं, इनके कामों के लिए एक इंकवायरी कमेटी बनानी चाहिए, इनके कामों का टैस्ट होना चाहिए और इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा में जो युवा हैं, उनमें जिस तरह से ड्रग्स एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश चारों तरफ से पंजाब और राजस्थान से घिरा हुआ है। हमारे जो युवा बच्चे हैं, उनमें ड्रग्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। वहां पाकिस्तान से भी स्मग्लिंग होकर ड्रग्स आते हैं। उन बच्चों में लड़के तथा लड़कियां भी हैं। इसकी वजह से उन बच्चों की मौत भी हो जाती है। सोशल स्टिग्मा की वजह से उनके माँ-बाप यह भी नहीं

बता सकते हैं कि इन बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। मुझे खुद उनके घरों में जाना पड़ा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। सरकार से मेरा आग्रह है कि ड्रग्स के अंदर जो स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कोई कानून आए। इसके साथ-साथ हर जगह रिहैबिलिटेशन तथा डिएडिक्शन सेन्टर खोले जाएं। मैं सिरसा लोक सभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ। मैं बॉर्डर पर स्थित डबवाली, कालावाली, रानियां, नरवाना तथा रतिया की बात कर रही हूँ। वहां हमारे युवाओं में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन फैल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में डिएडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेन्टर बनाए जाएं। सरकार उन सभी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लेकर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1530/SAN/CP)

**MOTION RE: REFERENCE OF PERSONAL DATA PROTECTION BILL
TO JOINT COMMITTEE**

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करें।

1530 hours

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS
AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data, specify the flow and usage of personal data, create a relationship of trust between persons and entities processing the personal data, protect the rights of individuals whose personal data are processed, to create a framework for organisational and technical measures in processing of data, laying down norms for social media intermediary, cross-border transfer, accountability of entities processing personal data, remedies for unauthorised and harmful processing, and to establish a Data Protection Authority of India for the said purposes and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members from this House, namely:-

1. Smt. Meenakashi Lekhi
2. Shri P.P. Chaudhary
3. Shri S. S. Ahluwalia
4. Shri Tejasvi Surya
5. Shri Ajay Bhatt
6. Col. Rajyavardhan Singh Rathore
7. Shri Sanjay Jaiswal
8. Dr. Kiritbhai Solanki
9. Shri Arvind Dharmapuri
10. Dr. Heena Gavit
11. Shri Uday Pratap Singh
12. Shri Rajiv Ranjan Singh

13. Shri Gaurav Gogoi
14. Ms. S. Jothimani
15. Prof. Saugata Roy
16. Smt. Kanimozhi
17. Shri P.V. Midhun Reddy
18. Dr. Shrikant Eknath Shinde
19. Shri Bhartruhari Mahtab
20. Shri Ritesh Pandey

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the last week of the Budget Session, 2020;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make;

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee; and

that the Speaker shall appoint one of the Members of the Committee to be its Chairperson.”

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रमाण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे

संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात् –

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री पी.पी. चौधरी
3. श्री एस.एस आहलुवालिया
4. श्री तेजस्वी सूर्या
5. श्री अजय भट्ट
6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री संजय जायसवाल
8. डॉ. कीर्तीभाई सोलंकी
9. श्री अरविंद धर्मापुरी
10. डॉ. हिना गावीत
11. श्री उदय प्रताप सिंह
12. श्री राजीव रंजन सिंह
13. श्री गौरव गोगोई
14. सुश्री एस. जोति मणि
15. प्रो. सौगत राय
16. श्रीमती कनिमोज़ी
17. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
19. श्री भर्तृहरि महताब
20. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे।”

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं विषय पढ़ दूँ, उसके बाद आपको मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चूंकि माननीय सदस्यों को विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर संशोधन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए मैंने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा दी गई संशोधन की सूचना को स्वीकृत किया है।

अब आप बोलिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, from my party, the name of Prof. Saugata Roy has been included. He is so busy with other party jobs and party works. So, we cannot put his name over here. I would request that the name of Shrimati Mahua Moitra may be inducted in that place. It is the decision of our party.

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, आप आपस में इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। फ्लोर लीडर से बात कर लीजिएगा।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): वोटिंग हो जाएगी, तो फिर कैसे होगा? उसके लिए फिर दोबारा वोटिंग करनी पड़ेगी। यदि हटाना है, तो अभी हटाना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Party Leaders should have been consulted. They have put the names in the Committee on their own. ... (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, Prof. Saugata Roy is a very important leader of our party. He is required to be engaged in so many jobs. ... (Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, whenever any Parliamentary Committee is formed, there is a system of coordination between the Parliamentary Affairs Minister and the parties concerned. To the best of our information, all this has been done. Therefore, I will have to stand by that.

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, आप बताइए। इसके बारे में क्या कहना है? इनके प्रस्ताव को स्वीकृत करना है या नहीं करना, दो लाइन बताइए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, यह जो मोशन आया है, इस मोशन पर जैसे अधीर रंजन जी भी बता रहे थे, किससे चर्चा की - सुरेश जी बैठे थे, कभी चीफ व्हिप से चर्चा हुई है, कभी फ्लोर लीडर से हुई, लेकिन कंसल्टेशन हुआ है और 10 से ज्यादा मेंबर्स वाली पार्टियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Whom has he consulted?
... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इनके प्रस्ताव को शामिल करना है या नहीं करना है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं चर्चा करके ही बता पाऊंगा। ... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, एक काम करें। इस प्रस्ताव में मैं ही मूव करता हूं कि जो माननीय टीएमसी लीडर की ओर से प्रस्ताव आया है, वह इसमें रहेगा कि ये चर्चा करके उसको कर लेंगे, ताकि उनके नाम को अभी हम लोग वोट में इनक्लूड नहीं करते हैं। हो गई बाता। ... (व्यवधान)

(1535/NK/RBN)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इसमें व्यवस्था यह होती है कि जो आप प्रस्ताव लाए हैं, इस प्रस्ताव को अगर परिवर्तन करना है तो कल लाएं, नहीं तो आज यही प्रस्ताव जाएगा।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, इस पर वोटिंग होने दें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इस विषय में मेरा कहना है कि आप आपस में चर्चा कर लिया करें।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, आज वोटिंग हो जाए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): In Rule 74 it is stated, "It be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council". But it has not been made clear whether the concurrence of the Council has been taken or not. हमारी मांग है कि इस पर पब्लिक ओपनियन इलिसिट करने के लिए इसे थोड़ा सर्कुलेट किया जाए। हमारी पार्टी के दो लोक सभा मेंबरों को दिया है। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, खुद आप जैसे मंत्री हैं, क्या हमारी पार्टी की तरफ से एक-दो मेंबर्स बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है? दो दिन पहले हम लोगों ने सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का लेजिस्लेशन पारित किया, यह नॉन मुस्लिम बिल पारित किया, यह भी एक नॉन मुस्लिम मोशन पारित होने जा रहा है। इसमें एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। यह ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, ये कैसी बातें कर रहे हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, thank you. Parliamentary Standing Committees are not formed on the basis of religion.

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी कि संसदीय समितियां धर्म के आधार पर नहीं बनाई जाती हैं।
...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, thank you very much. ...(*Interruptions*) I have given a notice moving of amendment to the Motion moved by the hon. Minister under Rule 75 (2) (b) of the Rules of Procedure and Conduct of their Business in Lok Sabha. My amendment is that this Bill be referred to the public for eliciting the public opinion thereon and to have a Report by 31st of March, 2020. That is the amendment which I would like to move. Unfortunately, there is a paucity of time. I fully agree with the hon. Speaker regarding the paucity of time. But at the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister to Rule 74. As per the proviso in Rule 74, two days' notice is compulsory or mandatory unless and otherwise the Speaker permits. I know that the Speaker has already permitted it.

SHRI PRALHAD JOSHI: You yourself has quoted the Rule. The Speaker has already permitted it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It has not been passed yet. It is only before the House.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिबेट होते रहनी चाहिए लेकिन एक शब्द नीचे लिखा हुआ है कि जिसे सभी लोग पढ़ते रहा करें। अध्यक्षीय व्यवस्था अंतिम व्यवस्था है नहीं तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): But the objections of the Opposition are very relevant. It is said, "such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made." So, we fully abide by the ruling of the hon. Speaker. Two days' notice has not been given.

(1540/SM/SK)

At least, before referring the Bill to the Joint Committee or to the Select Committee two days' notice has to be given. This is my submission. Once again, I would like to make this appeal because so many NGOs, so many voluntary organisations, social activists are very much concerned about the Data Protection Bill. They are very much interested in contributing to the Data Protection Bill.

So, my submission to the hon. Minister and the Government is kindly refer the matter to the Joint Committee for eliciting public opinion. Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, what happened to our proposal regarding the name of Shrimati Mahua Moitra that we had proposed? What is the decision ultimately taken?

माननीय अध्यक्ष: मैं सब की भावनाएं समझता हूं। मेरी सब की भावनाओं को देखते हुए कोशिश है कि हम सभी अधिकतम समय में संसदीय प्रक्रिया और नियमों का पालन करने का प्रयास करें। अगर बहुत आवश्यक हो तभी इस पर अध्यक्षीय छूट देने का प्रयास होना चाहिए। यह हमेशा प्रयास होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमसे हमारी पार्टी के मैम्बर्स का नाम नहीं पूछा गया। ...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): हमसे भी नहीं पूछा गया। ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

Sir, I want to say that Shri Suresh has given the name and everyday he comes to my chamber. It is a good thing. I am speaking to him and also to Shri Adhir Ranjan Chowdhury also. Sureshji has given the name. Now, if he wants to deny, let them change the name. We do not have any objection for that ...*(Interruptions)* What is this? अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वे सॉल्व करें, उसमें हमें मत लेकर आइए।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): When I went to his room, at that time, the hon. Minister was dictating the names of the Members of different political parties ...*(Interruptions)*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: He took the name from you ...*(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I was a witness for that ...*(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Rather, you dictated the names ...*(Interruptions)*

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्लेरिफाई कर दूँ क्योंकि प्रेमचन्द्रन जी का प्रस्ताव मूव हो रहा है। इसके कन्सलटेशन में 2000 ओपिनियन आए, देश में चार जगह कमेटी गई थी। हमारे विभाग ने अलग से कन्सलटेशन किया। जो कमेटी बनेगी उसे कन्सलट करने का पूरा अधिकार होगा।

मैं एक बात माननीय बंदोपाध्याय जी से कहूंगा कि प्रोफेसर राय बहुत ही सुलझे हुए डिस्टिंगुइश हैं। हम चाहते हैं कि सलैक्ट कमेटी को आपके व्यापक अनुभव का व्यापक लाभ मिले, इसलिए उन्हें ही रहने दें, यही मेरा आग्रह है। वोटिंग कराई जाए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, the Minister mentioned my name and addressed me. Ravi Shankar Ji, if you ask me, I will consider that Prof. Sougata Ray is the best person in the Parliament. उसमें क्या बात है? यह मेरी पार्टी का डिसेजन है। You cannot change my Party decision from your side. What decision my Party is going to take, I will communicate it to the House.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“That the Personal Data Protection Bill, 2019 be circulated for eliciting public opinion of the people thereon by 31st March, 2020”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Personal Data Protection Bill, 2019 be circulated for eliciting public opinion of the people thereon by 31st March, 2020”

The motion was negatived

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि व्यष्टिकों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित उनकी निजता के संरक्षण, वैयक्तिक डाटा के प्रवाह और उपयोग को विनिर्दिष्ट करने, व्यक्तियों और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में लगी इकाइयों के बीच विश्वास के संबंध का सृजन करने, ऐसे व्यष्टिकों के अधिकारों जिनके वैयक्तिक डाटा का प्रमाण किया गया है, का संरक्षण करने, डाटा का प्रक्रमण करने में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए ढांचा सृजित करने, सोशल मीडिया मध्यवर्ती, अंतरसीमा अंतरण के लिए सन्नियम अधिकथित करने, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाली इकाइयों की जवाबदेही, अप्राधिकृत और हानिकारक प्रक्रमण के लिए उपाय करने तथा उक्त प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य, अर्थात् –

21. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
22. श्री पी.पी. चौधरी
23. श्री एस.एस आहलुवालिया

24. श्री तेजस्वी सूर्या
25. श्री अजय भट्ट
26. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
27. श्री संजय जायसवाल
28. डॉ. कीर्तीभाई सोलंकी
29. श्री अरविंद धर्मापुरी
30. डॉ. हिना गावीत
31. श्री उदय प्रताप सिंह
32. श्री राजीव रंजन सिंह
33. श्री गौरव गोगोई
34. सुश्री एस. जोति मणि
35. प्रो. सौगत राय
36. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
37. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
38. श्री भर्तृहरि महताब
39. श्री रितेश पाण्डेय

तथा राज्य सभा के 10 सदस्य सम्मिलित होंगे

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष बनाएं;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित; और

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक

1544 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब मद संख्या 25 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 ली जाती है।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for the establishment of an Authority to develop and regulate the financial services market in the International Financial Services Centres in India and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

(1545/MK/AK)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी विधेयक के बारे में प्रस्तावना रखना चाहती हैं?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: जी हाँ सर।

माननीय अध्यक्ष: संक्षिप्त में रख दीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, around 2008, a Committee was appointed by the Ministry of Finance, and the Committee was headed by an eminent person called Shri Percy Mistry. He had gone through the entire issue of Financial Services and even at that time, by 2008, it was felt that by 2015 up to US\$ 50 billion will be spent on International Financial Services by the Indian companies and that amount would obviously be going outside of the country because we do not have an International Financial Services Centre.

Therefore, from then, the necessity of having a Financial Services Centre in India was recognised. In 2011, a Section in the SEZ Act, namely, Section 18 was brought in distinctly for establishing

a Financial Services Centre. Then, by 2015, it was made completely operationalized because the various regulators who deal with various financial institutions such as the RBI, the SEBI, the PFRDA and so on started issuing their notifications to regulate those institutions, which are now functioning in the GIFT-City of Ahmedabad, which we, in short, refer to as International Financial Services Centre.

Just to give you a status of what is there, the India's stock exchange, the BSE, has set up the INX there; the National Stock Exchange has established the IFSC Stock Exchange there; and the daily volume crossed US\$ 4 billion already. Besides this, there are about 13 international banking institutions, which are functioning from there. Banking transaction alone has crossed US\$ 24 billion. There are 40 or more operational brokers there, and about 100 plus are licensed. Insurance players are also already active there. There are about 19 plus players, all in the re-insurance business, and insurance intermediaries are also present there. Now, there are about 30 plus entities in IT and IT enabled services. All of these are bringing a certain advantage to India and Indian companies because now they do not need to go elsewhere to deal with international markets, to access international markets, to access international currencies, and also to participate in international financial functions.

Now, through this Bill, we are largely doing two things. One, we are bringing several of these regulators together as one unit to the limited extent of having to deal with the various institutions, which are present in the IFC. Together with it, we are also making it clear and defining as to what are the actual businesses, which are being recognized there. We are defining the various financial products

whether they are services or institutions. We are also defining IT enabled services in the financial sector.

They alone, in that IFSC, are providing employment to more than 10,000 people all of whom are engaged actively in the backroom processing of financial matters for global companies. Therefore, in short, what I would like to say at the beginning, in the opening remarks, is that this Bill is something, which was foreseen a long time ago.

(1550/SPR/YSH)

We wanted a unified authority to deal with a particular specialised financial services hub. We will, because it is established now, have something similar to London or Singapore in terms of international financial hub which will be giving the opportunities to Indian companies to be able to access international markets and deal with international markets through this centre. It has already been given quite a few tax concessional benefits. This Bill was earlier proposed in the Rajya Sabha but however because it was meant to be tabled only in Lok Sabha, being the Finance Bill, we had to withdraw from Rajya Sabha in spite of having obtained the Cabinet's approval in February, 2019.

Sir, it was withdrawn from Rajya Sabha. We have now come before Lok Sabha for consideration. Thank you very much, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

1551 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Hon. Speaker, Sir, this House has spoken about the state of economy many times. Many opinions have been voiced; statistics have been bandied about; and the Minister also gave some large numbers right now but economics is not only about numbers. Numbers sometimes do not tell the whole story. Numbers can be antiseptic. But the real story is the human story. When business is down, when people are not selling enough, there is a human cost. When a builder is not able to sell flats, he is not going to build more flats. What does it mean? It means that masons, bricklayers, electricians, plumbers are all not employed. When people are less employed, it means they have less money in their wallets. If they have less money in the wallets, it means they spend less. It also perhaps mean they go with empty stomachs. While numbers definitely tell a story, the human story is much more poignant and much more potent. What we can keep debating about economics until the cows come home. There is a popular joke in academia, if you put five economists in a room, you will get six opinions. I have an opinion myself. The Government really should be focusing on the demand side and not on the supply side. We can have a debate about this much later. But we should never ever forget the human story behind the economy. Under this backdrop, we have a Government today which constantly wants to portray a feelgood nationalistic story and glosses over not so pleasant and less than glamorous reality. True introspection will give better answers. But the Government's insensitivity or incomprehension of the realities of life for the most unfortunate comes off often. As it did recently with the onion episode.

1553 hours

(Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

I understand the Government's desire to create an economic hub of international standards in India. It is indeed a laudable goal. I am given to understand that the inspiration came when our Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat visited Singapore in 2007, which is why the Gujarat International Financial Tech City, which is popularly called the GIFT city was envisioned. But hear me out. But overambitious, grandiose scheme without thinking about the practicalities of a successful venture is the trademark of this Government.

Before going into the intricacies of the Bill, I would like to point out to this House that there is only one international financial services sector in India today, which is the GIFT city. So, when you think about the provisions of this Bill, where it will be applied, and who are the beneficiaries, it will only be applied to the thousand acres of land in India's favourite State, and to the GIFT city in Gandhi Nagar. It will not apply to anything, anywhere else, it will only apply to the GIFT city. This law is only for the GIFT city.

Ask any young MBA or Financial or Economic student of a reputed university, be it Harvard or Cambridge, where would you like to go out and work? Their answer would always be, I would like to go out and work in the city. When they say 'city', they really mean New York, London or Singapore and the Minister herself, in her opening remarks, alluded to Singapore and London.

(1555/UB/RPS)

What is common among these places? While they have the biggest financial institutions and banks, they also have a great quality of life, they have a great vibe, and more importantly, they have a liberal environment which holds all of that together. It is not enough to have liberal markets, you rather need liberal cities. What this Government needs to realise is that it is not just enough to create institutions, build tech parks and offer tax rebates. The reason why New York, Singapore and London are what they are today is because of the societal infrastructure. The hon. Finance Minister herself has worked in London and I am absolutely sure she understands what I am talking about. It takes a lot more than regulations and authorities to create a cultural hub and a business hub.

For businesses to thrive, you need to attract global talent. When I say global talent, I do not mean just NRIs or Indians who go, study abroad and come back, but truly non-Indian global talent from the biggest universities. Global talent is definitely not attracted to a nation which exercises curbs on individual freedom, lashes out on dissent and where exists rampant moral policing.

The GIFT City is highly impractical. It ignores such issues as location and steel availability. Realistically speaking, no young financial professional in the world wants to go and work in a dry State. Let us be very clear. Everybody who works in New York, London and Singapore, wants to have a real life; nobody wants to go and work in a dry State, that too in the middle of nowhere, especially

when they have graduated from the top universities in the world and are coming from cosmopolitan and metropolitan backgrounds. Most companies will be willing to pay higher rents and operate out of Bombay where the talent pool exists rather than working out of Gandhinagar.

This GIFT City is also mired in controversy and delays. Grandiose infrastructure targets have failed to materialise. Only 3 million sq. ft. of the 62 million sq. ft. planned development has been completed so far. IL&FS, the company which was given the contract to set up the city, is being investigated for fraud. It has defaulted on its debt. Despite being a public authority and being within the ambit of the RTI Act, the GIFT City is not complying with the Act. The project also does not offer itself to C&AG Audit. In fact, I have read the newspaper reports that the support services like restaurants which have been set up in the GIFT City are struggling because there is not enough business for them.

Madam, I keep mentioning all this because it is important to note that we do not have any other functioning IFSC elsewhere in India so far. This Bill, being considered in the House today, is applicable to only one place. Therefore, it is imperative for this House to understand the viability. The status of this project is also brought to light before going into the intricacies of this Bill.

Now, coming to the Bill itself, while I commend this Government in its noble and well-intentioned, although far-fetched, given the current economic scenario, endeavour to build a global financial hub in India's favourite State. Any efforts to streamline the existing regulatory processes must first be questioned on their spirit. There exists the letter of the law and the spirit of the law. The spirit of the law must be benevolent. The mindset of the institutions should be to facilitate the business, not just to be the regulators of the business. Here, the Bill becomes problematic.

I have just four points to make. In the efforts to get rid of multiple layers of bureaucracy, the creation of the IFSC Authority should not lead to a turf war between the new and the old authorities like RBI, SEBI and IRDA. The old authorities like RBI and SEBI will no longer have the power. What happens to any pending proceedings? The creation of a Central Regulatory Authority seems to be a hobby of this Government which does not realise that the tasks of this nature require due diligence and specialisation. The officials working in SEBI

cannot do the same work as those of RBI. The Government must clarify where the human resources for this unified authority will come from.

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार): माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के और भी वक्ता बोलेंगे, इसलिए आप अब अपनी बात खत्म कीजिए।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): I need a couple of more minutes, Madam. In its effort to become a 'Jack of all trades', the authorities will be reduced to the 'Master of none'.

माननीय सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Madam, I have just three more points. Interestingly, the Bill provides for a Performance Regulatory Committee which is a regulator of a regulator. While it is a noble idea to regulate the regulator, the Bill states that the Committee will consist of, at least, two members of the authority. So, in essence, the authority will be reviewing its own functioning. This brings a question whether the authority will be truly independent or one more centralised body of the Ruling Party is to carry out its political bidding. Financial hubs require transparency and clarity in processes. Singapore transformed its economy with the help of transparent and sound legal framework complementing its economy and political stability. The industry needs certainty on regulations and processes.

(1600/KMR/IND)

Setting up GIFT-City and creating a unified regulator is all good, but where is the feasibility of the policy in the IFSC? How are you going to attract the best financial and banking firms here?

I urge this Government to first focus on GIFT-City, on creating larger social infrastructure conducive to do business. The Government must aim to enable and create social infrastructure that is on par with other similar projects globally and not a throwback to some conservative area. Otherwise, dreams of competing with IFSC Singapore and London would simply be farfetched.

As it is, businesses in India deal with an alphabet soup of RBI, SEBI, IC, ROC and now with CBI and ED. We should not add to this alphabet soup by creating IFSCA as well. Please focus on that.

Thank you.

(ends)

1601 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी कांग्रेस के माननीय सांसद ने बिल के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने एक बात इस बिल के विषय में अपनी पार्टी की तरफ से रखी कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है और वहां दारू नहीं मिलती है, इसलिए यह वहां सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये हमेशा गांधी जी के सिद्धांत पर अपने आपको चलने वाला बताते हैं और ये दारू की बात करते हैं कि गुजरात में दारू न मिलने की वजह से यह सेंटर नहीं चल सकता, यह बहुत ही निंदनीय बात है। मेरे साथी यह भी कह रहे हैं कि ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... कह दिया जाए, यह बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माननीय सांसद कह रहे हैं यह अलग बात है।...(व्यवधान) यह बात हम सेंट्रल हॉल में करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार): निशिकांत जी, आप बैठ जाएं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकार्ड में सिर्फ माननीय सदस्य पी.पी. चौधरी जी की बात ही जाएगी।

...(व्यवधान)...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति : चौधरी साहब, आप चेयर की तरफ देख कर बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Madam, the International Financial Services Centre Authority Bill is in fact a gamechanger for our country. The impact of this Bill is immense. If you question as to how India can become a global financial centre, the complete answer for that can be found in this Bill. I extend my thanks to hon. Finance Minister and hon. Prime Minister for their vision in bringing this important piece of legislation before this august House.

We have adopted the policy of liberalisation in 1991 and after the expiry of so many years we are bringing this Bill before the House. When the Special Economic Zones Act, 2005 was enacted, specific provision was made under Section 18 of that Act that such an International Financial Services Centre Authority can be established in the SEZ for providing tax exemption and many other exemptions. This is the first time that this Bill is before this august House. First time in 2015, a decision was taken by hon. Prime Minister Narendra Modi Ji for bringing in the GIFT-City the International Financial Services facility.

Apart from this, the World Bank said that India is a very bright spot among developing and emerging economies and on its liberalisation it can achieve more. (1605/SNT/ASA)

If we see the economic development of various countries, then these countries have taken the initiative to develop the International Financial Services

Centres in their countries for providing International Financial Services and they have developed the centres. I would like to mention some such countries, namely, New York, London, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong and Singapore. The contribution of these centres in the respective countries is immense with respect to economic growth and job creation. Out of 196 countries in the world, around 80 countries have developed the International Financial Services Centres but in India, it is too late and for years together, nobody has visualised it, except Prime Minister, Shri Narendra Modi. He has visualised that such types of centres are very very essential for the economic growth of the country.

Despite the fact that India is one of the largest countries and also a large user of International Financial Services, we are having an open economy. Prior to 1991, we were having a closed economy. Now, we are having an open economy. At present, India's capital account convertibility is still under-developed and contribution to the global financial market is considered negligible. If we see the global market today, the entire globe is one. It is well connected with technology, and in our country, the use of technology is immense.

So, bringing the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019 is the need of the hour. If this Bill would not have been there, or if I say, in absence of this Bill, the country is losing 50 billion US dollars per year. This is a report of 2015 by the Finance Ministry. By 2025, we will be losing around 120 billion US dollar per year, if this Bill would not have been enacted. So, this Bill, in India, I can say, is a major game changer and it will certainly boost the economy of the country. It will also prove to be a catalyst for employment generation.

Basically, there is a need to develop International Financial Services Centres in India for expansion of the global economy and strategic influence. It is necessary to promote the International Financial Services Centres because the benefits of this Bill and these centres will be certainly going to the country as well as to the stakeholders, that is, to the capital market. Therefore, one of the imperatives to promote International Financial Services arises from India's deepening linkages and inter-dependencies with the rest of the world. It is also necessary because the economy of any country today depends upon the economy of other countries.

India's reliance on foreign funds to finance its current account deficit, and large purchases of International Financial Services from abroad, weakens its position globally, with significantly adverse implications on its economic and

strategic space. It is because we are buying international services, we are taking financial services from abroad.

India is basically a large purchaser of International Financial Services from the rest of the world, and loses significant revenue from the trading of the rupee alone and index derivatives on foreign platforms located outside the country, like we are doing from Singapore, Dubai and London. In trading in rupee derivatives alone – if we count, then it could be more – an IFSC will generate a revenue of Rs.1,500 crore per day, and in one year, it will generate a revenue of Rs.2 lakh crore. That is why I am saying that this Bill is a game changer for the economic development of the country and it will also generate employment.

(1610/GM/RAJ)

As on today, we do not have such a centre on-shore. We are buying everything from outside. It may be equity or derivatives market. So, we are increasingly moving off-shore on account of the development of our economy. Once such a centre is established on shore, the trend will be reversed and it will enable best regulatory practices. Tax, provident and pension fund investment policies and on-shore activities will be increased and that is the need of the hour. So far, they were only talking about the GIFT City. But the decision was taken by the Modi Government in 2015 for establishing the GIFT City in Gandhinagar, Gujarat. In the initial 50 days, banking transactions worth USD 100 million were reported. From the Congress side, it was said that it cannot be a successful model in India, especially in Gujarat, where there is prohibition and *daaru* or *sharab* is not available. I would like to make it clear that India's comparative advantages are so many, not just one. Firstly, India's location is such that we can serve all time zones. Secondly, we are having long-standing cultural and trading ties at global level. At the same time, we have capital talent. What else do we need? We will need excellent infrastructure and best regulatory practices. I request the hon. Minister to kindly see that in this centre we have sufficient capital and excellent infrastructure of world standard. I think sufficient safeguards have been provided in the Bill itself for enabling the best regulatory practices. Apart from this, why should India be preferred? Other countries will prefer India because the cost of real estate and the wage cost in our country is lower in comparison to other places where international financial services centres are available, like Tokyo, New York, Shanghai, Hong Kong and Singapore. Besides, we have professionals; we have the competent persons. There is no dearth of the pool of professionals in our country. We have

technical skills in our country. We also have the finest brains in the field of finance. These things are lacking in those countries where these centres are located.

I would like to say that India is a hinterland economy. Places like Singapore and Dubai lack this facility. For New York, the US is there; for London, the entire Europe is there; for Hong Kong, China is there. We can also develop it. So, it is wrong to say that after this Bill is passed, this centre will not function properly. In fact, it can work very well because we have the hinterland economy. The Finance Ministry has taken an initiative in this direction and we have to compete with Dubai, Singapore and Hong Kong.

We have seen the agony of the brain drain. After the establishment of this centre, the trend will be reversed and we will have brain gain. This will result in re-importing of securities in Indian market. For sustainable growth and development of the country, manufacturing sector alone will not be sufficient. Therefore, the hon. Finance Minister has rightly said that we have to develop ourselves in the international financial services sector and IT and IT-enabled services.

(1615/RSG/VB)

It can boost the economy on this count also and generate employment. So, again I can say at the cost of repetition that this Bill and this provision for establishment of an International Financial Services Centres Authority can prove as a catalyst for these services.

So far, we have been talking about GDP index so many times but at the same time we should not fail to understand that one more index is very important in our country because we are having a very different set up for centuries together, that is the Happiness Index. Along with the GDP index, we have to harmonise the balance; we have to strike a good balance. In the last five years the Narendra Modi Government has initiated schemes. समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं, उन लोगों के लिए योजनाएँ लाई गई हैं, चाहे गैस के चूल्हे की योजना हो, आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो या आयुष्मान भारत योजना के तहत पाँच लाख रुपये के इलाज की योजना हो, जिसके तहत पाँच करोड़ लोगों को कवर करने की योजना हो। हो सकता है कि वर्ष 2015-16 में हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा था, लेकिन जब हम बात करते हैं और आज हैपिनेस इंडेक्स की जो बात आती है, we have to see that along with the GDP index the Happiness Index is also increasing. In the coming years, if such type of Bills are brought, economic growth will be certainly immense as I have stated.

In India, we have seen that so many financial sectors are there like commercial banks, insurance companies, non-banking financial companies, co-

operatives, pension funds and mutual funds. For these financial sectors, the regulators like RBI are dealing with commercial banks, urban co-operative banks, financial institutions, non-banking financial institutions; NABARD is dealing with the regional rural banks and co-operative banks; the National Housing Bank is dealing with the housing finance companies; and the Department of Corporate Affairs is dealing with corporate deposits. So, this is a dual authority. So far as the co-operatives are concerned, their management is with the State or with the Central Government depending upon the co-operative society whether they are multi-state or state co-operative societies. So far as the banking part is concerned, that is with the regulator. So, there is a need to remove this dichotomy. Apart from this, there is SEBI dealing with capital market and mutual funds; IRDA dealing with insurance; PFRDA dealing with pension funds. So, there are different regulators for different sectors. This Bill is going to unify all these sectors and whatever powers are being exercised by those regulators will be exercised by this particular Authority. So, it would be very easy and convenient and enhance the ease of doing business.

We see that financial regulation based on the product is covered by different Acts. Various Acts and enactments are there. Under all these Acts and enactments, each product is separately regulated by the institutions. There are so many institutes. We see in the Second Schedule the amendment has been done with respect to a particular provision giving power and authorising the Authority to exercise the power with respect to that Act. Earlier the work allocation with respect to various regulators and various sectors was not so well defined. Therefore, sometimes, there was overlapping; sometimes, disputes arose. It created a lot of a problem for a particular sector by a particular regulator. So, there were problems with multiple regulators in India. There were different regulatory requirements posing so many challenges. ...(*Interruptions*) I am concluding in just a minute. There was a regulatory gap. For instance, we have seen the ponzi schemes. On account of the regulatory gaps in various sectors and various regulators, they had taken advantage of the situation and people had been cheated. The ponzi schemes were not regulated by any of the existing agencies. So, the overlap of the regulators and conflict on account of multiple regulators was always there.

(1620/RK/SPS)

So far as the legislative structure of the financial sector in India is concerned, as on today we have 60 Acts and multiple rules and regulations in force since 1950.

The purpose, the spirit and the motto of these legislation was to ban certain financial activities. The RBI Act was enacted way back in 1934. The Insurance Act was enacted in 1938. The SEBI Act was enacted in 1956. Now, there is a change in the financial landscape. At that time, the financial landscape was different. ATM or the credit card was not there at that time....(*Interruptions*) Madam, do not worry. You can deduct the time taken by me out of the total time allotted to my Party.

At that time, we did not have Internet banking, investment advisory services, private banking and so many other modern technologies. So, these enactments are quite old. FDI was facing tremendous hardship at that time. This Bill will provide the ease of doing business.

So far as the reforms in financial sector are concerned, today we are a globalised world and there is a growing interconnection between various countries....(*Interruptions*) I am just concluding, Madam.

If you see the composition of the Authority; the Chairperson to be appointed by the Central Government, one member each to be nominated by RBI, SEBI, the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Pension Fund Regulatory and Development Authority, and two Members from amongst the officials of the Ministry dealing with Finance are to be nominated by the Central Government. So, the composition of the Authority is outstanding and it will function extraordinarily.

Apart from the Authority, the Performance Review Committee has also been provided in the Bill. The Performance Review Committee will adjudge the working of the Authority and from time to time report to the Government of India with respect to its functioning. Tax exemption has also been provided.

I once again support this Bill. Thank you.

(ends)

1623 hours

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson, Madam, I am so happy and privileged to debut and deliver my maiden speech in this august House.

I have come here after being elected from Tamil Nadu State, the home of poets, visionaries and self-respect, revolutionary and social movements. I represent Vellore Parliament constituency, which is the land of heritage, culture and valour. Vellore showcased the first ever large-scale violent Indian sepoymutiny against the East India Company. The historians call it the land that debuted its first freedom struggle for India's Independence. I am proud of my town, Madam.

I also take a lot of pride in mentioning that I hail from the DMK Party, founded with and by the principles of Thanthai Periyar and Peraringar Anna, the revolutionaries who changed the face of politics in Tamil Nadu and even across India.

I would first like to thank the people of Vellore for their mandate and their longstanding belief in self-respect and Dravidian principles that I hold close to my heart. I am thankful, grateful and indebted for my life to the voters of Vellore parliamentary constituency. All of us, if not always, must have felt this destiny and the high sense of responsibility for which we are being called to be here in this House.

Madam, five years back my great legendary Leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, the former Chief Minister of Tamil Nadu, wanted me to be elected to this august House. His wish was made true and possible only by our leader, a patriot with a philosophical outlook, a politician with constructive gifts, an able administrator with the streak of evangelism, a reformer with a crusading zeal, a statesman and a strategist of high order.

(1625/RC/MM)

None other than our DMK Party Leader, Sri Muthuvel Karunanidhi Stalin fondly called by the masses as Thalapathy M.K. Stalin is one of the most powerful influences in the contemporary politics. He, along with me, gifted to this House the finest parliamentarians from Tamil Nadu. They are men of calibre, vision, knowledge and character that it lacked in the past five years.

I would be cursed if I do not thank my mother, Shrimati Santha Kumari and my mentor, guide and philosopher, my dad, Shri Duraimurugan, who is the Deputy Leader of Opposition in Tamil Nadu Assembly, treasurer of DMK Party, and 11 time MLA from the same Katpadi constituency. My dad is one of the intellects with ability to accurately assess situations and resolve them within matchless time and now observing his son from the gallery.

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Hon. Member, you speak on the Bill.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Madam, this is my maiden speech. I am coming to the point.

My heartfelt thanks and gratitude to my parliamentary colleagues, Sri T.R. Balu, Shrimati Kanimozhi Ji, Sri Raja, Sri Jagathrakshakan, Sri Dayanidhi Maran and my youth leader, Sri Udhyanidhi Stalin.

Let me now try to focus on the International Financial Services Centres Authority Bill. In continuation of the discussion on the Bill, I would like to state that nobody has the monopoly of wisdom or knowledge. In spite of having the most creative entrepreneurs, the most dynamic business leaders and the sharpest financial brains in the world, we are still affected by three basic problems – poverty, unemployment and foreign exchange trade deficit.

One's patriotism is questioned when actions of the State are criticised. So I have to be careful and thoughtful in my statements. The Bill has challenges which it has to overcome. Today, India's economy is facing a lot of challenges. The GDP growth rate is declining. The exports are on a downward trend. The unemployment rate is high. The consumer spending is low. The capacity utilisation is falling. The investment figures tell us that the business confidence is down. The Indian economy is also leaking out its cash reserves by the Liberalised Remittance Scheme. Its percentage is also growing.

The Centre for Sustainable Employment of Azim Premji University tells us that 9 million jobs or above have been lost in the last six years.

Madam, if an economy has to boom and if a country has to shine, you definitely need foreign investment. The trade has to be smoothed out but the country is now facing big challenges and because of that the investors are afraid to come to this country. There is a fear in the Government as well as in the economy whether this economy is going to stand strong or it is going to break.

The hon. Minister has presented this Bill before this august House for passing because the International Financial Services Centre Authority has to be established in the GIFT city but that GIFT city is already facing its failures – the failures of mobility. Why do you have to put all your eggs in one basket kept in Gandhi Nagar? You always have Mumbai which is called the financial hub. You have Kolkata and also Chennai which is supposed to be an automobile and foreign exchange generating State.

(1630/SNB/SJN)

But the Government is clearly and politely shifting all its eggs to the North-West part of the country. The State of Tamil Nadu is also a big hub and the State should have been considered for setting up of this Centre. It is because the Southern States always have ruled the financial sector. Our previous ruler, Kalaingar Karunanidhi had put in a lot of efforts to establish Special Economic Zones in the State which populated the automobile industry, the software industry as well as the semi-conductor industry. A lot of manufacturing is happening in the South. The State of Andhra Pradesh has got its automobile industry; the State of Karnataka has Infosys and software technology parks, but even then, why is this Centre being set up in Gandhinagar in Gujarat? Earlier, when the GIFT city was established almost 9000 jobs were promised but today the direct and indirect jobs both are not interesting. As has been mentioned by the hon. Lady Member, a lot of institutions had to be moved. Now, we are talking about Remote Management. When all these centres were moved and today when you talk to the people there, when you talk to the investors there, when you talk to the banks which have been moved there, they are not finding it interesting. They say they want to work in an area, in a State and a city where it is already populated and has a booming economy. But the Government is moving it out to a remote area.

An investment target of Rs. 78000 crore had been set for the Special Economic Zone. The city has attracted only Rs. 9800 crore. How will the new Bill attract more investors when there is an overall economic slump? The main partner of GIFT is in huge financial trouble and its future is uncertain, despite huge efforts by this Government to provide needless tax breaks and regulatory concessions. The GIFT's Chief Executive has chosen to quit. As per newspaper reports, only one shop in the city's market is open in the region. From what we

have learnt, GIFT today survives just because of the influence of this Government and nothing else.

Madam, now, I am going to talk about the proposed Authority. The provisions in Clause 21 of Chapter VIII makes the Authority bound to the directions and policies the Central Government might dictate. Secondly, the complete powers of the Authority are not defined and there is a provision provided to the State to “make the rules for implementation of the Act” by notification, making accountability meaningless.

There is also a provision for constitution of a Performance Review Committee under Clause 17 of this Bill which will consist of two members of the same Authority nominated by the Centre to review the functioning of the same Authority. The fact that the members of the Authority itself are in-charge of reviewing the working of the Authority is a matter of concern and such a thing could lead to biased decisions.

One more reason for my scepticism on this version of the Bill is that it seems to give away powers which are controlled by independent authorities to a Centre-controlled one. Though I support the need for establishment of such an Authority that creates special provisions for the Financial Services Centre, I also firmly believe that it should be independent and be able to make its own policy decisions.

Madam, I want to make this very clear that I do sympathise with the necessity of having such an IFSC Authority. In the current political scenario, I am reminded of the time the founder of our Party, Peraringar C N Annadurai stood in the other House and said and I quote:

“Correct us if we are erroneous. Convince us if you have got solid facts. Convert us to your point of view, instead of compelling. Compulsion, especially through law – I need not say it in a House where there are so many luminaries from the legal profession – it is the worst form of argument.”

(1635/RU/GG)

Sir, I am not trying to disrespect the mandate this Government has been gifted with. I just want to emphasise the importance of this Opposition to debate the feasibility and accountability of this IFSC and its authority to be constituted.

We are here representing the common man and more importantly, the youth of this nation who are now raising valid questions to transform India into a different India, an India that is compassionate and welcoming, an India that does not lynch its minorities, an India that wants to keep religion out of politics, an India that respects dissent, an India that believes in freedom of expression, an India that questions the people in power and more importantly, an India that works for all of us, not just the rich or the privileged. Our nation is again a nation of diversities in all respects. If we are able to echo that in all our decisions, then we will not get lost in the by-lanes trying to emphasise one way of life or one language or one religion. Then we will never lose our way.

Various factors may be there which go to make foreign investments in India very attractive. First and foremost, when they invest in India, they invest in democracy. Let us protect our democracy, democracy of speech, democracy to do business and democracy to express our views and thoughts and democracy to live happily in this country. When this Government is attempting to trample that democracy, then entire economy will be questioned and therefore, I urge upon this Government and Finance Minister to please release this country out of fear which the investors are facing now. ...(*Interruptions*)

Madam, today is the birth anniversary of our great Tamil poet, Barathiyar. I am so happy and privileged to give my debut speech here and also talk on a Bill presented by Shrimati Nirmala Sitaraman. Being from Tamil Nadu, she is the first woman Finance Minister. I congratulate her and salute her and I am so happy that my first speech in the House has been on her Bill. I know that Madam will support the State of Tamil Nadu which will receive a lot of her attention. We need a lot of support from you, Madam.

(ends)

1638 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I shall be very brief. The rest of my time may be given to Shrimati Mahua Moitra who will be speaking from my Party.

There is nothing to oppose in the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019. The only point is, this Bill is overdue. In 2015, the then Finance Minister, Shri Arun Jaitley announced the setting up of a GIFT City in Gujarat. In February 2019, the Government brought a Bill in Rajya Sabha. It has taken four years from late Shri Arun Jaitley's announcement – may his soul rest in peace – to even bring this Bill to this House.

Shri Karti Chidambaram spoke very well. He said that this Bill is entirely for one GIFT City because there are no other International Financial Services Centres in India at present. You may know that an expert panel headed by former World Bank economist, Percy Mistry submitted a Report on making Mumbai an International Financial Centre in 2007. Bandra Kurla Complex would have been ideal for setting up such an International Financial Institution.

(1640/KSP/KN)

The decision to set up this institution in Gujarat was entirely a political decision. Now I wish the Finance Minister success in her effort. She is going through a bad time, since the economy is in bad shape, with a rate of growth at 4.5 per cent, unemployment at 8.5 per cent, inflation making a come back etc., and she is in difficulty. So, it would be good if she can revive part of the economy through this Bill.

But the problem is, the GIFT City, the dream project of the Prime Minister, who is from Gujarat and, maybe the Home Minister, who is also from Gujarat, is in dire trouble. You may know that the GIFT City's future hangs in balance, because the new board of ILFS, which is a non-banking financial company that collapsed, admitted that many of ILFS group companies involved in the project, including the joint venture partner, holding company, IL & FS will not be able to pay off their debt to their financial creditors. So, the basic financial infrastructure of the GIFT City is collapsing.

The GIFT City was a 50:50 joint venture between IL & FS and the State Government-owned Gujarat Urban Development Company. So, maybe the Finance Minister would assure the House that the GIFT City's finances will not collapse. There have been problems because one of the primary objectives behind setting up of the GIFT City was to bring offshore trades based on Indian stocks

and currencies to the trading platform in the Indian IFSC. The Centre has been very worried about migration of volumes from the NIFTY's futures to the Singapore Stock Exchange. They currently account for 30 to 40 per cent of the daily turnover in NIFTY.

Madam, the sad thing is that we are a country of 130 crore people. Our Prime Minister talks of making it a 5 trillion-dollar economy. But puny, little places like Singapore, where Mrs. Sule lived for a long time, have become international trading hubs. London and New York were there and now Dubai and Shanghai are coming up, but in 70 years of Independence, we have not been able to make a trading hub in this country.

So, I want the Finance Minister to plug all the loopholes that are present in the GIFT City. The question of setting up another International Financial Services Centre is far-fetched. You will take a decision and then you will take 10 years to set up an IFSC. Now, our hope rests on the Gujarat GIFT City. That is an unfortunate part that you have to bring this Bill for this purpose. I will not go into the details of the Bill. A new authority will be set up, it will have a Chairman, two full-time Members and it will do away with all the regulators. SEBI, RBI, IRDA and PFRDA will all come under one roof. That will be an advantage and that should be done in any case. It will help in sustaining local economy and it will also do fund raising services, asset management, wealth management, global tax management, global and regional corporate treasury management, risk management operations, merger and acquisition activities. All these are essential services and for that we need a strategic location and a good quality of life.

(1645/SRG/CS)

What did Singapore do? If you want to bring the best, bring the best brains of the financial world to Gujarat to create an enabling environment. So, while I support the Finance Minister in her effort to create an International Financial Services Centre in India to start with Gandhinagar on the banks of Sabarmati river in Gujarat and to continue with other places in the country, I think that the future of GIFT city does not look all that bright. So, I shall request the Finance Minister Madam to remove the clouds of doubt and suspicion and create an enabling environment for an International Financial Services Centre to be set up and work in India.

With these words, I conclude.

(ends)

1646 hours

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Madam, on behalf of my party, the YSRCP, I rise to support the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019 with no reservations. For when it comes to making a mark in the global financial context, effective governance and regulatory mechanisms are pre-requisites of a sound indigenous system.

We have opened up to the forces of globalization almost 28 years ago. Until 2015, Indian corporate entities continued to seek international financial services and transactions in offshore financial centres. However, with the arrival of an IFSC in Gujarat, we have emerged as a progressively competitive financial centre. In just three years after its inception, the IFSC at GIFT city entered the main series of the Global Financial Centres Index and ranked 77 among 100 global financial centres. While the powers and functions of the RBI, SEBI and IRDA under respective Acts shall still be exercised and performed by this Authority, I hope its very existence as a unified entity will make cooperation, coordination and compliance easier.

While we as legislators and Governments are occupied with setting standards for international financial services, products and institutions, one challenge we often overlook is to effectively impose them. I hope we eliminate ambiguities to avoid prolonged court battles, like we have seen in the recent case of TRAI and telecom companies. On a side note, I have to commend the Government in safeguarding public interest in this case and extending support to the companies which were in danger of bankruptcy despite their size. I hope the IFSC Authority Bill will see no such legal ambiguities compromising our credibility both domestically and internationally.

India is hungry for the kind of capital whose cost is at par with the rest of the world. While Indians need access to internationally diversified investments, foreign investors need smooth access to the growing domestic economy. I also think a strong IFSC is backed by a stable local economy and developed infrastructure. We need to grow as an economy to match our aspiring population and develop our infrastructure exponentially to even come close to standards in the West. Even as on today, we are unable to provide basic necessities and good quality of life to our people, be it drinking water, healthcare services, education, sanitation, transportation, housing etc. My own Parliamentary constituency, Eluru, has several issues concerning infrastructure. Bridges which are almost 70 years old, several small, medium and large irrigation projects which could be the lifeline for large areas are still pending. I must mention that a 500 kms freight canal was proposed by the

Central Government between Kakinada and Puducherry almost five years ago, but there is no sign of progress due to lack of funds, forget about cost effective funds.

Meanwhile, we see nations like Singapore, Dubai and China mitigate international capital to achieve tremendous growth while our own capital account convertibility is still underdeveloped. We want to compete with China, yet we are not prepared as we lack a manufacturing base to deliver quality or quantity. A lot of us believe that the trade standoff between Donald Trump and China will escalate and automatically turn into an advantage for India.

(1650/KKD/RV)

There is a clear and present danger that if China has to devalue their currency because of the standoff, our exports will lose out on our own trade, forget gaining theirs because of the cost advantage China will gain. I hope, we equip ourselves to fight this uncertainty and take standalone measures so that our exporters get access to cheaper capital, which can come through these IFSCs.

I would also like the Government to create a stronger atmosphere of confidence and ease of doing business in India. India stands at the 63rd position among 190 countries in the 'World Bank's Ease of Doing Business Report, 2020.' I hope, we target to move up by several notches. The promotion of International Financial Services Business must go hand in hand with regulations. For this, I would suggest appointing a member who is an expert at it and who can closely watch and monitor the health and progress of the industry in our country. That member could be chosen as one of the two, to be appointed on the recommendation of a Selection Committee as provided for in the Bill.

I must also point out that since IFSCs are said to foster job creation and kick-off economic development, I would have ideally suggested the setting up of a higher number of IFSCs at strategic locations. The Bill states that IFSCs are set up under the SEZs alone. It might be a practical move to do so at a time as it can serve as a testing ground for financial sector reforms before they are rolled out in the entire nation. I do hope, Andhra Pradesh stands next in line for the next centre considering the opportunity available between the new State and the new administration led by our next generation Chief Minister, hon. Shri Jagan Mohan Reddy-garu, who believes in transparency and clean governance.

Madam, all in all, my concluding comments would be that the initiative to regulate the IFSCs should, by no means, slow down business interests. I hope, we aggressively pursue growth potential of International Financial Services to help kick-off our efforts in meeting India's dire need for development.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

1652 hours

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019

I would like to begin my speech by extending my support to this Bill, which has been brought before this House by the hon. Finance Minister.

India has the potential, both in terms of human capital and a globally renowned IT industry, to set up International Financial Services Centres that can compete successfully in this market space. Additionally, IFSCs would certainly aid in improving the current economic climate, which is persisting in the country, by attracting inflow of financial resources into India. It would also increase the demand for INR in the international market along with new business opportunities of providing financial services to the global market.

Madam, the intention of the Bill was to set up a single authority that would regulate the transactions of the IFSCs.

Though I support the need to set up a single regulatory body in contrast to multiple regulators, but I disagree with the Government's view of the Authority's role. Here, Clause 21(2) of the Bill states:

"The decision of the Central Government, whether a question is one of the policy of not, shall be final. "

This is an extremely autocratic provision, Madam Chairperson. So, I would request the Government to rescind this provision.

The Bill already provides for the Authority to have four members appointed by the Central Government. It is providing an avenue to the Central Government that their views are put forward. Here, I fail to understand the reason as to why the Government still feels the need to have such a dictatorial provision.

Similarly, Clause 17 of the Bill relates to Performance Review Committee which would consist of, at least, two Members from the Authority. In my view, it is a conflict of interest. Any review of performance must be carried out by an independent third party agency.

Madam, SEBI, RBI and IRDA are independent regulatory agencies. Thus, any authority that would supersede or takeover their regulatory powers, must also be an independent agency in order to ensure that the changing political landscape does not hurt the economic interests of the country. Additionally, the

presence of an independent regulatory agency would ensure stability, which is an essential component for attracting foreign capital.

(1655/RP/MY)

Thereby, any attempt made towards curbing the independence of financial regulatory bodies bears the risk of adversely affecting the financial interest of the country.

Madam, I would also like to take this opportunity to propose to the Minister to set up an IFSC in Mumbai. The city enjoys all the necessary requirements to set up an international financial centre and home to the Bombay and the National Stock Exchanges. Additionally, Mumbai also boasts of structuring 90 per cent of the country's merchant banking transactions and 80 per cent of the country's mutual fund registrations. And thus, it has all financial infrastructure necessary for an IFSC.

Madam, the Government set up GIFT city in Gujarat as the country's first IFSC, however, the said IFSC has not been able to take off in the manner that the Government assumed it would. Out of 67 million square feet of land allocated for the planned development of the centre, only 3 million square feet has been developed so far. Additionally, the State lacks the necessary skill-set for an IFSC whereas Mumbai is the Financial Capital of the country and has been navigating through the financial waters for decades. Thus, it has both the skill-set and the capacity to have a successful IFSC. I would like to request the hon Minister to take note of this and do everything necessary to set up an IFSC in Mumbai which could give the economy its much-needed boost.

To conclude, I would like to state that I agree with the hon. Minister about for the need for setting up of such an authority. However, I would also like to request the hon. Minister to take my suggestions into consideration in order to ensure a stable future for our country's financial market. Thank you.

(ends)

1657 hours

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Madam, an IFSC enables bringing back the financial services and transactions that are currently carried out in offshore financial centres by Indian corporate entities and overseas branches or subsidiaries of financial institutions to India by offering business and regulatory environment that is comparable of other leading international financial centres in the world like London and Singapore.

It would provide Indian corporates easier access to global financial markets. IFSC would also complement and promote further development of financial markets in India.

Currently, the banking, capital markets and insurance sectors in IFSC are regulated by multiple regulators like RBI, SEBI and IRDAI. The dynamic nature of business in the IFSCs necessitates a high degree of inter-regulatory coordination.

It also requires regular clarifications and frequent amendments in the existing regulations governing financial activities in IFSCs. The development of financial services and products in IFSCs would require focussed and dedicated regulatory interventions.

Hence, there is a need for having a unified financial regulator for IFSCs in India to provide world-class regulatory environment to financial market participants. Further, this would also be essential from an 'ease of doing business' perspective.

The unified authority would also provide the much-needed impetus to further development of IFSC in India in-sync with the global best practices.

The establishment of a unified financial regulator for IFSCs will result in providing world-class regulatory environment to market participants from an 'ease of doing business' perspective.

This will provide a stimulus for further development of IFSCs in India and enable bringing back of financial services and transactions that are currently carried out in offshore financial centres of India.

This would also generate significant employment in the IFSCs in particular as well as financial sector in India as a whole.

I am requesting the hon. Finance Minister to establish an IFSC centre in South India and Hyderabad is a suitable and centrally located place for this. It has also a good infrastructure too.

Thank you, Madam.

(ends)

(1700/CP/RCP)

1700 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, सरकार इस बिल के माध्यम से, देश के विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससी) के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमन करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान कर रही है। यह उनके कानूनों की जटिलता को कम करेगा और भारत में वित्तीय बाजार में भागीदारों को वैश्विक स्तर का विनियामक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत वित्तीय विनियामक प्राधिकरण के रूप में उपलब्ध होगा।

1701 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

इससे भारतीय निगमित उपक्रमों की वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी। आईएफएससी से भारत में वित्तीय बाजार के विकास को और बल मिलेगा, विदेशी मुद्रा में लेन-देन और सरल हो जाएगा। रोजगार सृजन में अहम वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

महोदय, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बैंकिंग, पूंजी बाजार का नियमन, रिजर्व बैंक, सेबी, इरडा जैसी विभिन्न एजेंसियां कार्य कर रही हैं। इससे भी छुटकारा मिलेगा। एकल प्राधिकरण कार्य करेगा, जिससे ईज आफ डूइंग बिजनेस की सार्थकता सिद्ध होगी। प्राधिकरण विश्वस्तरीय नियमन का माहौल उपलब्ध कराएगा।

महोदय, प्रवासी भारतीय, विदेशी निवेशकों, संस्थागत निवेशकों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा के तहत मात्र भारतीय निवासी आईएफएससी में भाग लेने के हकदार होंगे। कुल मिलाकर वित्तीय बाजार को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। इससे वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काफी लाभ मिलेगा एवं अधिक रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है।

महोदय, काफी छूट देने से धोखाधड़ी की भी आशंका बढ़ जाती है। पहले भी देश अनेक वित्तीय घोटालों को देख चुका है। अतः मेरा सुझाव है कि निगरानी तंत्र काफी सुदृढ़ हो और किसी भी धोखाधड़ी में कड़े दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। एक बार जो धोखाधड़ी में पकड़े जाएं, उनके लिए लाइफटाइम बैन का प्रावधान हो। फास्ट ट्रैक निर्णय लेने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

1703 hours

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Chairman, Sir for calling upon me to participate in the debate on the IFSC Authority that is sought to be set up by the Government. There are two aspects to this Bill being brought in by the Finance Minister. One is with regard to the concept of the IFSC, of course, the very concept, the very essence of it. The second is relating to the provisions of the Bill itself.

I think, the concept of the IFSC has got off on a false start, if I may say so with respect. The idea is to locate it in the Gandhinagar GIFT city ignoring the long-pending application of the Bandra Kurla Complex. BKC has had a very long waiting period. When they have applied for an IFSC there, that has been ignored by the Government for reasons best known to the Government. They have, instead, sought to locate it in the GIFT city which has had a completely disastrous beginning because there is an aborted partner there. We have no idea who is going to take over from the IL&FS; we have no idea how the Government plans. It is because IL&FS was an equal partner with the Gujarat Urban Development Company Ltd. With the IL&FS now facing multitudes of litigations and multitudes of prosecutions in a complete state of shambles, who is going to take over this 50 per cent partnership role is anybody's guess. I think the stunted manner in which the GIFT city has tried to limp along has been mentioned by other friends of mine, colleagues of mine. There is 62 million square feet plan. So far, only three million square feet is built up which clearly shows that this is not looking like it is going to take off in a hurry.

(1705/MMN/NK)

I am constrained to say this on the floor of the House, but, you know, to set up an international agency of this nature in a place which is dedicated to prohibition, for instance, I think, is not in consonance with the kind of ambiance and the kind of international business practices that flourish all over the world. Even in places like Dubai, for instance, which are traditionally Islamic countries, there are very liberal laws with regard to alcohol distribution and consumption. Therefore, I believe that will be one of the reasons why this will be stunted. A lot of people prefer to choose cosmopolitan Mumbai rather than Gujarat or Gandhinagar which, they sense, is, perhaps, a little more provincial than the cosmopolitanism of Mumbai. Therefore, I am not sure that the very substratum

of the IFSC, which has been sought to be located in Gandhinagar, has got a rational and a logical basis to it. Therefore, now from thereon, how the Government wishes to first ensure that this flourishes in Gandhinagar by attracting talent and by attracting international investment is something for the Government to do. It has to fast-track it. It has to also ensure that there is an absolutely targeted and very focussed, I think, attempt at harnessing and garnering both talent as well as resources to this place. I think you have to give them a massive slew of incentives in order for people to come there.

I think one of the things that the Government ought to think about is to liberalise this entire process and fast-track applications. Now that there is an authority, which is being sought to be brought in, use the authority as a good regulator to fast-track applications. Let us have many more of these centres. These are centres of excellence. These are centres of magnets which attract both talent and investments. Therefore, this should be fast-tracked.

Plus, I think we should go international. For instance, Dubai has gone international. Dubai has set up their authority in London as well. Therefore, there is no reason why we cannot go to Singapore or go to Dubai or go to London and try and internationalise our operations which I think will certainly go a long way in integration of these international markets with Indian markets.

As far as the Act itself is concerned, I have just a couple of very quick points. First, Section 6 is saying that no member shall hold office without prior approval of the Central Government for a period of two years. I am very sorry to say that this Government has been very, very liberal in giving a 'go-bye' to this very restrictive clause. In fact, persons of very high stature in very high positions, including Constitutional authorities—I do not want to mention their names on the floor of the House and I think we all know who they are—have chosen to take immediate permission from the Government, which has been granted very, very liberally to join very large corporations in India. It does not give out a good signal. Indeed, I think the Government should have been much more sparing in giving these liberal permissions that it has been giving. Therefore, when you say that except with the previous approval of the Central Government, it is an approval which is virtually given in the breach rather than in consonance. Therefore, I do not know if this is something that is working in India.

The Performance Review Committee, I think, is again a laudatory Committee but again it is so completely inhouse that I do not know whether an independent audit can take place when two of your own officers are going to do an audit. The audit must be conducted by an outside agency rather than your internal agency. I do not know whether the Right to Information Act is going to apply to this. Maybe, the Minister can, in her reply, tell us whether the Right to Information Act will apply to this or not.

Very importantly, dispute resolution in India is, of course, critical and people do not want to come to these places because they find that they get entangled and embroiled in all kinds of legal disputes here, which have no easy resolution. Therefore, perhaps, the Government must think of following the Dubai International Financial Centre which has a dedicated dispute resolution authority comprising of four divisions within their system itself. It has DIFC courts. These are separate dedicated courts. There is the DIFC-LCIA Arbitration Centre. There is an Academy of Law and there is DIFC Wills and Probate Registry.

(1710/VR/SK)

Then, it becomes like an independent city in itself within its own law. I think it is very important if this dispute resolution at some point must be brought within the ambit of it.

With these words, I would want to wish the Government well, I would want to wish the Finance Minister well in bringing this authority in place. Bringing in one authority rather than a multitude and plethora of authorities is good because I believe that agencies like the RBI etc. have not been terribly successful in their monitoring capacities. Therefore, let us see what this authority does now.

I can only wish the Government well in its endeavour. But the Government must bear in mind that there are many pitfalls it has already suffered and many more pitfalls awaited unless there is a massive wake up call, the Government chooses to take.

Thank you very much, hon. Chairperson.

(ends)

1710 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, हालांकि यह बिल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स को परिभाषित करता है और उनके कार्यों को नियमित करता है जो कि एक सार्थक पहल है, इस बिल में केंद्र सरकार ने आईएफएससी के संचालन और कार्यान्वयन के अत्यधिक अधिकारों को अपनी मुट्टी में बांध कर रखा है। यह प्रथा आज कल के वित्त माहौल को देखकर, खास तौर से सरकार के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के नारे के बिल्कुल विपरीत है।

महोदय, इस बिल में केंद्र सरकार ने एक रैगुलेटरी बॉडी बनाई है, रैगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की है, जिसका काम आईएफएससी के संचालन और क्रियान्वयन की देखरेख करना है। मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ तथ्यों को उजागर करना चाहता हूं, इस बिल के तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को किसी भी तरीके से, मनमाने तरीके से परिभाषित कर सकती है और कभी भी परिभाषा को बदल सकती हैं।

इस बिल के तहत केंद्र सरकार आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी आईएफएससी के रैगुलेटरी फ्रेमवर्क से कभी भी निकालकर बाहर कर सकती है। इस बिल के तहत केंद्र सरकार मनचाहे तरीके से इस रैगुलेटरी अथॉरिटी को कभी भी भंग कर सकती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आईएफएससी को चलाने के लिए समूची शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथों में केंद्रित हैं।

मान्यवर, मैं उसी कड़ी में बताना चाहता हूं कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है कि उसकी वित्त संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हों, मजबूत हों। ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं सरकार के कार्यकाल के बाद भी चलती रहती हैं, अगर इनके कानूनों में सरकार का इस तरह से हस्तक्षेप रहेगा तो जायज बात है कि निवेशकों के मन में संदेह पैदा होगा और विश्वास नहीं जगेगा।

यदि केंद्र सरकार इन संस्थाओं के नियमों और कानूनों को मनमाने तरीके से कभी भी बदलने की शक्तियां अपने में समाहित रखेगी तो यह सत्य है कि पूरी तरह से निवेशक विश्वास नहीं करेंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा।

हमारी सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों में भय रहता है और वह है आर्थिक नीतियों में अस्थिरता। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कल तक सैमसंग टीवी की चैन्नई में एक फैक्ट्री थी। अचानक टीवी के कुछ जरूरी पार्ट्स पर दस परसेंट टीडीएस लागू हुआ और सैमसंग ने 'मेक इन इंडिया' का नारा छोड़कर 'मेक इन वियतनाम' का जाप शुरू कर दिया। वह कंपनी चली गई, सैमसंग ने देश ही छोड़ दिया, टीवी बनाना ही छोड़ दिया और उसके साथ लोगों की नौकरियां भी चली गईं। यह सब हमारी आर्थिक नीतियों की अस्थिरताओं की वजह से हो रहा है।

जब जीएसटी का खराब क्रियान्वयन हुआ तो हजारों-लाखों लोगों की नौकरियां सफा चट्ट हो गईं। कल तक जो सब चंगा था, अचानक तुगलकी फरमान आया कि 500 और 1000 रुपये के नोट

पूरी तरह से खारिज हो गए हैं। सैंकड़ों लोगों ने लाइनों में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जीडीपी की टांग टांग फिस्स हो गई, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

यहां आदरणीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। वह बहुत ही शिक्षित हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जिम्मा उन पर है। मैं पुनः उनको एहसास दिलाना चाहता हूं और अपनी छोटी सी पोजीशन से जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे बुनियादी चीज जिस पर निवेशकों का विश्वास होता है, वह है आर्थिक नीतियों में पूरी तरह से स्थिरता।

(1715/MK/SAN)

जब तक विश्वास कायम नहीं रहेगा, ये सबसे बुनियादी चीज है, तब तक यहां पर विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। इसलिए, हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर अडिग रहने की जरूरत है। वर्ष 2014 से इस सरकार ने, खास तौर से वित्त मंत्रालय ने जिस तरह से निवेशकों के मन के अंदर भय और उसके साथ-साथ अविश्वास पैदा किया है, पूरी तरह से, जो हमारी अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, यह उसके लिए जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, मैं अंत में कन्क्लूड करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी इस बिल पर वापस विचार करेंगी और यह जरूर सोचेंगी कि हम सरकार की इतनी ज्यादा शक्तियों को एक ही संस्था में समाहित न करें और एक अलग रेगुलेटरी बॉडी, जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी नीतियां स्थायी हों, उसकी स्थापना करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1716 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here obviously in support of the Bill, but there are a few points which I would like to highlight to the hon. Finance Minister.

Actually, out of the last four weeks of Session, unfortunately I was not here for one week, but I have been here for three weeks. One Minister who has almost led this entire Session has been the hon. Finance Minister and her MoS. I would like to compliment this team because they have been, I think, the champions and the maximum Bills that have been passed, I think, whether we liked or disliked, we agreed or disagreed, were championed by the Finance Minister. So, I appreciate the efforts that they have made.

I do understand, which I said earlier also in my speeches, that this is not, I am sure, the position she wanted to be in, but she is actually sitting on a very powerful seat, but it is full of thorns unfortunately. She has been put into that role and she has shown so much responsibility in a very difficult situation of the economy. So, I do understand that she faces a lot of challenges while navigating through this very difficult, turbulent times that India is going through economically.

It was strange that Shri P.P. Chaudhary, unfortunately he is not here, from the Treasury side said that the happiness index has gone up. I do not know where he is getting data from, but I would definitely like to put it in record that the happiness index of this country has gone down and the hunger index has gone up. I think that is what we really need to consider. ...(*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is one point up.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): That is not very laudable.

Anyway, the hon. Finance Minister, in her opening remarks, made very serious points on which I would like to ask clarifications from her. She talked about PSE, banking, brokers, insurance and IT sectors taking advantage of the tax benefits. Now, the legal jurisdiction of all these investments is in India, but the entire physical infrastructure is out of the country because they invest globally. Moneys are not necessarily always parked here and the benefits are nurtured. She also said that due to ITeS, about 10,000 jobs were created because of the back-office work which is wonderful. I will give you an example

of Rajiv Gandhi Infotech Park which is in Maharashtra and it happens to be in my constituency. It is a much smaller infrastructure. It is put up by people who invest. Over 3.5 lakh of jobs directly or indirectly – she is aware of all this and I do not have to explain that to her – are created. So, for the kind of monetary investment that we made, what is the cost-benefit analysis of the amount of investment that we have put in and the return that we are getting. Ten thousand jobs at a go sound exceptionally impressive given the situation of unemployment in India today, but really for the amount of land and investment, it is actually peanuts. Rajiv Gandhi Infotech Park as a concept of an IT hub *versus* international FSC is way different. I know that the concept is completely different. The IFSC is a concept different from that of IT, but if you are only going to look only for job opportunities, is IFSC an option or IT Infotech Parks is a much better option? We do give tax benefits there also. Here, the kind of tax benefits that are given are exceptionally high.

I would like to flag a point which is about Mumbai since I come from that city. A lot of people have referred to the HPSC, the high-powered committee. There are quick points that I would like to make. Why did they not consider Mumbai? Had it happened in Gandhinagar, I would have no objection. If another State is doing well, we are happy as eventually, we are a one country. If one benefits, we all benefit because of each other. When Mumbai was the first choice recommended, why were we denied this opportunity? They could have had Gandhinagar and Mumbai both. Why not both?

(1720/RBN/YSH)

My second point is this. The Report specifically says that unless the GDP is over ten per cent, this will not flourish. This is what the note says. So, what is your view and the Ministry's view on this? I am seeking this clarification for my knowledge. It says unless there is lower debt, that means if there is a high debt of the Government this will not be able to sustain. So, is this factual? I am asking this because this is what the sources say and the people say.

There are other few queries which I have in my mind while I read this Bill. This whole concept was to bring in good investments. Even in your opening remarks you said that there were good investments. But the job creation comparatively is not very good.

I am not able to understand one thing in this entire concept. There is on-shore and off-shore investments. What is the definition of on-shore and off-shore? What I understand from this whole concept is that physically the money is going to be out of our country and only legally the money will be here. So, what really is our country achieving? A lot has been said about Singapore and London. Those are different economies. Their sizes are different; their development indexes are different; their social denominators are different. We are a very different country. Look at the size of Singapore. What is applicable to Singapore is not applicable to India with its sheer number of people. One can compare oranges with oranges. You cannot compare oranges with peaches. So, can you clarify that to me? It almost makes us a tax haven. That is what my little limited knowledge of finance explains to me.

About KYC norms, I would like to say that we are very happy that this Government wants to bring in black money and it wants to bring in transparency. Now, KYC norms are applicable to everything. One gets to read in newspapers about Participatory Notes, Masala Bonds, etc. I understand there is no need for disclosure. If you could kindly throw some light on it, I would be grateful to you. If it is so, then this is money laundering and it will be only dirty money. We do not know where it is coming from, where it is going. It is applicable internationally and there is a huge tax benefit. Who are we giving this tax benefit to? Or is the money just round tripping? It is going from here and coming back from somewhere else. The loss is India's loss. It may not be dirty money coming through another way. But are we allowing it? These are just few doubts. If you could clear them and put them on the table, I think all this can be put to rest.

I just heard this was under the SEZ. If I am not correct, I stand corrected. This was under the Ministry of Commerce but now has come under the Ministry of Finance. Is that correct?

Somebody talked about the RBI. I have reservations about the comments made by Shri Pinaki Misra. He is right that a lot of wrongs have happened. But I still have faith in the RBI. I think that the RBI is a great authority of India and we have full faith in it. Things may have gone wrong. But this is our chance to correct them. This just does not mean we have to make one more law. Does that mean it is going to improve it? Only time will judge us. But is starting multiple authorities a solution?

We have been through the cases of hawala, forex index, etc. I think India is looking for a clean-up from the Government. But if you hurt every institution at one time, what is going to be the outcome? We all see what is happening to the economy of this country. We are going through absolutely a struggle. I compliment the honesty of the Finance Minister when she talked about the slow down. I really appreciate it. She has actually got the job in the most troubled times. I wish her only luck because her performance is not about only Opposition and people being in power. But my country gets affected by all these performances and decisions.

So, I urge her to give clarifications to all these issues. What do we need a good economy for? It is for the benefit of the people. We should get better jobs, better lifestyles and create wealth in this country and make sure poverty is alleviated. If that is our final goal, is this the way out? Given all the crises that we are going through, do we really need this Bill? Do we really need this if there is any suspicion that this is going to create a tax haven? We need taxes. You have not paid us the GST share. This entire morning was about the GST payments not given to the States. Even my own State is suffering because of that. So, I urge the hon. Minister to look into this and address them. Please clarify them. We do not need tax haven in this country. What we need is a transparent and a fair taxation system. You take pride in making people pay taxes. Everybody is happy to pay tax as long as its fair and just. Thank you.

(ends)

(1725/SM/RPS)

1725 hours

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I thank you for the opportunity to speak on the International Financial Services Centre Bill, 2019. I appreciate the Government's move to set up a uniform regulator for international financial service centres in India.

Financial services and products in an IFSC require dedicated focus and effective regulatory management to prosper and hence this Bill brings about the much-needed regulatory intervention in this sector. I hope with this legislation, we will see better inter-regulatory coordination which will help further develop IFSCs in India.

But I have a few doubts, concerns and recommendations in my mind with some aspects of this Bill. Clause 5 of the Bill deals with composition of the authority. The authority has representatives from RBI, SEBI, IRDA, PFRDA and the Ministry. Clause 5(1) (d) says that two members would be appointed on the recommendation of the Selection Committee. But the Bill does not specify who these people will be. Will they be from political background, policy experts, industry stakeholders? It is vague and it leaves scope for bring in anybody. So, I would like to request the hon. Finance Minister to clarify what the criteria will be for selection of these members.

Sir, my next point is relating to capital account convertibility. It has been more than 28 years since we opened our economy. But, so far, total capital account convertibility has not been achieved and it is because of this, our contribution to global financial market is very little.

Sir, there is no doubt that we are one of the largest countries in the world which uses international financial services, but our contribution is very less. In these circumstances, what are the plans of the hon. Finance Minister, at least from now onwards to keep India next to the world's leading financial hubs? I would like to ask the hon. Finance Minister whether plans of giving tax cuts and other incentives are in place to attract units to come to India.

I also recommend the Minister to take steps for popularising the cross-border transactions in the rupee terms, especially in respect of External Commercial Borrowings (ECB), trade credit and exports and imports, thereby reducing the exchange risk for persons who are residing in India.

Sir, it is good to see that the Government is focussing globally- competitive financial centres in India and hence I would like to recommend setting up an IFSC in Amravati, the capital of Andhra Pradesh. After Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, then the TDP Government led by Shi Nara Chandrababu Naidu envisaged Amravati as a world class capital for the State.

Sir, Amravati has potential to a city of the future, a financial and cultural centre not just for the country but also globally.

Amravati has reflected the dreams of the people of Andhra Pradesh. Sir, we have never seen such great participation of the public as in the case of Amravati. Farmers of Andhra Pradesh have voluntarily donated 33,000 acres of land for the construction of their new capital city. The TDP Government had inked several pacts with foreign and domestic stakeholders for the development of the world-class infrastructure in Amravati.

But, Sir, it deeply saddens me to see that the current State Government of the YSR Congress Party led by ... *(Not recorded)* is systematically destroying this great potential financial centre of the future just for petty political vendetta ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude now.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): The current Government of Andhra Pradesh has not only put a stop to all developmental projects in Amravati but also, they are committed to undoing all progress that has been made ...*(Interruptions)*

माननीय सभापति : प्लीज आप कन्क्लूड कीजिए।

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I am finishing, just one line. ...*(Interruptions)* Sir, the Chief Minister has ordered for demolition and destruction of infrastructure in Amravati. ...*(Interruptions)* What the current State Government wishes to achieve out of this is beyond logic and common sense ...*(Interruptions)*

Sir, ... *(Not recorded)* is playing with dreams and aspirations of the people of Andhra Pradesh by destroying Amravati which is the brain child of Shri Chandrababu Naidu and has the potential to be an International Financial Service Centre, but only if we can save it ...*(Interruptions)*

With this, I support the Bill and I sincerely hope that one day Amaravati can become an International Financial Service Centre as it is the pride of the people of Andhra Pradesh. Thank you, Sir.

(इति)

माननीय सभापति : उसे देख लेंगे, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON.CHAIRPERSON: If there is any derogatory thing, उसे देख लेंगे, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज आप बैठ जाइए। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। बैठिए।

...(व्यवधान)...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

(1730/IND/AK)

1730 hours

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri S. Venkatesan in Tamil,
please see the Supplement. (PP401A to 401B)}

1733 बजे

श्री अजय कुमार (खीरी): सभापति जी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, जिसके द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स स्थापित करने, उन्हें नियमित करने और निगमित करने के लिए यह बिल लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005, जिसका संशोधन 2015 में किया गया था और उसके द्वारा केंद्र सरकार को ऐसे विशेष आर्थिक जोन में ऐसे सर्विस सेंटर्स की स्थापना करने और उसके कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, उसी क्रम में राज्य सभा में पिछले वर्ष फरवरी, 2019 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जी ने इस बिल को पेश किया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अनुसार चूंकि यह बिल वित्तीय बिल था, इसलिए इसे लोक सभा में पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य अपने देश में विश्वस्तरीय सुविधाएं व्यापारियों को उपलब्ध कराना है और इसके द्वारा हम ऐसे सेंटर्स को डेवलप करना चाहते हैं, जिनमें वैश्विक व्यापार करने वाली जो कम्पनियां देश से बाहर चली गई हैं, वे वापस आएँ। इसके साथ-साथ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संस्थाएं, जो यहां व्यापार करना चाहती हैं और ऐसे विदेशी और संस्थागत निवेशक फेमा के तहत, जिन्हें भारतीय पात्रता है, वे लोग भी इन सेंटर्स में भाग ले सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार अमरीका और चीन की जैसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, पूरी दुनिया में एक मंदी का दौर है।

(1735/ASA/SPR)

उस दौर में भारत एक ऐसा देश है जो अपने व्यापक आधार के कारण उस मंदी से बचा हुआ है। जो अभी सर्वेक्षण और अध्ययन के माध्यम से निकलकर आया है, उसमें यह कहा गया है कि जो पूरी वैश्विक मंदी है, उसमें जीडीपी में न्यूनतम स्तर पर इस समय 3.2 वृद्धि दर हो गई है। चाइना की भी जीडीपी न्यूनतम स्तर पर है और ब्रिटेन में यह भी कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 तक वे भी मंदी की चपेट में आने वाले हैं। यूरोप की एक बड़ी अर्थ-व्यवस्था जर्मनी, जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत हो गई है। साथ ही साथ अमेरिका में भी यह संभावना बताई जा रही है कि वर्ष 2021-2022 तक अमेरिका भी मंदी की चपेट में आने वाला है। लेकिन ऐसे समय में भी हमारी सरकार की नीतियों के कारण ही आज हम यह कह सकते हैं कि न केवल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसे बुनियादी ढाँचों को विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है, बल्कि वहीं विदेशी मुद्रा की जो विनिमय दर थी, उसको जब से हमारी 2014 में सरकार बनी है, लगभग हम इसे स्थिर रखने में सफल हुए हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार भी इस समय उच्चतम स्तर पर है और व्यापार सुगमता की जो सूची है, ease of doing business, उसमें भी 53 पायदानों की एक बड़ी छलांग भारत ने लगाई है।

ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो ये परिस्थितियां हैं, जब पूरी दुनिया इस समय मंदी की चपेट में है, भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरकर आया है, जिसने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से रखा है, बल्कि अपनी नीतियों के आधार पर हम इस बात पर सफल रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी गति भी प्रभावित न हो और देश में जो इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की एक बड़ी चुनौती वर्ष 2014 में हमारे सामने थी, उसको भी हम सफलता पूर्वक ठीक ढंग से करने में सफल रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने यह बाजार विकसित करने के लिए सेवा केन्द्रों को विकसित करने की बात कही है और उसमें विश्व-स्तरीय सुविधाएं देने का हम लोगों ने प्रयास किया है, एक सेंटर अभी हमने अहमदाबाद में खोला भी है। अहमदाबाद में जो सेंटर वर्ष 2017 में खोला गया था, वह सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी हमारे विपक्ष के कई साथियों ने उसके विषय

में कहा है। इस समय जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स है, उसने अहमदाबाद के सर्विस सेंटर को तीसरा स्थान दिया है। केवल वर्ष 2017 में खुलने के बाद इतनी बड़ी सफलता पाना, निश्चित रूप से विदेशों में जो भारतीय नागरिक वहां व्यापार में हैं और ऐसे विदेशी संस्थान भी यहां पर आने के लिए आकर्षित होंगे। साथ ही साथ हम यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। विदेशी स्टॉक एक्सचेंज भी यहां पर आएंगे। उसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा में ही फाइनेंस करने की सुविधा हमारे इन सेंटर्स में होगी। विदेशी मुद्रा में ही हम व्यापार कर सकेंगे। ऐसी सारी सुविधाओं के कारण हमें वैश्विक वातावरण बनाने में सफलता मिल रही है। चूंकि यह एक बहुत बड़ा बाजार है और एक बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत की अर्थव्यवस्था पर भी है और भारत की नीतियों पर भी रहती है। ऐसे समय में हम लोगों को तात्कालिक निर्णय लेने की आवश्यकता थी और उसी के तहत हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान, एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारा नेपाल से होता है, उस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि मैं लखीमपुर जनपद से आता हूँ, जो नेपाल से सटा हुआ जिला है और यह एक बड़ी लम्बी सीमा है। इस तरफ भारत में रहने वाली ऐसी सभी मंडियां नेपाल के व्यापार पर ही आधारित हैं। वहां पर जो व्यापार होता है, उसके लिए आवश्यक कस्टम ऑफिस, और चूंकि ज्यादातर कृषि उत्पादन का ही व्यवसाय दोनों देशों में होता है, इसलिए ऐसे सब्जी और फल आदि के प्रमाणीकरण के लिए भी वहां पर एक कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यालय बनता है जिसकी आवश्यकता उसका प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि मेरे लखीमपुर क्षेत्र में भानपुरी खजूरिया में एक कस्टम केन्द्र खोलने के साथ-साथ, गौरीफटा में कृषि मंत्रालय के सहयोग से एक ऐसा प्रमाणीकृत केन्द्र देने की कृपा करें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में जिस तरह की परिस्थितियां मिली थीं, भ्रष्टाचार के कारण, बिजली की कमी के कारण, कोयला गैस की कमी के कारण, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी।

(1740/RAJ/UB)

जब से हमारी सरकार बनी है, तब से हम लोगों ने उसके लिए क्रमबद्ध प्रयास किए हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा कि चाहे वह ब्लैक मनी की बात हो, फाइनेंस बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, बैंकक्रप्सी कोड हो, डिजिटल लेन-देन बढ़ाना हो, टैक्स के अंतर्गत लोगों को लाना हो, एक तरह से हम लोगों ने सिस्टम को डेवलप करने का काम किया है। इसके अलावा हम ने बैंकों के बोर्डों को एनपीए कम करने का अधिकार दिया है।...(व्यवधान) इस तरह से हम लोगों ने प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, जिनके परिणाम दिखने लगे हैं।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह पिछले पांच वर्षों की मोदी सरकार की अनुकूल नीतियां ही हैं, जिनसे न केवल हम विश्व के आर्थिक मंदी के दौर में भी सुरक्षित रहे, बल्कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया है और उस रफ्तार को भी कम नहीं होने दिया है।

पुनः, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो क्रम माननीय अरुण जेटली जी ने उस समय शुरू किया था, उसे माननीय वित्त मंत्री आगे बढ़ा रही हैं।...(व्यवधान)

(इति)

1741 hours

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I congratulate the Government on this good initiative. It is very essential for India which is a fast-developing economy in the world. We must have such an institution of international standard but we are actually late. The idea of IFSC was brought in 2005 but it was not implemented, maybe, because of the global financial crisis. This Institution could be the next growth engine for the Indian economy. We hope for the best.

Sir, this top-most executive body consists of nine members which are nominated by the Government. It is all right but being an international level institution, merit should be the only criteria to become a member. Any kind of pick and choose policy should not be there.

With regards to the functions of the Authority and its the regulatory mechanism which have been categorically stated, it is governed by the RBI, SEBI and IRDAI. This is a new system. The IFSC will have all kinds of power that will avoid the delay and unnecessary paraphernalia.

Sir, India is emerging as a major economy, and creating a financial hub in India is very much needed and, in that respect, this move is commendable. Infrastructure should also be of international standard. IFSC must provide the avenues to the centralised financial infrastructure hub that can truly cater to the needs of a growing economy. At present, London, New York and Singapore are the global centres. They have a very good infrastructure. There is no doubt that India can go much ahead of them.

We are fortunate that India is blessed with a huge human capital. We are proud of it. The extensive use of English in India is another important point. Moreover, generations in India have the experience of entrepreneurship which is a plus point for India. Indians play a pivotal role in the top global financial firms.

Sir, the Percy Mistry Committee which is the main brain behind the idea of IFSC also gave recommendations about 'Democracy' and 'Rule of law'. If these two things are not there and if a political turmoil is there, then it will affect the functioning of the IFSC. With these words, I support the Bill.

(ends)

(1745/KMR/VB)

1745 hours

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. This idea is laudable to bring everything under one roof. मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड जो इंटरनेशनल एक्सपिरीएंस एवेलेबल है, उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले डबलिन, आयरलैंड में आईएफएससी बनाया गया था। आज वह दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हैवन है। वहाँ हर साल सौ बिलियन डॉलर टैक्स की चोरी होती है। मुझे उम्मीद है कि इस बिल को बनाते समय आपने उस इंटरनेशनल एक्सपिरीएंस को जरूर ध्यान में रखा होगा।

ग्लोबल एक्सपिरीएंसेज जितने हैं, जितने एसईजेडस हैं, मैन्यूफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हैं, उन्हें फोकस्ड रखें। अगर ज्यादातर से सर्विसेज पर रखते हैं, तो इसमें टैक्स चोरी बहुत होती है।

जो रेगुलेटर्स हैं- आरबीआई, सेबी इन सभी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इनको इससे बाहर निकाला जा रहा है। आपको यह देखना चाहिए कि क्या इनको बाहर निकालने की जरूरत है, क्या उन्हीं में कुछ पैदा किया जा सकता है?

अंत में, मुझे सिर्फ यह कहना है कि यह प्रायोरिटी जरूर कर लें कि गिफ्ट सिटी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा।

(इति)

1747 hours

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the International Financial Services Authority Bill, 2019. I would like to thank the hon. Finance Minister for bringing this Bill to the House.

By facilitating the establishment of International Financial Services Centres in Special Economic Zones in the country, this Bill will definitely be a booster-shot or a catalyst for our economic growth and development. It will not be wrong to say that the Bill will bring a financial revolution in the country towards achieving the hon. Prime Minister Modi's goal of a five trillion Indian economy. This Bill will invite even greater FDI into the country and will put India on the track to become a global financial hub.

It is a matter of pride that the first SEZ in India was established in my State of Maharashtra and that is the Santacruz Electronics Export Processing Zone in Mumbai. But I regret to inform that SEZs have not achieved their purpose. Instead, they are simply a means of land acquisition and real estate business. There are many regulatory obstacles that happen in establishing SEZs. पिछले सेशन में एसईजेड बिल में कुछ अमेंडमेंट्स आए।

To deal with foreign currency in India, banking, capital markets and insurance sector are governed by different regulators like RBI, SEBI and IRDAI. These sectors need inter-regulatory coordination and frequent clarifications and amendments. This leads to lot of uncertainty in the minds of investors and creates an uncertain business environment. The IFSC Authority Bill establishes a single authority with representatives of these bodies and that will govern the dealings of an IFSC in foreign currency.

Sir, I will give two suggestions. It is because of hon. Prime Minister Modi Ji and the former Finance Minister late Arun Jaitley Ji that the first IFSC was commissioned in Gujarat International Finance Tec-City. Actually, this is expected to generate about five lakh direct and indirect jobs. Similarly, an International Financial Centre has been set up in Navi Mumbai by our former Chief Minister Shri Devendra Fadnavis Ji with CIDCO as nodal agency. This Centre is based on the use of Fintech or Financial Technology. This refers to the use of technology to create and provide financial products and services to customers.

(1750/SNT/SPS)

It is my request to the Government to look into the possibility of creating an IFSC in the financial capital of India, Mumbai. The benefits from this will come to the State of Maharashtra and to our country too.

The intent of this Bill is correct. We have to ensure that even if transactions take place in foreign currency, the trade and business will be there. The production of goods and services must happen in India so that more jobs can be generated.

It is important to create regional centres through the setting up of IFSC in SEZs. Regional centres can be an economic ecosystem created around the IFSC. This will lead to development of the city where the SEZ is located, and also of rural areas surrounding the IFSC in the SEZ. Otherwise, the situation created will be of high Human Development Index in cities where the investment comes in, and low Human Development Index in other areas. This is not desirable. We should strive for equal human development.

My constituency Jalgaon is the leading producer of plastic, gold and cotton in the country. The investment invited through the IFSCs must be used to enhance the capabilities of such local businesses. Export and import units can be established in Jalgaon that will help businesses so that they can grow even bigger and our economy can become self-reliant.

The setting up of IFSCs also deal with flow of finance, financial products and services across borders. To make these products accessible to our common citizen, it is necessary to take up capacity building measures across the country. We need professionals who customize these products to our needs and demands. For example, farmers and Self-Help Groups are forced to take money from NBFCs at very high interest rates, as high as 36 per cent. The penetration of these financial products and services can happen only if we have skilled workers.

Lastly, once again, I would like to congratulate the hon. Minister for introducing this Bill. It is my earnest desire that hon. Members present in this august House bring their expertise and experience to make suggestions on the Bill. At the same time, we must send a message of unity to Indian citizens to show our intent in solving the economic crisis.

Thank you.

(ends)

1752 hours

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, Sir, for allowing me to take part in the discussion on the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019.

Sir, I would like to start by saying that this is not a Bill but a bell. 'For whom the bell tolls' is a famous novel by Ernest Hemingway. In this Parliament House, the question, for whom the bell tolls has a different meaning. This Bill seeks to establish a single authority to develop and regulate the various financial services, products and institutions set up in the International Financial Services Centres set up in Special Economic Zones across the country.

Sir, this is the report of the Comptroller and Auditor General of India. In this report, C&AG clearly stated, in India, land allotted to SEZs are misused. The performance of SEZs reveals that out of 392 notified SEZs, only 152 undertake any business. The domestic companies conspire with the foreign citizens and companies, and misuse the land for real estate business. It was noticed that in the selected 117 Developers/Units in 12 States, the actual employment, that is, 2,84,785, vis-à-vis the projections, that is, 39,17,677 made by the Developers/Units had fallen short by 92.73 per cent. Companies even raised loans on SEZ land.

Sir, I believe, this Bill, quietly, and literally so, cuts the throat of RBI. According to clause 3, in chapter 1, sub-section (d), all financial services are converted into mere financial products, the securities, the contract of insurance, the deposits, the credit arrangements, the foreign currency would all turn out to mere financial products. Practically, going by the definition contained in the Bill, the RBI will have no power. It would no longer remain as the financial watchdog of the country.

(1755/GM/MM)

Our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh resisted the swells of economic crisis from reaching Indian shores only by sustaining and nourishing the system of checks and balances. This has been prevailing since the days of Pandit Jawaharlal Nehru. Even when the mighty American economy nose-dived, the Indian economy stood and flourished during the time of Dr. Manmohan Singh because of the system of checks and balances. It is unfortunate that the present Government is trying to destroy the system of checks and balances, which

means if there is an unstable situation or a fluctuation in the world market, India will go down with it.

1756 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : इसमें सभी की सहमति है। मैडम, आप पांच मिनट में जवाब दे देना। इसमें सभी की सहमति है। क्या कोई ऑब्जेक्शन है इस बिल पर? नहीं है, ठीक है।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, please give me one minute. Please note that the sub-section 2 of the 2005 Act has been misquoted. ...(*Interruptions*) In the Bill, it is said that “.....the Central Government may, subject to such guidelines as may be framed by the RBI, the SEBI, the Insurance Regulatory Development Authority and such other concerned authorities as deemed fit.....” The Bill negates the RBI Act and the SEBI Act and the Bill is a war-cry against the economic independence of our country.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी सदन में कांग्रेस के नेता है, इसलिए एक क्लैरिफिकेशन तो पूछेंगे।

1757 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I will not make a speech. I have only two or three clarifications. First of all, 6000 Indian entrepreneurs have migrated from our country in the last two years. Under the liberalized remittance scheme, USD 45 billion have also migrated. On one hand, the hon. Minister is talking about establishing a global financial hub in India. But on the other hand, she is failing to entice or allure those promising entrepreneurs. May I know from the hon. Minister what the fate of the GIFT City is? The IL&FS was a stakeholder with 50 per cent stake in the GIFT City. It is reported that IL&FS has collapsed and its stake has been bought by the Government. Is it true? What is the present status of the GIFT City?

Secondly, the Government has abolished the multi-regulatory regime. But on the other hand, the Government is invoking a unified authority which simply implies the centralization of the authority. These are the two issues that need to be clarified.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती महुआ मोइत्रा जी, आपको केवल एक क्लैरिफिकेशन पूछना है... (व्यवधान) आपको आपकी पार्टी को दिए गए समय के अतिरिक्त समय बोलने के लिए दिया जा रहा है। ... (व्यवधान) आज सभी महिला सांसदों को राष्ट्रपति जी के यहां जाना है।

1758 hours

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, I will keep my speech short. As everyone said, the intent of this Bill is absolutely noble, but it is quite ironic that in a country as large as ours, 70 years after Independence you are bringing in a Bill that is converging powers into a single regulator and it is only brought in for the purpose of a single International Financial Services Centre that was announced four and a half years ago. So, if you look at the development status of this particular GIFT City that has come up in Gandhinagar, only 3 million square feet of the planned development of 62 million square feet has been built. The original plan was that the IL&FS, which is now a bankrupt defunct entity, was in a 50:50 joint venture with the Gujarat Urban Development Company Limited. The IL&FS has since collapsed. What is the new way that you are going to take this forward?

The other thing is that if you are talking about the essence and spirit of the international financial services regulation which we need to embody in India, I think we should have this available to other cities as well. The application for BKC, Mumbai as an international financial services centre has been pending for years. All of us would be single-minded in our approach that Mumbai perhaps deserves it more than any other city in India.

(1800/RSG/SJN)

So, why is it being done for Gandhinagar? When you are talking about connectivity and when you are talking about quality of life, it is almost like Delhi being shifted to Thuglaqabad and you are doing everything to do it. So, while on principle, we do not mind the idea of an IFSC, it is ironic that you are bringing it up only for this.

(ends)

RE: EXTENSION OF TIME

1800 hours

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप सभी की अनुमति है, तो सदन का समय इस विधेयक की समाप्ति और शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

**THE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES
AUTHORITY BILL – CONTD.**

1801 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker Sir. I will confine my speech to two issues.

First, I am not going into the other details but you may kindly see that the Bill consists of 34 Clauses and two Schedules; and 14 enactments made by the Parliament are being amended through a piece of legislation moved by the hon. Finance Minister. So, the two issues which I would like to highlight are regarding the multiplicity of authorities. We are having an Insurance Regulatory Development Authority, the Reserve Bank of India, SEBI, as well as the PFRDAI. There are so many authorities that we have under various Acts. Now, the hon. Minister, by means of this Bill, is creating a new authority, that is, International Financial Services Centres Authority. So, another authority is also coming. We want to avoid the number of authorities; we want to avoid the number of agencies. We want to have a single-window system for ease of doing business. But unfortunately, at the same time, we are creating more and more authorities. I would like to seek a clarification on that issue.

Secondly, coming to the technical point, this is very important and I am seeking protection from the hon. Speaker as a Member of Parliament. Kindly read Clause 31 (i), which says: "The Central Government may, by notification, direct that any of the provisions of any other Central Act ..." It says: "The Central Government may, by notification, amend any of the provisions of any other Central Act or any rules or regulations made thereunder or any notification or order issued or directions given under specified notification (a) shall not apply to financial products, financial services, or financial institutions as the case may be in the international financial services centres." Who gives the authority? How

can Parliament give a stamp to the Government that any other Central legislation can be made not applicable to the international financial services centres? This means, all other legislation which we have passed are indirectly being amended by means of a legislation. It is not good for a healthy democracy because it is the domain of the Parliament. The Parliament's supremacy is being taken away by Clause 31. Clause 31 has to be reviewed because Parliament does not give or cannot give any authority to change any other law made by Parliament that those laws are not applicable according to the whim and fancy of the Government. If you can make notifications from time to time to say that this Act is not applicable to the international financial services centres, why have you brought 14 Acts within the purview of this Bill? You have already brought 14 Acts within the purview of this Bill but you are also saying that 'any other Act, any other Central legislation' is not applicable as far as international financial services centres are concerned. You could have very well said in one sentence and concluded that no law is applicable to the international financial services centres. You have specified 14 Acts and you are giving a blank cheque to the Executive, to the Government, that you can change the rules and Acts made by Parliament. That is not good for a healthy democracy. I strongly object to the provisions in Clause 31. Kindly review Clause 31.

Thank you very much.

(ends)

1804 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Dhanyavad, Speaker Sir.

I thank all the Members who have participated in this discussion. Even at the beginning, I went into a bit of details about what this Bill proposed to bring. It is certainly trying to get one authority which would be a single sort of window to take care of the financial centre which is being established in Gandhinagar.

(1805/GG/RK)

Sorry, Sir, I am taking a little time to gather my papers.

Sir, about 21 hon. Members have spoken on this Bill. They all have gone into great details and I will try, as much as possible, answering each one with specific references. A lot of what has been raised by several Members, will be covered in the general answer. Answer given for one Member may equally apply for the other Members. Sir, I seek your indulgence, if I do not name each one of the Members while giving answers.

I will just go back for a minute to say that the establishment of an exclusive Financial Centre, the way you establish an IT Park or a particular manufacturing park and so on, was proposed – with a bit of emphasis I would like to say – and the clearance for such an SEZ exclusively for financial purpose was given not in 2015, as many of the Members have quoted. In 2015, a notification and also a proposal, speaking about how regulators will issue notification for the functioning of those institutions in GIFT cities, came through in the Parliament. But, the application for setting up an SEZ exclusively for financial services, was made by the State of Gujarat in 2011 and its permission was given by the then Commerce Ministry under the UPA Government. At that time, pardon me, if I sound a bit sarcastic, it was not questioned as to why the Government is going to a State there is prohibition. जिस राज्य में प्रोहिबिशन है, वहां फाइनेंशियल हब को ले जाने में लोग कहाँ आएंगे? तब क्यों आपके दिमाग में यह नहीं आया? सन् 2011 में एसईजेड गांधी नगर में सैट-अप करने के लिए जब गुजरात सरकार दिल्ली पहुंची, तो तब की कॉमर्स मिनिस्ट्री से परमिशन दी गयी थी। तब आपने प्रोहिबिशन के बारे में नहीं सोचा? उससे पहले मैं यह भी बोलना चाह रही हूँ, सरकारिस्टिकली समझो, सॉरी if it sounds sarcastically गुजरात में कांग्रेस की सरकार तब से थी? कितने साल थी? अरे इंडस्ट्री नहीं आएगी, इनवेस्टमेंट नहीं आएगा, प्रोहिबिशन को हटा दो माहत्मा गांधी के राज्य से। आपको सोचने के लिए अधिकार था। आपको यह सब सोच अब आ रही है। International Financial Centres like Singapore or London, do not have free

availability of liquor. Let us be a little more serious when we are putting an argument. I would say that the permission for setting up this SEZ was not given after the NDA came to power under the leadership of Modi ji. It was given permission in 2011. The Commerce ministry had given this permission then. Let us take that in our stride. So, the notification for the GIFT city as a Financial Services Centre was given in 2011. Post which, of course, a lot of discussion took place.

Even as I am saying this, I would like to underline the fact that nothing stops anybody else from applying for it. Every State, like they would have applied for setting up an SEZ, can seek the Commerce Ministry's approval for setting up an SEZ. They can say that the land is acquired, infrastructure is ready and the Centre will give permission for establishment of one more SEZ. If the States want to apply, they can. I will go one-by-one on these points.

It is not as if now, somebody from the Centre, under the NDA led by the Prime Minister Shri Modi, is giving it to Gujarat. Please appreciate the fact that he was the first mover, as the Chief Minister of Gujarat, to think futuristically and he said that India needed a financial hub which would match up with London, Singapore or any other financial centre.

(1810/RC/KN)

He created that SEZ; applied to the Centre; got it cleared; invested in it and also made sure that it meets global standards. So, I would appeal to Members to understand that it is not a gift being given now. As an hon. Chief Minister of Gujarat then and now Prime Minister, he gifted it to his State for the people of Gujarat. Therefore, it is now standing there.

Today, whatever is being done is because we need to have a sense of pride also to make sure that we create international class institutions. Nothing stops any other State from applying. Nothing stops any other State from investing. Nothing stops any other State from giving incentive to build an international hub. So, let us remove that misconception.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Has any other State applied?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Prof., I will have to check that.

So, that is the way in which we would like to lay this fact about the GIFT city. Let me reiterate for clarity sake that the Special Economic Zone – the Gandhinagar International Financial Centre – was permitted by the Ministry of

Commerce and Industry on 18th August, 2011 for setting up IFSC at Gandhinagar, Gujarat.

Then, what happened in 2015? All of us think that it was in 2015 when it was set up after Shri Modi became Prime Minister. Actually, in 2015, in the Budget Speech, the then Finance Minister had very clearly said that the first phase of GIFT as an International Finance Centre would soon become a reality. So, once the conception, permission and everything were obtained in 2011, the first phase commencement was what got announced in 2015 in the Budget leading many of us to think that it was then set up. No, it was the first phase which was part of the Finance Minister's announcement.

I just want to trace very quickly the entire background. Then, of course, in 2016 competitive tax regimes were announced by FSC. The exemptions were provided in 2017 and 2017 also saw a tie up with Singapore and International Arbitration Centre for dispute resolution mechanism to be set up. Then, in 2017, the starting of an international exchange happened. Several banking units came in there and insurance entities also reached there. Then in 2018, announcement for setting up a unified regulator for IFSC was announced. Now, we are seeing the Bill for it. Additional tax reforms were also announced in 2018. Then 2019 also saw quite a few announcements like announcement to set up aircraft leasing and financing activities in IFSC. Then 2019 also saw, 13 banks, 19 insurance firms and around 50 capital market entities licensed in IFSC. So, IFSC Authority Bill comes now. This is how I would like to trace the entire activity of the IFSC. So, it is not that suddenly we have chosen to give it to one particular State.

I think I have sort of answered this question about why Gandhinagar but I would now like to quote a reply given by the then Finance Minister in this House in response to a question which is very similar to the question Supriya Ji has asked, that is, why not Mumbai and why not Bandra-Kurla Complex (BKC). Professor has also asked this and many others have also asked this. I was surprised that Prof. Sougata Ray was asking for Mumbai, Bandra-Kurla Complex and not about Kolkata. Are you all right with that? ...(*Interruptions*). That is all right but you were very keen to quote that rather than Kolkata.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I will move an amendment on this.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Which, of course, will now get negatived.

(1815/SNB/CS)

...(Interruptions) Thank you, I do not need judgemental comments. If sarcasm has been thrown at me, so shall I with the permission of the Chair
 ...(Interruptions) Each time I do qualify for that – sarcasm for sarcasm.

I would now like to quote the then Finance Minister. I am doing an English translation of what he said, not reading the Hindi although the Hindi version is with me here. I quote:

“Hon. Speaker, Madam, there is no direct relation to the Question”
 Which meant ‘why not elsewhere’ “but I can say to the hon. MP,”

I am quoting the late Arun Jaitley who said it in this House.

“that there is a limit to how many such International Financial Centres can be set up.”

There is not, of course, one – this is not part of the quote:

“This is because the first GIFT city is already under development in Gandhinagar, Gujarat. Firstly, we have to utilise fully that one and then we can think of another. The Government of Maharashtra is requesting again and again that such IFSC should be made in BKC, Mumbai. But if we make more, then we can’t utilise the existing one fully. Therefore, we should first optimally utilise the GIFT city and then we can think further on this issue.”

This was the reply in response to a question asked to Shri Arun Jaitley on 22nd December, 2017. That partly probably answers the questions that there is no limitation, in the sense, States can apply and if they want to set up more, they can.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): पहले गाँधीनगर को यूटिलाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): गाँधीनगर को यूटिलाइज करने में 20 साल लगेंगे। हम हैदराबाद के बारे में पूछ रहे हैं...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Why did you then not give the permission? You were the then Commerce Minister. In 2017, why did you not give the permission?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Has the quote I read out not given the answer to your question? I will read it again, if you wish.

“Hon. Speaker, Madam, there is no direct relation to the Question but I can say to the hon. Member that there is a limit to how many such International Financial Centres can be set up. This is because the first GIFT city is already under development in Gandhinagar, Gujarat. Firstly, we have to utilise fully that one, then we can think of another. The Government of Maharashtra is requesting again and again that such IFSC should be made in the BKC, Mumbai. But if we make more, then we can't utilise the existing one fully. Therefore, we should first optimally utilise GIFT city and then we can think further on this issue.”

This was his reply. ...(*Interruptions*) But I have explained the process.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, if there is investment in an area in my district *vis-à-vis* another district which is developed, then should that district not be considered? Mumbai has opportunities. Would you consider setting up one IFSC in Mumbai? ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Like as I said, if the States invest and like any other SEZ if they apply for it and they want us to consider, ...(*Interruptions*) I am trying to further answer your question specifically that the provisions allow for setting up more IFSCs ...(*Interruptions*) Prof. Ray, you have been keen to get this answer, the provisions allow for setting up more IFSCs. The rationale why the second was not immediately considered was explained by my predecessor and I have quoted that. That is the factual position. So, there is nothing which says that there cannot be a second one. But the answer given at that time in 2017 was to say we need to optimally utilise it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Now, since you are the Finance Minister, will you consider it now?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I do not represent the Commerce Ministry.

(1820/RU/RV)

I now move to the broader point of what exactly is the infrastructure. The total area of the GIFT City is 886 acres and the GIFT City is divided into two zones. One is domestic zone which is spread over 625 acres and the other is the SEZ IFSC zone which is spread over 261 acres. The second half of IFSC is a multi service SEZ with International Financial Services Approval Centre and IFSC houses several Services SEZ units. It also houses the Financial Service Units under the IFSC umbrella regulated by RBI, SEBI, IREDA, PFRDA and so on.

What we want to do now is to get one Authority which can oversee all these operations. That does not mean that the regulators and their independence and the power that they enjoy is getting undermined. In as much as having to take care or supervise and regulate activities in the IFSC, they become single window. But that does not undermine the power of the RBI or SEBI or other authorities which are any way functioning as the way they have functioned all the while. It is only for this purpose that they all become one instead of people having to run to several authorities to ask for clearances.

As I explained before, States have to seek permission to set up an International IFSC and they have to approach the Department of Commerce. All this remains; nothing has changed but however, there were quite a few Members who asked whether the CAG will check up what happens. The IFSC, for clarity sake, is a company with less than 51 per cent of Government equity about which all of you have raised in connection with the ILFS. I will explain that too.

The Authority will be subject to CAG, will be subject to CVC, and oversights of all of them will apply on the Authority.

The Ministry of Finance is responsible for regulating financial transactions of the IFSC and the Authority will be, of course, an independent one. It is not as if the Central Government is taking all the authority and controlling them. They shall be an independent body.

Referring to the Percy Mistry Report, Shrimati Supriya Sule spoke about the GDP growth which has to be more than 10 per cent and also the Government debt will have to be reduced. Yes, the Committee recommended about eight to ten per cent growth. If it can be sustained, it will be better for this institution. India is definitely growing and I do not think there is a blip in a quarter, I am not

undermining the challenges. I do not want it to be interpreted like that immediately. But that need not be a dampener for setting up an institution of this kind which takes a long gestation to come to fruition.

It also did recommend lowering public debt and I take this opportunity to say that public debt to GDP of the Central Government today is showing a reducing trend from 52.2 per cent in 2013-14 to 49.4 per cent in 2018-19. So, debt is coming down. And have we done a cost benefit analysis? Obviously, for a big venture like this, it is done. I started my initial remarks by saying that the Committee had even then, in 2008, recognised that the loss to the country by 2015 of those Financial Services fees going out of the country would be much more than 50 billion.

(1825/KSP/MY)

If we want to get that back, how do we get that back? It is because most of them pertain to Indian companies. They are going out to seek those services. So, we have to save that money from going out of this country and we can do that only if we have something which is going to meet the requirements of people who are seeking such services and, therefore, it is important.

We are amending 14 Acts. Shri N.K. Premachandran spoke about that. We are amending them and that is required because all the regulators like RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, all of them do refer to various Acts when they have to perform their duties as regulators. The Reserve Bank of India, while dealing with institutions of this nature, invokes at least seven different Acts and, that is why, in this Bill, we have shown those different Acts which will also have collateral implication of this Bill. As a result of this, they will have to be amended. So, 7 Acts which relate to RBI, 3 Acts which relate to SEBI, 3 Acts which relate to IRDA and one Act which relates to PFRDA are all now being, at least in some aspects, amended.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): As far as these 14 enactments are concerned, there is no objection because they are specifically mentioned in the Bill. But Clause 31 of this Bill gives a blanket cheque to the Government to amend any other Central legislation. By this, the legislative supremacy of the Parliament is taken away. That is my objection.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: As far as the specific question that you asked me about Clause 31 is concerned, there are several precedents, Premachandranji. It is like Clause 49 of the SEZ Act of 2005. These are powers which are made or powers which are being referred only because you want to make ease of functioning is not violating anything to do with the sovereign authority of the Parliament. So, this is not a *carte blanche* which the House is giving us when you are passing this Bill. Earlier in the SEZ Act, the Government has done this and we are not doing anything violative of the established practices.

The hon. Member Shri Venkatesan has mentioned in Tamil that there are 14 Acts being taken up and said that ED, CBI, C&AG etc. would not be able to question. No, that is not true. All laws of the land will apply to this area. There is no law which is being kept away. ED, PMLA and CBI would all be able to function as they are now. The C&AG would audit the Authority and the 14 Acts are amended only because the Authority needs to be empowered. Otherwise, you are going to have people having to go to eight or nine different institutions to establish their units in these areas. Therefore, it was more from the point of facilitating, rather than taking away the powers.

The hon. Member Shri Kaushalendra Kumar asked a question about the Prevention of Money Laundering Act. This Act forms the basis of all KYC and client due diligence measures in India are applicable to the GIFT City. So, every money laundering related measure which the Government takes will be fully applicable even in the IFSC.

I think, broadly I have addressed all the issues except the question of ILFS and also the question as to whether this is going to become a tax haven. Not at all, because tax holiday is given for IFSC only for 10 years and that is in line with the policy adopted under the SEZ Policy of the Government of India. So, if you did not have this fear about SEZ anywhere else for any other functioning, you need not have it for this one also.

(1830/SRG/CP)

So, all laws are applicable and a tax holiday is only with a Sunset clause. I think this suspicion that might end up being a tax haven, need not be in our minds.

As regards IL&FS, first of all, there is a very clear attempt to resolve the crisis of IL&FS with the Government-appointed Board about which I think, at some other time we can get into the details. But it is a fact that it is nearing some kind of a resolution. I am not speaking for Government of Gujarat, but I have seen reports where the Government of Gujarat has very clearly said that they are making efforts to ensure that, that component in this body where Government of Gujarat owns shares and IL&FS also got a hold. Probably somewhere Government of Gujarat would want to take over IL&FS's part in context of the difficulties being faced by IL&FS. So, it is not as if it is doomed, it is not as if is collapsing. Everybody there is quite seized of it. We are also monitoring the situation.

About the worry that the CEO of Gift City has quit, I am sorry, the CEO was the nominee of the IL&FS. Therefore, after the crisis of IL&FS came out, he had to quit. Former Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shri Tapan Ray is now the CEO. So, let us not have this fear that, 'Oh, somebody has quit, he has left and gone, so the whole place is vacant.' No, No. Morally, the right thing was done. He had to quit as he was a nominee of the IL&FS. So, now whoever is appointed has been appointed by the Gujarat Government. So, I think, broadly most of the issues have been addressed by me.

About the PRC, the Performance Regulatory Committee, a lot of Members have spoken saying it is all internal, we are looking at whatever is happening. This follows best global practices. A two-member Committee looking into what is happening inside is one of the ways in which performance is monitored; and that is following the best practices which prevail globally. There is nothing otherwise.

Sir, thank you very much for having allowed me to give the explanation.

(ends)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मेरे दो प्रश्न हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका ज्ञान सभी मानते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। यह बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन है, लेकिन जो कंसर्न है कि अभी जो एक्सटर्नल कामर्शियल बॉरोइंग या रीडिंशयोरेंस या एफडीआई जो भी आता है, उसके रेग्युलेटर उसको रेग्युलेट करते हैं। यदि यह सारा अधिकार हम उसमें देंगे, तो रेग्युलेटर और उनके बीच में जो लड़ाई होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? यह मंत्री जी को बताना चाहिए।

दूसरा सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। इन्होंने टैक्स हॉलीडे एसईजेड में 10 साल के लिए दिया है। मान लीजिए कि गिफ्ट सिटी में इन्होंने एसईजेड बनाया। देश में उदाहरण है कि एसईजेड डीटीए में कनवर्ट हो जाता है। 10 साल के बाद वह डीटीए बन जाएगा। उसी की सारी संस्थाएं, मान लीजिए बीकेसी में कोई लाइसेंस आपने दिया, तो बीकेसी चला जाएगा, कोलकाता चला जाएगा। सेम कंपनी 10 साल यहां टैक्स हॉलीडे लेगी, 10 साल मुंबई में लेगी, 10 साल कोलकाता में लेगी। इसको रोकने के लिए सरकार ने इस बिल में क्या उपाय किया है? ये दो चीजें मंत्री जी बताएंगी, तो बहुत कृपा होगी।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं मेंबर का सेकेंड पाइंट सुझाव के नाते ले लेती हूं। On the first point, every overseas borrowing is regulated by the authorities and if there are activities happening here, they will obviously be going through the regulator who is all present there. Therefore, GIFT city's treatment for overseas borrowings being a bonded area of Special Economic Zone will also be regulated. It does not mean that regulators do not function there. We have unified all of them, so that there is a single window. But regulators will work even there.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1835/KKD/NK)

खंड 3

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment No. 1.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 16 मूव करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment No. 16. It is about definition of financial product.

I beg to move:

Page 2, *after* line 15,--

insert “(iv a) contracts of Indemnity bonds;”. (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“ कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment Nos. 2 and 3.

I beg to move:

Page 3, for lines 28 and 29,--

substitute “(3) The head office of the Authority shall be located at
at Kolkata and Regional Offices shall be located at four
other places in the country.”. (2)

Page 3, line 31,--

omit “or outside India”. (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 43 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment No. 43.

I beg to move:

Page 3, line 23,--

after “Authority”

insert “of India”. (43)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“ कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment Nos. 4 and 5.

I beg to move:

Page 3, *after* line 34,--

insert “(aa) Two Members from Lok Sabha and one Member from Rajya Sabha , to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha respectively, ex-officio;”

(4)

Page 4, lines 4 and 5,--

for “whole-time or part-time Members as the Central Government deem fit” (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 मूव करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment Nos 17 and 18 because I feel that the Selection Committee to the Authority should be independent.

I beg to move:

Page 3, *for* lines 34,--

substitute “(a) a Chairperson , who shall be a retired judge of High Court;”. (17)

Page 4, *for* lines 10 and 12,--

substitute “(a) Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court authorised by the Chief Justice of India;

(b) Minister of Finance; and

© Leader of the largest party in opposition.”. (18)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 37 और 38 मूव करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I am not moving my amendment Nos 37 and 38.

माननीय अध्यक्ष: श्री श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 44 से 46 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendment Nos. 44 and 45, but I am moving my amendment No. 46.

I beg to move:

Page 4, for lines 6 to 9,--

substitute “(3) The Members shall be persons of proven ability, integrity and standing who have displayed capacity in effectively addressing matters in connection with financial sectors of hold domain level knowledge or experience of law, finance, economics, accountancy and bookkeeping, managerial administration which in the opinion of the Central Government, shall be of operational utility to the Authority till such time as the Central Government deems appropriate as specified by the regulations.”. (46)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“ कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 6 से 8 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment Nos. 6,7 and 8.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 19 मूव करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my amendment No. 19.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 47 मूव करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendment No. 47.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“ कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1840/SK/RP)

खंड 7

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन- उपस्थित नहीं।

श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving my amendments 49 and 50.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendments 13 and 14.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 39 और 40 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 5, *omit* lines 44 and 45. (39)

Page 6, *omit* lines 1 to 5. (40)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 और 40 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 13, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will move only very serious amendments. This is: "The authority shall maintain proper accounts and audit." The provision is "in consultation with" C&AG and my amendment is "as per the directions of" C&AG.

I beg to move:

Page 7, line 3,-

for "in consultation with"

substitute "as per the directions of". (21)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 और 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1845/MK/RCP)

खंड 22

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में केंद्र सरकार के पास पावर का जो केंद्रीयकरण हुआ है, उसको देखते हुए, इसे हटाने के लिए मेरा यह मत है कि मैं इस संशोधन को मूव कर रहा हूं।

I beg to move:

Page 8, for line 27, –

substitute “22. (1) If at any time, the Comptroller and Auditor

General, after consultation with the Central Government,

is of the opinion that.” (41)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, it is an important amendment. The Reserve Bank of India is the custodian of all the matters related to finance. I beg to move:

Page 8, line 37, –

omit “, not exceeding six months,” (50)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 27 से 30

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving the amendment because it has become infructuous.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 31

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is the contentious amendment which I have already moved. The hon. Minister has replied. But my suggestion is that let it be with the prior approval of the Parliament. We cannot give a blanket cheque to the Government to amend all the existing Central legislations. I beg to move:

Page 10, line 32, –

after “may,”

insert “, with prior approval of the Parliament,”. (25)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 31 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि खंड 31 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving my further amendments.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि खंड 32 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**